चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

नरेगा के सामने नई चुनौतियां

पेज 3

मुसलमान सबसे पीछे क्यों ?

पेज 5

केलो नदी को बचाने की ज़रूरत

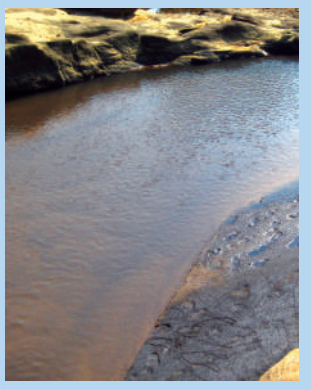

पेज 7

गुरु ही सफलता का द्वार

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 25 जनवरी–31 जनवरी 2010

सीआईए और मोसाद का स्माइल इंडिया 2015

सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमारी इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई है भी या नहीं. देश के ख़िलाफ़ साज़िश दो ताक़तवर देशों की ख़ुफ़िया एजेंसियां कर रही हैं, हम जितनी छानबीन कर रहे हैं उतनी ही ख़ौफनाक तस्वीर उभर रही है. सरकार अगर जवाब नहीं देती तो मानना चाहिए कि सरकार सो रही है और देश के राजनैतिक दल लुंजपुंज हो गए हैं. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री कहें कि हमारी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, और तब हम अपने को पुन: परख पाएंगे. लेकिन अगर ख़ामोशी रहती है तो मान लेना चाहिए कि देश के साख वाले लोगों के साथ हादसों की शुरूआत होने वाली है, चाहे वे हादसे चरित्र हनन के रूप में हों या शारीरिक हमलों के रूप में. दलालों की मंडी में मीडिया के चंद साख वालों से इतना ही कहना है कि आज के बाद कल उनका ही नंबर आने वाला है. आंख खोलने का आज ही वक़्त है.

रूबी अरुण

यह अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए का मिशन हिंदुस्तान 2015 है, जो भारत को टुकड़े-टुकड़े कर इसके वज़ूद को ख़त्म करने की ख़ौफ़नाक साज़िश है. इस मिशन पर अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए ने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. सीआईए की मंशा है कि वह भारत को 2015 तक इतना खंडित कर दे कि देश के अंदरूनी हालात 1947 की भयावह स्थितियों में तब्दील हो जाएं. अराजकता और अफ़रातफ़री इस क़दर फैले कि सरकार का समाज पर से नियंत्रण ख़त्म हो जाए. और, तब भारत के बिगड़े हालात सुधारने के बहाने इसकी सत्ता पर सीआईए अपनी दबिश बनाए और आख़िरकार भारत अमेरिका का गुलाम बन जाए.

इस ख़ौफ़नाक मिशन में सीआईए का साथ दे रही है कुख्यात इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद. इन दोनों के एजेंट पूरे देश में हर स्तर पर अपना जाल बिछा चुके हैं. वे अपने ख़तरनाक मंसूबे पर बख़ूबी अमल भी कर रहे हैं. यही वज़ह है कि सीआईए ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमारे ही देश की कुछ नामी-गिरामी चुनिंदा हस्तियों को बेहिसाब क़ीमत पर ख़रीद लिया है. जिसमें शामिल हैं हरेक तबके के लोग. पत्रकार, उद्योगपति, आला अधिकारी, समाजसेवी और मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्तियां.

भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों के पास इस बाबत पूरी ख़बर है. रॉ और आईबी के पास वह नक़्शा भी मौज़ूद है, जो सीआईए ने अपने मिशन के लिए तैयार किया है. इस नक़्शे में भारत को उतने ही टुकड़ों में बांटा गया है, जितने कि यहां राज्य हैं. यानी कुल 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग देश के रूप में दर्शाया गया है. यह ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जिस तर्ज़ पर सोवियत संघ के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे. इस नक़्शे के साथ जो दस्तावेज़ मिले हैं, उनमें साफ़ तौर पर इस बात का ज़िक्र है कि भारत को धर्म, जाति और चरित्र के आधार पर तोड़ा जाए. अलग-अलग धर्म-संप्रदाय के प्रतिष्ठित और समाज को नेतृत्व देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ गंदी और हौलनाक़ साज़िश रच ऐसी दुश्वारियां पैदा कर दी जाएं कि वे सामाजिक तौर पर बर्बाद हो जाएं. ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़े. सांप्रदायिकता फैले. दंगे भड़कें और सीआईए अपने मक़सद में कामयाब हो जाए. भारत के अलावा दुनिया के अन्य साठ विकसित देश भी सीआईए के निशाने पर हैं. हालांकि दिखावे के तौर पर अमेरिका यह कहता है कि उसकी यह ज़ंग आतंक के ख़िलाफ़ है. अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित नासा के दफ्तर में मौज़ूद इंटरनेट की दुनिया का बादशाह गूगल सीआईए के निशाने वाले देशों की एक-एक हरक़त की पूरी ख़बर अपने ई जासूसों के ज़रिए सीआईए तक पहुंचाता है. पर पहला टारगेट हमारा देश भारत ही है.

दरअसल मालेगांव ब्लास्ट भी सीआईए और मोसाद की इसी योजना की एक कड़ी थी. 12 अप्रैल 2008 को सीआईए और मोसाद ने इस सिलसिले में भोपाल के श्रीराम मंदिर में एक मीटिंग भी की थी, जिसमें रॉ और आईबी के कई पूर्व और वर्तमान अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था. सीआईए और मोसाद की इस नापाक साज़िश की ख़बर हमारे उच्च ख़ुफ़िया अधिकारियों को है, पर उन्होंने कितनी जानकारी प्रधानमंत्री को दी, कहा नहीं जा सकता. क्योंकि इन साज़िशों पर रोक लगाने के लिए अभी तक सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया है. कुछ पत्रकारों पर शक़ है कि वे सीआईए और मोसाद के लिए सूचनाएं इकठ्ठा कर रहे हैं. पत्रकार अगर अपने पेशे से गद्दारी करे तो वह अच्छा इन्फार्मर बन जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच आसानी से सूचना और निर्णय करने वाले केंद्रों तक होती है. साउथ और नार्थ ब्लाक के दरवाज़े आसानी से पत्रकारों के लिए खुल जाते हैं.

रॉ और आईबी के पास वह नक़्शा भी मौज़ूद है, जो सीआईए ने अपने मिशन के लिए तैयार किया है. यह ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जिस तर्ज़ पर सोवियत संघ के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे. इस नक़्शे के साथ जो दस्तावेज़ मिले हैं, उनमें साफ़ तौर पर इस बात का ज़िक्र है कि भारत को धर्म, जाति और चरित्र के आधार पर तोड़ा जाए.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के पास ख़बर है कि सीआईए के लिए मुख़बिरी करने वाले एक पत्रकार मैथ्यू रोज़ेनबर्ग, पाकिस्तान के संघशासित स्वायत्त कबायली क्षेत्र फाटा और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत एन डब्ल्यू एफ पी के अधिकारियों कैप्टन हयात ख़ान एवं हबीब ख़ान के साथ पिछले दिनों लगातार सघन यात्रा पर थे. एक बड़े ख़ुफ़िया अधिकारी बताते हैं कि मैथ्यू रोज़ेनबर्ग सीआईए और मोसाद दोनों के ही संयुक्त एजेंट हैं. मैथ्यू ने सीआईए के लिए तालिबान आतंकवादियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान की भी मुख़बिरी की थी. पाकिस्तान से उन्हें चेतावनी भी मिली थी. पर भारत में मैथ्यू के लिए ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि भारत के कई बड़े अधिकारी मैथ्यू की ही तरह सीआईए के एजेंट हैं. ख़ुफ़िया रिपोर्टों में इस बात की भी जानकारी दर्ज़ है कि विदेशी अख़बारों में रिपोर्ट करने के नाम पर शातिर जासूसों का दल दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाता है.

दूसरी ओर, आतंक का सफ़ाया करने के नाम पर भारत और अमेरिका के बीच ख़ुफ़िया सूचनाओं का धड़ल्ले से आदान- प्रदान हो रहा है. अमेरिका यह कहता है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जारी उसकी जंग में भारत एक प्रमुख सहयोगी है और इस बहाने पिछले दस-बारह सालों से भारत और अमेरिका के बीच ख़ुफ़िया सहयोग बढ़ता ही जा रहा है. इस ख़ुफ़िया सहयोग का एक परिणाम यह हो रहा है कि निर्णय लेने से पहले अधिकारी भारत के हितों से ज़्यादा विदेशी हितों का ध्यान रख रहे हैं.

भारत में जब एनडीए की सरकार थी, तब अमेरिका की एक अन्य ख़ुफ़िया एजेंसी एफबीआई को दिल्ली में ऑफिस खोलने की अनुमति भी दे दी गई थी. पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अमेरिकी एजेंसियों की भारत में मौज़ूदगी को सरकारी रूप से सत्यापित किया. और यहीं से शुरू हुआ भारत की ख़ुफ़िया सुरक्षा और लोकतंत्र में अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों का मज़बूत हस्तक्षेप.

हालांकि यह सिलसिला पचास के दशक से ही शुरू हो चुका था, पर उस वक़्त भारत में अमेरिका विरोधी माहौल था. सीबीआई के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि सीआईए ने बेहद योजनाबद्ध तरीक़े से भारतीय नेताओं, अधिकारियों को अपने जाल में फांसना शुरू किया. एजुकेशन टूर और फेलोशिप का चारा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मध्य प्रदेश के अतिरिक्त वन सचिव प्रशांत मेहता स्वीकार करते हैं कि पन्ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जहां बाघों की संख्या घटकर शून्य तक पहुंच चुकी है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाघ को बचाइए

बाघ विलुप्ति के कगार पर हैं. यह राष्ट्रीय चिंता की बात होनी चाहिए. जब आप राजस्थान के रणथंबौर राष्ट्रीय उद्यान आते हैं तो यहां आपकी उम्मीद जगती है. सैलानियों के ठहरने का एक आरामदायक ठिकाना शेरबाघ है. जैसल और अंजलि सिंह इसके मालिक हैं. जंगल में गाड़ी चलाने के लिहाज़ से जैसे अनुभवी ड्राइवरों की ज़रूरत होती है, यहां हाज़िर मिलेंगे. कहने की ज़रूरत नहीं कि यह भ्रमण के लिहाज़ से बेहतरीन जगहों में से एक है. बाघ को जंगल का राजा कहा गया है. रणथंबौर का राष्ट्रीय उद्यान 1400 एकड़ में फैला है. हाल के दिनों में बाघों की तेज़ी से घटती आबादी उद्यान प्रबंधन के लिए चिंता की बात रही है. ताजा अनुमान के मुताबिक़, रणथंबौर में अभी क़रीब 40 बाघ हैं. अभी वहां जैसे ऊर्जा से भरे एवं सक्षम ज़िला वन पदाधिकारी पदस्थापित हैं, ठीक वैसे ही वन पदाधिकारियों से अभयारण्य और वन्य जीवों की आबरू बचती है. पड़ोस में सरिस्का में जिस तरह की तबाही मची, वह इस बात की गवाह है. लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसके लिए नौकरशाही भी कम ज़िम्मेवार नहीं है.

मध्य प्रदेश के अतिरिक्त वन सचिव प्रशांत मेहता स्वीकार करते हैं कि पन्ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जहां बाघों की संख्या घटकर शून्य तक पहुंच चुकी है. ज़ाहिर है, शिकारियों और मानव घुसपैठियों से बाघ को बचाने के लिए अधिकारियों का अच्छा होना भी ज़रूरी है. रणथंबौर की सबसे बड़ी और स्वाभाविक समस्या यह है कि यहां सुरक्षित क्षेत्र के अंदर मंदिर है. यह यहां बढ़ते मानव प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. इससे वाणिज्यिक गतिविधियां भी बेलगाम रूप ले लेती हैं. लोगों की भीड़ पार्क के अंदर काफ़ी भीतर तक जाती है. उनका यह जमघट वन विभाग के लिए नाहक ही परेशानियां खड़ी करता है. वे स्वयं तो नियंत्रित नहीं ही हैं, उन पर कोई निगरानी भी नहीं होती. बाबुओं की नाकामी का यह मामला राजनीतिक उदासीनता और मिलीभगत से कई गुना बढ़ जाता है. हर जगह की यही कहानी है. बावजूद इसके पर्यटन मंत्रालय नैनीताल में जिम कॉर्बेट के नजदीक नए होटल बनवाने में बेदम है. वहां 17 और होटल शुरू होने वाले हैं. पार्क यहां पहले से ही होटलों में 3200 बिस्तर उपलब्ध करा पाने की स्थिति में है, जबकि यहां हर रोज़ औसतन 600 सैलानी ही आते हैं. पास में ही सैलानियों को एडवेंचर स्पोर्ट्स, डिस्कोथेक और रेन डांस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. वन्य इलाकों में पारिस्थितिकीय मानदंडों की सरासर अनदेखी की जा रही है. बाबू लोग इस अपराध में समान रूप से भागीदार हैं. यह एक राष्ट्रीय ख़तरा है. ज़िला वन पदाधिकारी और वन विभाग के दूसरे बाबू एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे वे पहले ही हार चुके हैं. पर्यटन विभाग के बाबू साफ़ तौर पर असहाय भी हैं. दिल्ली के बड़े बाबू लोगों की सुगबुगाहट जारी है, जबकि बाघ अतीत की याद बस बनने ही वाले हैं.

सुधारवादी सलाहकार

मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु का वित्त मंत्रालय में वह पहला दिन था, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने में परहेज ही रखा. दरअसल माइक्रोफोन के सामने रोचक बयान देने के लिहाज़ से अर्थशास्त्र को एक जटिल विषय के तौर पर ही देखा जाता है. बहरहाल मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाले बसु ने अपनी नई सेवा को अकादमिक दृढ़ता और शानदार गरिमा प्रदान की है. नौ जनवरी, 1952 को पैदा हुए कौशिक बसु कॉरनेल विश्वविद्यालय में अध्यापन कर चुके हैं. वहां वह प्रोग्राम ऑन कंपरेटिव इकॉनोमिक डेवलपमेंट के निदेशक रह चुके हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इकोनोमिक्स इन इंडिया का वह संपादन कर चुके हैं. इसके अलावा वह सोशल च्वाइश एंड वेलफेयर के भी संपादक हैं. वर्ल्ड बैंक इकोनोमिक रिव्यू के बोर्ड ऑफ एडिटर्स में भी शामिल हैं.

अपनी नई भूमिका में अब वह वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए व्यापक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराएंगे. वास्तव में उन्हें जो शुरुआती ज़िम्मेवारियां दी गई हैं, उनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने की ज़िम्मेवारी प्रमुख है. इसे इस साल फरवरी में किसी दिन संसद में पेश किया जाएगा. उनकी सुधारवादी छवि को देखते हुए जैसी कि उम्मीद है, बसु को वित्तीय क्षेत्र में और भी ज़्यादा सुधार लाने के लिए कहा जाएगा. ख़बर तो यह है कि उनके पास नौकरशाही में सुधार से संबंधित योजनाएं भी हैं. लेकिन हमें तो इसके लिए इंतज़ार करना और देखना होगा! बहरहाल, बसु के लिए सरकारी कामकाज का यह पहला तजुर्बा है. उनके पिता 1960 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं. पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वह एक ऐतिहासिक समानता भी रखते हैं. विमल जालान के पिता भी पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे.

कौशिक बसु का जन्म कोलकाता में हुआ था. वहीं उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की. 1969 में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज आ गए. 1974 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमएससी किया. उनके ख़ाते में कई अकादमिक उपलब्धियां हैं. कई शोध पत्रों का प्रकाशन और जनरल्स का संपादन करने वाले कौशिक बसु ने 1992 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स की स्थापना की और 1996 तक इसके एक्जक्यूटिव डाइरेक्टर रहे. वित्त मंत्रालय उनके सुधारवादी क़दमों की प्रतीक्षा कर रहा है.

सीआईए और मोसाद का मिशन हिंदुस्तान 2015

पृष्ठ एक का शेष

डालकर देश के जाने–माने लोगों के बच्चों को अमेरिका भेजने की रणनीति तैयार की गई. धीरे– धीरे देश में अमेरिकापरस्त लोगों की तादाद बढ़ती गई. उस वक़्त भारत पर सोवियत संघ का जादू चलता था. जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने देश में सीआईए, केजीबी आदि के एजेंटों की सेंधमारी पर कड़ाई से रोक लगाने की कोशिश भी की. बावज़ूद इसके उनके कैबिनेट में ही एक कद्दावर नेता सीआईए एजेंट के तौर पर मौज़ूद था. उसी वक़्त से सीआईए ने सरकार में हरेक स्तर पर अपनी मज़बूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी.

ख़ुफ़िया सूत्र बताते हैं कि यह नेता 1964 से ही सीआईए एजेंट का काम कर रहा था. जब 18 मई 1974 को पोखरन परीक्षण किया गया था, तब इस बात की सूचना पहले ही उसी नेता के ज़रिए सीआईए को मिल चुकी थी. उस समय जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे. उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी. वह इस बात से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने पटना की एक आमसभा में इस बात को ज़ाहिर भी कर दिया था. पर चूंकि उस नेता का क़द इतना बड़ा था कि सरकार की उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी.

बहरहाल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अमेरिका से नजदीकी रिश्ते बढ़ाने के इच्छुक नहीं थे. लिहाज़ा उनके ख़िलाफ़ अपने ही देश में अमेरिकापरस्त लोगों ने गोलबंदी शुरू कर दी. लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद धीरे–धीरे देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही गई, जो अमेरिका से दोस्ती के हिमायती थे. मनमोहन सरकार द्वारा परमाणु क़रार हो या वाजपेयी सरकार द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की बात. नरसिंह राव की सरकार हो या देवगौड़ा की, जिन्होंने परमाणु परीक्षण टालने की कोशिश की और उनकी इस कोशिश को अमेरिकापरस्ती के रूप में ही देखा गया. जब इराक युद्ध हुआ तो उस समय भारत की सत्ता पर क़ाबिज़ चंद्रशेखर की सरकार ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईंधन देने में मदद की. यह भी अमेरिका समर्थित लॉबी का ही दबाव था. भारत में लगभग हर दल में अपनी पैठ बना चुकी सीआईए के हौसले इसके बाद बढ़ते ही चले गए.

आज भी भारतीय न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर क़ब्ज़ा करने की सीआईए की मुहिम बदस्तूर जारी है. प्रधानमंत्री कार्यालय हो या रक्षा और गृह मंत्रालय. या फिर आईबी, रॉ, सीबीआई जैसी ख़ुफ़िया और जांच एजेंसियां. इन सभी के अधिकारियों का नियमित अंतराल पर अमेरिका जाना, प्रशिक्षण लेना और वर्कशाप के नाम पर लेक्चर देना इसी की कड़ी है. इन अधिकारियों को बाकायदा अमेरिका जाने की फेलोशिप दी जाती है. गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बेहद चिंतित अंदाज़ में कहा कि अमेरिका ख़ुफ़िया एजेंसियों की भारतीय तंत्र में घुसपैठ ने भारतीय ख़ुफ़िया और जांच एजेंसियों को उनका पिछलग्गू बना दिया है. भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों की औकात बस इतनी रह गई है कि वह अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों के सवालों का पूरी कर्तव्यपरायणता से जवाब दें. पर उनसे कोई सवाल न करें. अगर किसी केस के सिलसिले में भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियां सीआईए से सवाल करने की गुस्ताख़ी कर भी दें तो सीआईए उनको जवाब देना ग़ैरज़रूरी समझती है. भारतीय जांच एजेंसियों के लिए यह स्थिति बेहद अपमानजनक होती है. पर वे विवश हैं, क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की आग में झुलस रहा है. और ऐसे में अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों से मदद लेना उसकी मजबूरी बन चुकी है. पर इन सबके दरम्यान एक कड़वा सच यह भी है कि अमेरिका से अपने रिश्ते निबाहने की वज़ह से भारत की अपने पड़ोसी देशों से दूरियां बढ़ रही हैं, जो भारत के हित में कतई नहीं हैं. पर अमेरिका की योजना का हिस्सा ज़रूर हैं.

आईबी के एक सचिव स्तर के अधिकारी कहते हैं कि यह वही अमेरिका है, जो पहले खुलकर भारत का विरोध करता था, पर आज वह भारत को सहयोगी बताते नहीं अघाता. साफ़ है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के ख़िलाफ़ कर रहा है. उसी तरह, जैसे पहले वह पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन के ख़िलाफ़ करता था. आज अमेरिका की एजेंसियों ने कुछ भारतीय अधिकारियों को इस क़दर पालतू बना लिया है कि वे सीआईए के लिए राष्ट्रद्रोह करने तक को तैयार हैं. रॉ के भगोड़े अधिकारी रबिंद्र सिंह का उदाहरण हमारे सामने है.

रबिंद्र सिंह रॉ के संयुक्त सचिव थे. उन पर रॉ के साउथेस्ट एशिया डिपार्टमेंट को संभालने की ज़िम्मेदारी थी, पर काम वह सीआईए के लिए करते थे. जब यह बात सार्वजनिक हुई तो वह अमेरिका भाग गए. अमेरिका ने उन्हें बाइज़्ज़त शरण दी और उसके बदले रबिंद्र सिंह से दुनिया भर में हो रही भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों की गतिविधियों की गहनतम जानकारियां उगलवा लीं. भारत सरकार अमेरिका से इस पर नाराज़गी भी नहीं जता पाई.

सीआईए की साज़िश की जड़ें भारत में कितनी ग़हरी हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है कि सीआईए को न सिर्फ़ भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों की एक–एक योजनाओं की जानकारी रहती है, बल्कि नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बन रही रणनीतियों की भी उसे पूरी ख़बर होती है.

भारत को पूरी तरह पंगु बनाने की ख़ातिर सीआईए ने एक नया पैंतरा खेला है. आतंकवाद से निबटने के बहाने अमेरिका और इजरायल भारत पर अब इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह उनके उपकरण ख़रीदे और ख़ुफ़िया मिशन में उन्हीं का इस्तेमाल करे, ताकि सूचनाओं को साझा करने में कोई परेशानी न हो. तकनीकी उपकरणों की ख़रीद पर सरकारी बातचीत लगभग अंतिम चरण में है. पिछले दिनों हेडली प्रकरण के नाम पर सीआईए प्रमुख पैनेटा के भारत आने पर इस पर गंभीरता से बातें हुईं. उस वक़्त भारत के बड़े अधिकारियों के साथ इजरायल के गृह विभाग के उच्चाधिकारी भी मौज़ूद थे.

अब ज़रा सोचिए, अगर तकनीकी उपकरणों का साझा इस्तेमाल भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियां करने लगीं तो उनकी हल्की सी जुंबिश भी सीआईए और मोसाद की निग़ाह से नहीं बच सकती. और इस तरह भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियां पूरी तरह सीआईए और मोसाद की मुट्ठी में होंगी. यानी कि सुरक्षा के स्तर पर भारत को ख़ाक़ में मिलाने की पूरी तैयारी है.

ख़ुफ़िया विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि सीआईए की नज़रों में भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों की कोई अहमियत नहीं है. सीआईए के अधिकारी रॉ या आईबी के अधिकारियों पर रत्ती भर भरोसा नहीं करते. उनके साथ दोयम दर्ज़े का व्यवहार किया जाता है. जब कभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों या ख़ुफ़िया अधिकारियों का भारत आना हुआ है, सुरक्षा की पूरी कमान सीआईए अपने हाथों में ले लेती है. उस समय भारतीय ख़ुफ़िया अधिकारियों की भूमिका महज़ गूंगे–बहरे दर्शक की होती है. हवाई अड्डे से होटल या दूतावास तक की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकाल के दौरान भी भारतीय अधिकारी महज़ दिखावे की भूमिका में होते हैं. उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी जाती कि अमेरिकी अधिकारी या राष्ट्रपति का अगला कार्यक्रम क्या है?

ऐसे में ज़ाहिर है, आने वाले दिन भारतीय अस्मिता के लिए बेहद घातक साबित होने वाले हैं.

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 1 अंक 46,
दिल्ली, 25 जनवरी–31 जनवरी 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 011–23418962/0120–4783999
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ऐसे तथ्य, जो पिछले पांच वर्षों से चल रहे नरेगा कार्यक्रम को चौपट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. पहली बार कुछ ऐसी समस्याओं की पहचान की गई है.

नरेगा के सामने नई चुनौतियां

■ किराए पर चलता जॉबकार्ड का धंधा ■ दिन नहीं, काम की मात्रा पर मज़दूरी ■ प्रति भुगतान के बदले 10 रुपये कमीशन ■ नए कामों की कमी

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ गांवों में नरेगा की जांच के दौरान कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आए हैं, जो यूपीए सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं. चौथी दुनिया ऐसे ही पांच बिंदुओं का विश्लेषण कर रही है, जो नरेगा के लिए ख़तरा बन चुके हैं.

शशि शेखर

नरेगा यूं तो रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है, लेकिन कई ग़लत कारणों से अब यह भ्रष्टाचार गारंटी योजना में तब्दील हो चुका है. मस्टररोल, जॉब कार्ड और भुगतान आदि में घोटाले की ख़बरें तो पहले से ही आती रही हैं, लेकिन अब यह योजना कुछ बिल्कुल नई क़िस्म की समस्याओं की गिरफ़्त में है. दिल्ली की एक संस्था है करम (कॉलेज अवेयरनेस रिसर्च एंड मैनेजमेंट). देश के कई सेवानिवृत अर्थशास्त्रियों की देखरेख में चल रहा एक संगठन. बी एल जोशी इसके मुखिया हैं और नरेगा सहित आम आदमी से जुड़े कई मसलों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं. इनके नेतृत्व में करम ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव, मध्य प्रदेश के दमोह और कर्नाटक के कोलार एवं बंगलुरू के देहाती क्षेत्रों में नरेगा के तहत चल रहे कामों का जायज़ा लिया. पहली बार कुछ ऐसी समस्याओं की पहचान की गई है, जिनके बारे में अभी तक कल्पना भी नहीं की गई थी बहरहाल, हम ऐसे ही पांच सवालों (समस्याओं) को उठा रहे हैं, जिनकी अनदेखी से इस ड्रीम प्रोजेक्ट का दीवाला निकल सकता है.

पंजीकरण का टोटा

क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगेगा कि किसी गांव के 160 परिवारों में से महज़ 13 फ़ीसदी यानी 20 परिवार ही नरेगा के तहत पंजीकृत हों? उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के एक गांव के सिर्फ़ 20 परिवार ही इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और साल में महज़ 32 दिनों का काम इन लोगों को मिल पाता है. कर्नाटक के कोलार एवं बंगलुरू (देहात) क्षेत्र का तो इससे भी बुरा हाल है. यहां के महज़ 10 फ़ीसदी परिवार ही पंजीकृत हैं. जबकि मध्य प्रदेश के दमोह में हालात थोड़े अच्छे हैं. यहां के लगभग 56 फ़ीसदी परिवारों का नरेगा के तहत पंजीकरण है और साल में उन्हें लगभग 52 दिन काम भी मिल रहा है.

किराये पर जॉब कार्ड

करम के चेयरमैन बी एल जोशी एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं. कहानी उन्नाव के वीरसिंह पुरा गांव की है. जोशी बताते हैं कि सर्वेक्षण के दौरान जब वह इस गांव में गए तो उन्होंने वहां के प्रधान को काफ़ी परेशान देखा. वजह, गांव में नरेगा के तहत एक निर्माण कार्य चल रहा था और उसके लिए पांच मज़दूरों की ज़रूरत थी, लेकिन चार ही मिल पाए थे. जबकि गांव में 250 लोगों के पास जॉब कार्ड थे. जोशी ने जब प्रधान एवं गांव के अन्य लोगों से इस बारे में बातचीत की तो पता चला कि बहुत से जॉब कार्ड धारक नरेगा के तहत काम ही नहीं करना चाहते. वे अपना कार्ड ग्राम प्रधान अथवा ठेकेदार को 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर दे देते हैं. ठेकेदार अपने मज़दूरों से 50 रुपये देकर काम करा लेता है और बाकी पैसे ख़ुद रख लेता है. दिलचस्प रूप से यह सारा

उन्नाव के वीरसिंह पुरा गांव में नरेगा के तहत एक काम के लिए पांच मज़दूरों की ज़रूरत थी, लेकिन चार ही मज़दूर मिल पाए थे. मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में 250 लोगों के पास जॉब कार्ड थे. खोजबीन करने पर पता लगा कि ज़्यादातर लोग नरेगा के तहत काम ही नहीं करना चाहते. कुछ तो अपना कार्ड गांव के प्रधान या ठेकेदार को 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर दे देते हैं और घर बैठे ही कमा रहे हैं. ठेकेदार अपने मज़दूरों से 50 रुपये देकर काम करा लेता है और बाकी के पैसे ख़ुद रख लेता है.

बी एल जोशी
चेयरमैन, कॉलेज अवेयरनेस रिसर्च एंड मैनेजमेंट

धंधा इतने सलीके से होता है कि कोई उंगली तक नहीं उठा सकता.

किराया दो, पैसा लो

नरेगा के तहत सभी कार्डधारकों का खाता डाकघर अथवा बैंक में खुलता है. यहीं से मज़दूरों की पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है. लेकिन, यहां भी कम गोरखधंधा नहीं है. जोशी बताते हैं कि अलवर ज़िले के एक गांव में ऐसा ही मामला देखने को मिला. वहां के डाकघर में जब कोई मज़दूर अपना भुगतान लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि किसी ऐसे आदमी के साथ आओ, जो तुम्हें और मुझे यानी दोनों को पहचान सके. अंतत:, तीन–चार महीनों के बाद बैंक या डाकघर का कोई क्लर्क गांव में जाकर प्रधान के सामने सभी मज़दूरों का भुगतान करता है. इसके बदले वह प्रति भुगतान 10 रुपये यह कहकर लेता है कि मैं शहर से आया हूं और इसमें मेरा ख़र्च हुआ है. ज़ाहिर है, अगर सौ लोगों से भी दस–दस रुपये मिले तो उस कर्मचारी को बिना कुछ किए एक हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है.

काम पूरा, पैसा कम

सर्वेक्षण से यह भी भी पता चला कि मज़दूरों को उनके काम के दिनों के आधार पर नहीं, बल्कि काम की मात्रा को पैमाना बनाकर भुगतान किया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर, चार–पांच लोगों के एक समूह को एक ख़ास काम दे दिया जाता है और फिर जितने दिनों में वह काम हो पाता है, उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक़, दमोह के एक गांव में एक पुरुष साल में 27 दिन काम करके भी 1887 रुपये ही कमा पाता है. जबकि कर्नाटक में यह आंकड़ा 22 दिन के बदले 2173 रुपये का है. वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में एक महिला साल में 23 दिन काम करके 1546 रुपये कमा पाती है.

नए कामों की कमी

नरेगा के तहत यह नया प्रावधान किया गया है कि किसी गांव में अगर एक काम होता है तो दोबारा फिर वही काम नहीं होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि एक गांव में कितने तालाब खोदे जाएंगे या कितनी सड़कें बनेंगी? ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में लोगों के पास काम की कमी होना तय है, लेकिन इस समस्या का भी कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा है. जोशी बताते हैं कि सर्वेक्षण के दौरान उन्हें एक भी ऐसा मामला नहीं दिखा, जहां काम न मिलने पर किसी जॉबकार्ड धारक को बेरोज़गारी भत्ता दिया गया हो.

निश्चित तौर पर, ये पांच समस्याएं नरेगा के लिए बड़ी चुनौती हैं जिससे तत्काल निपटने की ज़रूरत है. क्योंकि नरेगा सिर्फ़ यूपीए सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है जो उसकी राजनीतिक ख्वाहिश को पूरा कर रहा है. बल्कि, इस योजना में इतनी ताक़त है जो गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के सपनों को भी साकार कर सकती है. एक ख़ुशहाल जीवन का सपना.

shashishekhar@chauthiduniya.com

पंजीकृत परिवार (2009)

राज्य	पंजीकृत	पंजीकृत नहीं	कुल	प्रतिशत	दिनों की औसत संख्या (नरेगा के तहत काम मिला)
उत्तर प्रदेश (उन्नाव)	20	140	160	13	31.38
मध्य प्रदेश (दमोह)	79	62	141	56	51.24
कर्नाटक (बंगलुरू देहात, कोलार)	17	161	178	10	54
कुल	116	363	479	24	48.25

प्रति पंजीकृत परिवार की औसत आय (मजदूरी) 2009

राज्य	औसत आय (मजदूरी, रुपये में) पुरुष	महिला
उत्तर प्रदेश (उन्नाव)	2520	3000
मध्य प्रदेश (दमोह)	1887	1546
कर्नाटक (बंगलुरू देहात, कोलार)	2173	2144

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों को जारी जॉब कार्डों की संख्या उनकी संख्या से भी ज़्यादा है, जिन्हें रोज़गार की तलाश है.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (नरेगा) योजना

योजना में भारी भ्रष्टाचार

डॉ. शरद रंजन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के कार्यान्वयन को व्यापक तौर पर गांव की ग़रीबी और अभावग्रस्तता को दूर करने के कारगर उपाय के तौर पर देखा जा रहा है, बावजूद इसके गांव से शहरों की ओर पलायन जारी है. यह ऐसी पहली योजना है, जो ग़रीब अकुशल दिहाड़ी मज़दूरों को क़ानूनी रूप से काम का अधिकार देती है. यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देश के ग्रामीण परिवारों के वैसे वयस्क सदस्यों, जो स्वैच्छिक रूप से अकुशल कार्य करने को तैयार हों, को आजीविका की गारंटी देती है. काम की क़ानूनी गारंटी देकर नरेगा पूर्व के रोज़गार- मज़दूरी संबंधी तमाम कार्यक्रमों के बीच अपनी एक उल्लेखनीय पहचान बना सकी है. यह एक अधिनियम है, सिर्फ़ योजना नहीं. इसलिए यह देश की ग़रीब जनता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. लेकिन जैसा सही तरीक़े से उठाए गए क़दमों के साथ अमूमन होता है, यह पाया गया कि इस योजना के साथ कुछ बुनियादी परेशानियां हैं और शुरुआती दौर में इस योजना के साथ सब कुछ सही नहीं हुआ. उत्तर प्रदेश में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में इस योजना को कितनी कामयाबी मिल पाई और सामाजिक ढांचा इससे कितना प्रभावित हो पाया, यह जानने के लिए वर्ष 2008-09 में इसके कार्यान्वयन का वेबसाइट www.nrega.nic.in और ज़िलों की प्रति व्यक्ति आमदनी से जुड़े आंकड़े www.upgov.up.nic.in से जुटाए.

लोगों को जारी जॉब कार्ड

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों को जारी जॉब कार्डों की संख्या उनकी संख्या से भी ज़्यादा है, जिन्हें रोज़गार की तलाश है. मध्य, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में जितने कार्ड होने चाहिए, अतिरिक्त जारी कार्ड उससे 40 गुना ज़्यादा थे. विभिन्न क्षेत्रों के कुछ ज़िलों में बड़ी संख्या में जॉब कार्ड जारी किए गए थे और कई मामलों में यह संख्या औसत से भी ज़्यादा है. अलग-अलग क्षेत्रों में जहां फ़र्ज़ी कार्डों की संख्या क्षेत्रीय औसत और ज़रुरत से भी ज़्यादा पाई गई, उनमें मध्य क्षेत्र में बाराबंकी में 53 फ़ीसदी, सीतापुर में 50 फ़ीसदी, पूर्वी क्षेत्र में मऊ में 63 फ़ीसदी, बलरामपुर में 59 फ़ीसदी, आजमगढ़ में 55 फीसदी, संत कबीरनगर में 51 फ़ीसदी और पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ में 66 फ़ीसदी एवं बिजनौर में 58 फ़ीसदी आदि शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जारी फ़र्ज़ी कार्डों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा यानी 64 था. इसके दो ज़िलों में तो मानों हद की सीमा ही लांघ दी गई. चित्रकूट में यह 90 फ़ीसदी था तो महोबा में 70 फ़ीसदी. एबीएसएसएस सर्वेक्षण में जिस नतीजे पर पहुंची, उससे आप वाक़िफ़ हो चुके हैं. हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, उसकी सत्यता की पुष्टि तब हो गई, जब हमने यह पाया कि ज़िलों में दस्तावेजी सबूतों के अनुसार जो जॉब कार्ड जारी किए गए थे, वे अपेक्षित संख्या से काफ़ी अधिक थे. यह बात जानकर तो और भी निराशा हुई कि फ़र्ज़ी कार्ड अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए हैं.

जरूरत से ज्यादा संख्या में जारी फर्जी कार्डों का प्रतिशत

क्षेत्र	कुल परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए	कुल परिवार जिन्हें रोजगार	जिले की जरूरत थी	अतिरिक्त जारी कार्डों का प्रतिशत
मध्य क्षेत्र (41%)*	2624358	1074078	बाराबंकी	53
			सीतापुर	50
पूर्वी क्षेत्र (40%)*	5041642	2007377	मऊ	63
			बलरामपुर	59
			आजमगढ़	55
			संतकबीर नगर	51
दक्षिणी क्षेत्र (64%)*	2219329	768103	चित्रकूट	90
			महोबा	70
पश्चिमी क्षेत्र (35%)*	766689	488932	मेरठ	66
			बिजनौर	58

*रोजगार मांगने वाले वास्तविक ग्रामीण परिवारों की संख्या और उसके अनुपात में जारी जॉब कार्डों की संख्या.

स्रोतः आंकड़े www.nrega.nic.in पर उपलब्ध हैं.

सौ दिन के रोज़गार का झूठा वायदा

नरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल दिहाड़ी मज़दूरों को साल में सौ दिन रोज़गार देने की बात कही गई है. जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो दुर्भाग्यवश वहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. हमने जो पाया, उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है. रिकार्ड के मुताबिक़, वहां केवल 14 फ़ीसदी ग्रामीण परिवारों को ही साल में सौ दिनों का रोज़गार मिल पाया. अलग-अलग क्षेत्रों में इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला. उत्तरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 30 फ़ीसदी था तो पूर्वी क्षेत्र में 16. मध्य क्षेत्र में दस और पश्चिमी क्षेत्र में केवल सात फ़ीसदी. ग़ौर करने वाली बात यह है कि रोज़गार की इच्छा रखने वाले परिवारों में से सबसे ज़्यादा लोगों को सौ दिनों का रोज़गार दक्षिणी क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया. ऐसा उस क्षेत्र में हुआ, जिसमें बमुश्किल सात ज़िले शामिल हैं और जहां प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में नरेगा के मद में पर्याप्त रक़म ख़र्च की गई. अलग-अलग ज़िलों में भी इसमें काफ़ी फ़र्क़ दिखा. उदाहरण के लिए सौ दिन रोज़गार पाने वाले परिवारों का प्रतिशत मेरठ में 0.58, देवरिया में 0.95, कन्नौज में 0.95 और कुशीनगर में 1.64 था. इन मामूली परिणामों से इन ज़िलों में ख़राब कार्यान्वयन का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है. बहरहाल कई ज़िलों, जैसे पीलीभीत (पश्चिमी क्षेत्र) में 69 फ़ीसदी, गोण्डा (पूर्वी क्षेत्र) में 52 फ़ीसदी, महोबा (मध्य क्षेत्र) में 39 फ़ीसदी और बांदा (दक्षिणी क्षेत्र) में 32 फ़ीसदी परिवारों को सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया गया. बावजूद इसके कि कई शिक़ायतें भी थीं, जैसे मज़दूरी का कम भुगतान, कार्ड धारकों को भी रोज़गार उपलब्ध न करा पाना, घटिया सामग्री का इस्तेमाल और फ़र्ज़ी मस्टर रोल आदि. ये बिंदु लाभांवितों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना आवेदक परिवारों को सौ दिनों का रोज़गार उपलब्ध करा पाने के प्रावधान में कोई ठोस प्रगति करने में विफल रही है.

क्षेत्रीय स्तर पर काम की मांग करने वाले योग्य परिवारों को सौ दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के संबंध में उक्त आंकड़े रोचक तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं. मध्य क्षेत्र के दस ज़िलों में नरेगा योजनाओं के मद में 85.5 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए, जबकि बमुश्किल 10 फ़ीसदी अर्हता प्राप्त परिवारों में से दस फ़ीसदी को ही रोज़गार उपलब्ध कराया जा सका. इसकी तुलना में पश्चिम क्षेत्र जिसके अंतर्गत 26 ज़िले आते हैं, वहां 18.9 करोड़ रुपये ख़र्च करके आठ फ़ीसदी परिवारों को सौ दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराया गया. पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में ख़र्च में हेराफेरी के स्पष्ट प्रमाण दिखे.

कम विकसित क्षेत्रों में नरेगा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बहुत ध्यान दिए जाने और इन इलाक़ों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ज़्यादा रक़म ख़र्च किए जाने की ज़रुरत है. अगर हम बतौर विकास सूचकांक वर्ष 2006-07 में ज़िलों की प्रति व्यक्ति आमदनी (1993-94 की कीमत पर) के आधार पर उत्तर प्रदेश के कम विकसित ज़िलों की पहचान करें तो मालूम होगा कि नरेगा फंड का सही तरीक़े से वितरण नहीं हुआ. सांख्यकीय जांच में हमने नरेगा फंड के प्रावधान और प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के बीच मज़बूत एवं सकारात्मक सहसंबंध पाया. अकेले इस क्षेत्र में प्रदेश के 40 ज़िले आते हैं. यह इस बात का संकेत है कि योजना के कार्यान्वयन में सब कुछ सही नहीं है. जिनके लिए यह योजना बनाई गई है, कार्यान्वयन के स्तर पर भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है. कार्यान्वयन में पारदर्शिता ज़रूरी है.

नरेगा योजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव

नरेगा योजना मज़दूरों को रोज़गार की वैधानिक गारंटी देती है. इसलिए यह समाज के सबसे वंचित लोगों- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अक्षम लोगों के लिए नई और क्रांतिकारी कोशिश है. इसमें कम से कम एक तिहाई मज़दूर अनिवार्य रूप से महिला होने की बात कही गई है. लेकिन इसमें काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है. वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के कामों में सिर्फ़ 19.3 फ़ीसदी महिलाओं को ही रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए. क़ानून में महिलाओं को 33 फ़ीसदी अनिवार्य रूप से हिस्सेदारी देने की जो बात कही गई है, उससे यह बिल्कुल अलग है. अक्सर औरतों को काम न देने के पीछे ख़ास काम के लिए शारीरिक रूप से उनके कमज़ोर होने की बात कही जाती है. कुछ मामलों में यह कहा जाता है कि वे ख़ास कामों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं. कार्यस्थल पर बच्चों की देखरेख की सुविधा का अभाव एक और महत्वपूर्ण कारण है, जिसके चलते नरेगा के कामों में महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है. कार्यस्थल पर ठेकेदार की उपस्थिति भी नरेगा के कामों से महिलाओं के दूर रहने की वजह बताई जाती है. यह शिक़ायत आम है कि ठेकेदार महिलाओं का किसी न किसी रूप से शोषण करते हैं. भुगतान में देरी को भी इसकी एक प्रमुख वजह समझी जाती है. जब उन्हें समय से मज़दूरी नहीं मिल पाती है तो वे पुराने कामों की ओर लौट जाते हैं. खेरा और नंदिनी ने 2009 में अपने अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश में नरेगा के कामों में कई जगहों पर महिलाओं को 15 दिन की अवधि के भीतर मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया था. ये कुछ ऐसे आधार हैं, जो महिलाओं को न केवल नरेगा के कामों से दूर, बल्कि उन्हें आर्थिक लाभ से भी वंचित रखते हैं. पिछले साल भर के दौरान उन्हें केवल 18 दिनों का काम ही क्यों मिला, यह अध्ययन का विषय है. उनमें से ज़्यादातर (क़रीब 83 फ़ीसदी) रोज़गार के वैकल्पिक उपायों के बारे में सोच रहे हैं. केवल इतना ही नहीं, उनमें से किसी ने भी काम के बदले मज़दूरी नहीं प्राप्त की थी.

यह सही है कि खेरा और नंदिनी ने नरेगा योजनाओं में महिलाओं के साथ भेदभाव पाया, लेकिन साथ ही उन्होंने उनके परिवार में कई सामाजिक लाभ भी देखे. इस योजना ने उनके परिवार को भुखमरी का शिकार होने से बचाने का काम किया. 17 फ़ीसदी महिलाओं ने स्वीकार किया कि इस योजना के अंतर्गत मज़दूरी मिलने से उन्हें रोज़गार की तलाश में घर से दूर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा और इस तरह वे शोषण से काफी हद तक बच सकीं. इतने ही लोगों ने यह माना कि इस योजना के अधीन काम करने की वजह से वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर पाए और बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी एहतियात बरत पाए. 50 फ़ीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि वे अपने बच्चों के स्कूल की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठा पा रहे हैं और 67 फ़ीसदी ने क़र्ज़ उतार पाने में सक्षम होने की बात कही. नरेगा योजना में तमाम फ़र्ज़ीवाड़े और कमियों के बावजूद कई अच्छाइयां हैं और इसने कई घरों को ख़ुशियां दी हैं. इसके अलावा नरेगा योजना पर ख़र्च ने भी प्रति व्यक्ति रोज़गार के दिनों में बढ़ोतरी में मदद की. अध्ययन और पड़ताल के आधार पर यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नरेगा योजनाओं में जॉब कार्ड जारी करने में भ्रष्टाचार और हेराफेरी के सबूत हैं. अलग-अलग ज़िलों में इसका प्रतिशत अलग है और कहीं-कहीं तो यह 90 प्रतिशत तक है. इसके अलावा जानबूझ कर भेदभाव की बातें भी देखने को मिलीं. जैसे फंड के उपयोग और स्थान एवं वंचित लोगों के चुनाव आदि में. महिला मजदूरों के मामले में श्रम क़ानूनों का भी खुला उल्लंघन देखने को मिला. इस योजना में जन कल्याण की अपार संभावनाएं छिपी हैं. अगर सही तरीक़े से इसे लागू किया गया तो यह समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने और ग़रीबी एवं अभावग्रस्तता को दूर करने की ताक़त रखती है.

उत्तर प्रदेश में महिला मजदूरों को मिला आर्थिक लाभ

(कुल महिला मज़दूरों की उम्र का प्रतिशत)

महिलाओं की भागीदारी	05
विगत एक साल के दौरान नरेगा के अंतर्गत मिले काम के दिन	18
उन महिलाओं की संख्या, जिन्होंने अपनी मजदूरी प्राप्त की	00
उन महिलाओं की संख्या, जिन्होंने अपनी मज़दूरी रखी	00
पिछले तीन माह में जिनके पास नक़द आमदनी के दूसरे स्रोत थे	03

स्रोतः खेरा और नंदिनी (2009)

नरेगा योजना से लाभ होने की बात स्वीकार करने वाली महिला मज़दूर

महिला मज़दूरों ने जिन फायदों की बात कही	(प्रतिशत में)
भुखमरी से मुक्ति	100
पलायन से बचे	17
बीमारी से बचाव	17
खतरनाक कामों से छुटकारा	20
क़र्ज़ उतार पाने में सक्षम	67
बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं	50

स्रोतः खेरा और नंदिनी (2009)

feedback@chauthiduniya.com

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन पीजी इवनिंग कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.)

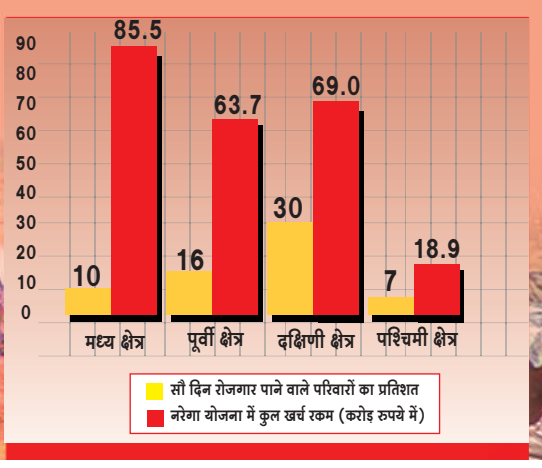

अगर जेल को छोड़ दें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हर कहीं कम है. आबादी के अनुपात में जेलों में उनकी उपस्थिति अवश्य अधिक है.

मुसलमान सबसे पीछे क्यों?

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

आज़ादी के बाद से ही देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा में लगातार गिरावट देखी जा रही है. उनकी दशा गिरकर अनुसूचित जाति के स्तर तक जा पहुंची है या फिर उससे भी बदतर. कुछ राजनेताओं, व्यक्तियों और ग़ैर सरकारी संगठनों की तो राय है कि समुदाय की ऐसी हालत के लिए ख़ुद मुसलमान ही ज़िम्मेवार हैं. राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने और देश के विकास में योगदान करने के बजाय उन्होंने अलग–थलग रहना पसंद किया. न सिर्फ़ राष्ट्र की मुख्यधारा से, बल्कि समाज से भी. मुसलमान अगर राष्ट्रीय मुख्यधारा और समाज से कट कर नहीं रहे होते तो वे इसके फ़ायदे के हिस्सेदार भी होते.

बहरहाल, देश के विभाजन के बाद विकास के दौर का अगर बारीक़ी से विश्लेषण करें तो जो तथ्य सामने आता है, वह इन आरोपों के बिल्कुल विपरीत है. मुसलमान अब भी विकास के हर क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं, इसकी हर मुमकिन कोशिश की गई है. हर क्षेत्र, जैसे कि निर्वाचित निकायों, रोज़गार के क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाओं आदि तो बस कुछ उदाहरण भर हैं, जिनमें उनके प्रवेश का आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद किया गया. आज मुसलमानों की जो दयनीय दशा है, उसके लिए आज़ादी के बाद देश में बनी सरकारें पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं. देश के विभाजन के बाद मुसलमानों का जो प्रबुद्ध और संपन्न तबका था, वह पाकिस्तान चला गया. लेकिन वे मुसलमान जो उस समय की मुस्लिम लीग की बातों में नहीं आए और जिन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहना पसंद किया, आज न केवल अशिक्षित और ग़रीब हैं, बल्कि बुरी तरह दमित, डरे हुए और हाशिए पर हैं. उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा अनुसूचित जाति में शामिल लोगों जैसी ख़राब है, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा बदतर है.

भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज़रिए अंग्रेजों ने मुसलमान अनुसूचित जातियों को भी दूसरे हिंदू हमपेशों के साथ आरक्षण की सुविधा दी थी, लेकिन आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश (अनुसूचित जाति) 1950 के ज़रिए इसे वापस ले लिया. यहां यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा तक ने भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को बग़ैर किसी संशोधन के 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार कर लिया था. ऐसा लगता है, मानो स्वतंत्रता के बाद हमारा धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व अपना संविधान लागू करने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसने आनन– फानन में अध्यादेश जारी करा दिया. यह संविधान सभा के निर्णय का खुला उल्लंघन कहा जाएगा. देश के मुसलमानों के प्रति कभी न ख़त्म होने वाली दुर्भावना और भेदभाव की वह शुरुआत थी और यह सजा आज भी बदस्तूर जारी है. उन्हें अशिक्षा, ग़रीबी और भुखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया गया है. अगर जेल को छोड़ दें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हर कहीं कम है. आबादी के अनुपात में जेलों में उनकी उपस्थिति अवश्य अधिक है. मुसलमान सालों से जेल में हैं और ज़्यादातर मामलों में उनका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और अगर शुरू भी हुआ है तो वह प्रारंभिक अवस्था में ही है. ज़्यादातर मामलों में अदालत को उनके ख़िलाफ़ कोई महत्वपूर्ण सुराग़ हाथ नहीं लगे. 22–24 अगस्त, 2008 को हैदराबाद में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लोगों की लोक अदालत लगी थी, जिसमें विगत दो साल के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपी मुसलमानों के उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में यह पाया गया कि जिन पर दोष सिद्ध नहीं हो सका और उन्हें रिहा किया तो गया, लेकिन कई साल तक ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से बंदी बनाए रखने के बाद. सरकार की एजेंसियों द्वारा उठाए गए ग़ैर क़ानूनी क़दम से इन भुक्तभोगियों और उनके परिवारों को जो परेशानी हुई, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा?

बहरहाल, सिर्फ़ नमूने के तौर पर केवल तीन क्षेत्रों यानी निर्वाचित निकाय, रोज़गार और शिक्षा में मुसलमानों के कमज़ोर प्रतिनिधित्व के कारणों की समीक्षा की जाए और इसका इतिहास 1947 से खंगाला जाए तो आपको इस बात का आसानी से पता चल जाएगा कि मुसलमानों की प्रगति की राह में किस तरह से रुकावटें पैदा की गईं.

निर्वाचित निकायों में मुसलमान

लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अलग–अलग धड़ों से इस बात को लेकर ख़ूब बावेला मचा कि संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है. यह दलील दी गई कि संसद में लोकसभा की 543 सीटें हैं और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़, देश में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत 13.4 है. इसलिए लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 543 का 13.4 फ़ीसदी यानी 72.76 यानी 73 होना चाहिए. जबकि वर्ष 2009 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या केवल 30 (केवल 41 फीसदी) है और इस तरह उसे 43 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा. इस कमी की कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे कि सही नेतृत्व का अभाव, एकजुटता की कमी, वोट का बंटवारा, अशिक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी का अभाव वग़ैरह. लेकिन, दूसरे कारकों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ज़िम्मेवार हैं, वे राष्ट्रपति के दो अध्यादेश हैं. एक तो संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 और दूसरा संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जनजाति) 1950 है. उक्त आदेश भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी किए थे. संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 दरअसल हमारे पंथनिरपेक्ष संविधान की भावना का आपराधिक उल्लंघन है. यह आरक्षण की सुविधा को केवल हिंदू धर्म मानने वालों तक सीमित कर देता है. आरक्षण की सुविधा जिन अनुसूचित जनजातियों को दी गई है, सुदूर लक्षद्वीप के अपवाद को छोड़ दें तो मुसलमानों में उनका कहीं अस्तित्व नहीं है. संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 के कारण हिंदू धर्म को छोड़ कर हर धर्म के अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हैं. इसलिए पूरे देश में इस अन्याय के ख़िलाफ़ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई. सिखों और बौद्धों ने तो इस आदेश के ख़िलाफ़ तीव्र विरोध जताया था. विभाजन के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि मुसलमान ख़ुद ही परेशानी में थे. लेकिन बौद्धों और सिखों के विरोध ने सरकार को आदेश में सुधार करने पर मजबूर कर दिया. सिखों को अनुसूचित जातियों की सूची में 1956 में और बौद्धों को 1990 में शामिल कर लिया गया. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 में धार्मिक आधार पर भेदभाव जारी ही रहा. इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो दलित पेशे से जुड़े हैं, छह दशक के बाद भी उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. मुसलमान अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के कुल अनुसूचित जनजातियों की केवल 0.25 फ़ीसदी ही होगी. ज़्यादातर लक्षद्वीप में हैं. वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़, अनुसूचित जाति और जनजातियां मिलकर देश की कुल आबादी की 24 फ़ीसदी (अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत और जनजाति आठ प्रतिशत) होंगी. इसका मतलब यह है कि देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण क़रीब 24 फ़ीसदी है. जबकि मुसलमान, जो कि संवैधानिक तौर पर आरक्षण का लाभ पाने के पात्र हैं, उन्हें 0.1 फ़ीसदी भी आरक्षण की सुविधा हासिल नहीं है. विडंबना तो यह है कि जहां हिंदू, सिख और बौद्ध संवैधानिक रूप से 100 फ़ीसदी (सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) सीटों या रिक्तियों के लिए कोशिश करते हैं तो मुसलमान केवल 76 फ़ीसदी सीटों (सामान्य और अनुसूचित जनजाति, जिसका मुसलमानों में अस्तित्व ही नहीं है) की पात्रता रखते हैं. 1950 में प्रस्तुत राष्ट्रपति के इन अध्यादेशों और इनमें संशोधन के बाद संसद एवं विधानसभाओं में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध सीटों की जो स्थिति है, उसे हम साथ दी गई तालिका से समझ सकते हैं. (देखें तालिका)

सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उत्साहवर्द्धक नहीं है. इस बात का ज़िक्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है.

लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का विवरण

क्र.सं.	राज्य एवं संघशासित प्रदेश	अनुसूची–एक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का विवरण						अनुसूची–दो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का विवरण					
		वर्ष 2004 में पार्लियामेंटरी एंड एसेंबली कंस्टीच्युएंसीज ऑर्डर, 1976 (समय–समय पर संशोधित) के आधार पर सदन में सीटों की संख्या			पार्लियामेंटरी एंड एसेंबली कंस्टीच्युएंसीज ऑर्डर, 2008 के आधार पर सदन में सीटों की संख्या			वर्ष 2004 में पार्लियामेंटरी एंड एसेंबली कंस्टीच्युएंसीज ऑर्डर, 1976 (समय–समय पर संशोधित)के आधार पर सदन में सीटों की संख्या			पार्लियामेंटरी एंड एसेंबली कंस्टीच्युएंसीज ऑर्डर, 2008 के आधार पर सदन में सीटों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	42	6	2	42	7	3	294	39	15	294	48	19
3	अरुणाचल	2	-	-	2	-	-	60	-	59	60	-	59
4	असम	14	1	2	14	1	2	126	8	16	126	8	16
5	बिहार	40	7	-	40	6	-	243	39	-	243	38	2
6	चंडीगढ़	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	11	2	4	11	1	4	90	10	34	90	10	29
8	दादर नागर हवेली	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9	दमन दीव	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	गोवा	2	-	-	2	-	-	40	1	-	40	1	-
11	गुजरात	26	2	4	26	2	4	182	13	26	182	13	27
12	हरियाणा	10	2	-	10	2	-	90	17	-	90	17	-
13	हिमाचल	4	1	-	4	1	-	68	16	3	68	17	3
14	जम्मू कश्मीर	6	-	-	6	-	-	87	7	-	87	*	*
15	झारखंड	14	1	5	14	1	5	81	9	28	81	9	28
16	कर्नाटक	28	4	-	28	5	2	224	33	2	224	36	15
17	केरल	20	2	-	20	2	-	140	13	1	140.	14	2
18	लक्षद्वीप	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	29	4	5	29	4	6	230	33	41	230	35	47
20	महाराष्ट्र	48	3	4	48	5	4	288	18	22	288	29	25
21	मणिपुर	2	-	1	2	-	1	60	1	19	60	1	19
22	मेघालय	2	-	2	2	-	2	60	-	55	60	-	55
23	मिजोरम	1	-	1	1	-	1	40	-	39	40	-	39
24	नागालैंड	1	-	-	1	-	-	60	-	59	60	-	59
25	दिल्ली	7	1	-	7	1	-	70	13	-	70	12	-
26	उड़ीसा	21	3	5	21	3	5	147	22	34	147	24	33
27	पुडुचेरी	1	-	-	1	-	-	30	5	-	30	5	-
28	पंजाब	13	3	-	13	4	-	117	29	-	117	34	-
29	राजस्थान	25	4	3	25	4	3	200	33	24	200	34	25
30	सिक्किम	1	-	-	1	-	-	32	2	12	32	2*	12*
31	तमिलनाडु	39	7	-	39	7	-	234	42	3	234	44	2
32	त्रिपुरा	2	-	1	2	-	1	60	7	20	60	10	20
33	उत्तराखंड	5	1	-	5	1	-	70	12	3	70	13	2
34	उत्तर प्रदेश	80	17	-	80	17	-	403	89	-	403	85	-
35	पश्चिम बं.	42	8	2	42	10	2	294	59	17	294	68	16
	कुल	543	79	41	543	84	47	4120	570	532	4120	607	554

रोज़गार

I.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	3 प्रतिशत
II.	भारतीय पुलिस सेवा	4 प्रतिशत
III.	भारतीय विदेश सेवा	1.8 प्रतिशत
IV.	भारतीय रेलवे 4.5 प्रतिशत (इनमें से तक़रीबन 98.7 प्रतिशत लोग कनिष्ठ स्तर की सेवाओं में हैं.)	
V.	सुरक्षा एजेंसियां	4 प्रतिशत
VI.	शिक्षा विभाग	6.5 प्रतिशत
VII.	गृह विभाग	7.5 प्रतिशत
VIII.	सिपाही	6 प्रतिशत
IX.	स्वास्थ्य विभाग	4.4 प्रतिशत

(स्रोतः सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 165, 167, 168, 172 और 173)

शिक्षा

देश के प्रमुख कॉलेजों में

I.	अंडर ग्रेजुएट	4 प्रतिशत
II.	पोस्ट ग्रेजुएट	2 प्रतिशत

(स्रोतः सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 69)

प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट में

I.	आईआईएम	1.3 प्रतिशत
II.	आईआईटी	3.3 प्रतिशत

(स्रोतः सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 68–69)

दरअसल यह केवल देश के मुसलमानों के सशक्तिकरण का सवाल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है. दुनिया का कोई भी देश अपनी 150 मिलियन से ज़्यादा आबादी को अशिक्षा, ग़रीबी और भुखमरी से जूझने के लिए छोड़कर प्रगति के बारे में भला कैसे सोच सकता है?

विश्लेषण

संसद

I. मुसलमान और ईसाई दोनों को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 84 सीटों पर चुनाव लड़ने से अलग रखा गया है.

II. मुसलमान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 47 में से 46 सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनमें अनुसूचित जनजाति का अस्तित्व न के बराबर है. मुसलमान केवल लक्षद्वीप की एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं.

III. मुसलमान लोकसभा की कुल 543 सीटों में से केवल 413 (76 फ़ीसदी) सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं.

विधानसभा

I. मुसलमान और ईसाई दोनों को विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 607 सीटों पर चुनाव लड़ने से अलग रखा गया है.

II. अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी 554 सीटों पर मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनमें अनुसूचित जनजाति न के बराबर है.

III. देश की तमाम विधानसभाओं की सीटों की अगर बात करें, तो मुसलमान केवल 70 फ़ीसदी सीटों पर ही चुनाव लड़ सकते हैं.

अहमद सोहेल सिद्दीक़ी
feedback@chauthiduniya.com

पीड़ित पतियों के लिए काम कर रही सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और घरेलू हिंसा क़ानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इनमें संशोधन की मांग कर रही है.

पत्नियां इतनी बुरी होती हैं !

विमल राय

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी देवाशीष सरकार ने 30 नवंबर 2006 को जब ग्रेजुएट देवारती दत्त सरकार से शादी की तो उनके सामने थे केवल सुनहरे सपने. लेकिन सपने पापड़ की तरह अचानक चूर-चूर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहां सोचा था. शादी के एक साल बाद से ही पत्नी उन्हें उस प्राइमरी स्कूल के पास घर लेने के लिए दबाव डालने लगी, जहां वे पढ़ाते थे. बूढ़े मां-बाप की देखरेख के लिए ही वह 50 किलोमीटर दूर का सफर रोज तय करते थे. सितंबर 2007 में वह पैदा हुआ. दो माह बाद वह अचानक मायके चली गई और फिर उसने वापस लौटने से इंकार कर दिया. उसने देवाशीष को नौकरी छोड़ कर उसके साथ तमिलनाडु में बसने का प्रस्ताव दिया, जहां उसका एक भाई रहता है. मई 2008 में उसने मुर्शिदाबाद की एक अदालत में धारा 498 ए, 406 और 125 के तहत मुक़दमा दर्ज़ करा दिया. अब वह केस उठाने की एवज में देवाशीष से आठ लाख रुपये की मांग कर रही है.

कोलकाता के बालीगंज इलाक़े की रूपा (छद्म नाम) के विवाह से पहले कई लड़कों से अवैध संबंध थे. इसी इलाक़े के मनीष के साथ उसकी शादी हो गई, पर शादी के बाद भी वह उन युवकों के संपर्क में रही. जब पति ने आपत्ति की तो उसने दहेज के लिए सताने का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज़ करा दिया. अब मनीष अदालत के चक्कर लगा रहा है और रूपा सारे गहने लेकर मायके में है. उसने एक ब्वॉयफ्रेंड के साथ लिव -इन- रिलेशनशिप को गले लगा लिया है. टालीगंज के नेताजी नगर निवासी सुदीप साहा की कहानी भी कुछ इसी तरह है. 1990 में उनका विवाह हुआ, पर कुछ माह बाद ही पत्नी सुजाता ने प्रेमी की मदद से प्रदीप पर अत्याचार शुरू कर दिया. जनवरी 1995 में दोनों के बीच तलाक हो गया, मगर स्थानीय क्लब और प्रेमी की मदद से सुजाता ने प्रदीप के फ्लैट पर क़ब्ज़ा कर लिया है. बेचारा पीड़ित पति दर-दर भटक रहा है. उत्तर 24 परगना के वनगांव निवासी सुशील कुमार दास वहां के ग्रामीण बैंक में काम करते हैं. 13 जून 1995 को शादी हुई. कुछ सालों बाद से ही पत्नी मां-बाप से अलग रहने के लिए दबाव डालने लगी. सुशील नहीं माना तो वह अपनी बच्ची को लेकर मायके चली गई. जुलाई 2001 में उसने बरासात सीजीएम अदालत में पति पर उत्पीड़न एवं भरण-पोषण का मामला दायर कर दिया. स्थानीय महिला समिति के हस्तक्षेप से सुशील गिरफ़्तारी से तो बच गया, पर अदालत के चक्कर लगाते-लगाते आख़िरकार 2007 में उसे भरण-पोषण का ख़र्च देने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब पत्नी का केस ख़त्म कर राजी-ख़ुशी तलाक लेने के लिए पांच लाख रुपये मांग रही है.

संभवत: इस तरह के मामलों ने ही देश के कई शहरों में पतियों को एकजुट होकर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया है. कोलकाता के अलावा दिल्ली, बेंगलुरू, सूरत और हैदराबाद जैसे शहरों में पुरुषों के हक़ के लिए लड़ने वाली संस्थाएं बनी हैं. भारत के पुरुष प्रधान समाज के मिथक के मद्देनज़र यह सब भले ही हास्यास्पद और अतिरंजित लगे, पर अबलाओं को सबला बनाने के लिए जो क़ानूनी हथियार दिए गए हैं, उनका कुछ महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, इस बात में कोई शक़ नहीं है. कोलकाता की पीड़ित पुरुष पति परिषद का जन्म भी पत्नी के हाथों पति के उत्पीड़न के कारण हुआ. महानगर के राधिका नाथ मलिक की शादी 1985 में हुई थी. उग्र स्वभाव की पत्नी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अनाप-सनाप पैसे मांगती थी. राधिका नाथ में सारी मांगें पूरी कर सकने में असमर्थ थे. घर में कलह ने बसेरा बनाया. 10 वर्षों तक घुटन की ज़िंदगी से ऊबकर राधिका नाथ ने 1995 में तलाक ले लिया. पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का लाभ उठाते हुए उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया. हालात ने उन्हें उनकी तरह दु:खी पतियों के आंसू पोंछने और कुछ करने के लिए प्रेरित किया. गृह कलह की हद से गुज़रने से पहले ही अगस्त 1992 में ही उन्होंने पति परिषद का गठन किया. आज परिषद के सक्रिय सदस्यों की संख्या 1400 के आसपास हो गई है. इसमें 40 महिलाएं भी हैं, जो संस्था के उद्देश्य से पूरी तरह सहमत हैं. परिषद की उपाध्यक्ष एडवोकेट अरुणा मुखर्जी मानती हैं कि महिलाओं का एक वर्ग भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 व 34 का उपयोग पुरुषों को सताने के लिए कर रहा है. नारी स्वाधिकार व अदालतेर डायरी (नारी के अधिकार और अदालत की डायरी) जैसी चर्चित बांग्ला पुस्तकों की लेखिका ने इन धाराओं की ख़ामियों को दूर करने की वकालत की है. परिषद पहले पति-पत्नी के बीच आई दरार पाटने का प्रयास करती है. विवाह टूटने की हालत में पतियों को क़ानूनी मदद उपलब्ध कराती है और कभी-कभी महिला संगठनों की तरह सभा एवं प्रदर्शन भी करती है. आज तक जो मामले परिषद के पास आए हैं, उनमें से 60 प्रतिशत घरों में फिर से बहार आई है. जबकि 40 प्रतिशत मामलों में तलाक दिलवाने में संस्था कामयाब हुई है. परिषद के संचालक एवं अवैतनिक महासचिव राधिका नाथ बताते हैं, हमारी संस्था नारी विरोधी या कट्टर पुरुषवादी नहीं है. इसे एक मानवतावादी संगठन कहना चाहिए.

पुरुषवादियों की प्रमुख मांगें

- धारा 498-ए में से ग़ैर-ज़मानती प्रावधान हटाया जाए.
- किसी भी क्षेत्र में लिंग भेद न हो.
- बस, ट्रॉम और ट्रेन आदि सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ख़त्म हो.
- पत्नियों के भरण-पोषण की बाध्यता तुरंत ख़त्म की जाए.
- महिलाओं को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 498(बी) जोड़ी जाए.
- पत्नियों की तरह पतियों को भी श्वसुर कर संपत्ति में हिस्सा मिले.
- विधवा भत्ता और पेंशन देना बंद किया जाए. मृत पिता के नाबालिग पुत्रों या पुत्रियों को भी ऐसी सुविधा दी जाए.
- पत्नी यदि तलाक का मुक़दमा करती है तो उसे पति को आर्थिक सहायता देनी होगी.
- पति की नौकरी पाने वाली विधवा अगर दोबारा शादी करती है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी.
- तलाक के बाद फिर से विवाह करने वाली पत्नी को पूर्व पति से हासिल संपत्ति लौटानी होगी.
- हर ज़िले में परिवार अदालतों का गठन हो.
- अगर पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हों तो किसी एक को ही मकान भत्ता दिया जाए.

पीड़ित पुरुषों का विरोध.

परिषद के कई मामलों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी निपटारा किया है. यह राष्ट्रीय महिला आयोग के भी संपर्क में रहती है. क़ानून ने किस तरह महिलाओं को पुरुषों को सताने का अधिकार दे दिया है, इसकी मिसाल देते हुए राधिका नाथ ने बताया कि पत्नी मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाकर पति को गिरफ़्तार करा सकती है. इस मामले में पुलिस कोई सबूत नहीं मांगती. पति की शारीरिक अक्षमता के कारण मां बनने में असमर्थ पत्नी तलाक पा सकती है, पर पत्नी की शारीरिक ख़ामी के कारण पिता बनने में असमर्थ पति इस आधार पर तलाक नहीं पा सकता. परिषद क़ानून के इस प्रावधान से क्षुब्ध है कि कोई भी स्त्री अगर पराए पुरुष के साथ व्याभिचार करती पकड़ी जाती है तो पुरुष ही दंड का भागी होगा, स्त्री नहीं. तलाक की स्थिति में पत्नी अपने बेरोज़गार पति से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है, वसूल सकती है. धारा 375 के मुताबिक़, नारी की अनुमति लिए बिना या उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ सहवास करना बलात्कार माना जाएगा. पति परिषद पूछती है कि बिस्तर पर नारी ने सहवास की अनुमति दी थी या नहीं, इसे कैसे प्रमाणित किया जाएगा?

परिषद ही नहीं, देश के कई संगठन भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए में संशोधन की मांग कर रहे हैं. इसके मुताबिक़, विवाह के सात साल के अंदर कोई वधू आत्महत्या करती है या शारीरिक-मानसिक पीड़ा का शिकार होती है तो उसकी ससुराल के लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और 90 दिनों तक उनकी ज़मानत नहीं होगी. परिषद की मांग है कि अगर वधू के हत्यारों को दंडित करने के लिए यह धारा बनी है तो वर हत्या के लिए भी 498-बी बनाई जानी चाहिए. संस्था कहती है कि महिला के साथ बलात्कार के दोषियों को सजा देने के लिए धारा 375 बन सकती है तो पुरुषों के साथ बलात्कार के लिए कोई क़ानूनी प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? कम से कम 498-ए को ज़मानत योग्य अपराध करार देने की पुरजोर मांग हो रही है. परिषद महिला संगठनों से खार खाई दिखती है. पति परिषद के एक पर्चे में लिखा है, नारीवादी देह व्यापार में लगी महिलाओं को वेश्या, गणिका या पतिता नहीं कहना चाहते. वे उन्हें सेक्स वर्कर या यौनकर्मी कह रहे हैं. वे श्रमिक का हक़ देने व ट्रेड यूनियन बनाने की मांग कर रही हैं. एक दिन सुना जाएगा कि रेड लाइट क्षेत्र सेक्स इंडस्ट्रियल कांप्लेक्स हो गए हैं. फिर इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग होगी. दलाल एक्ज़िक्यूटिव होंगे, वेश्याओं की मौसियां अध्यक्ष-चेयरमैन होंगी. फिर पेंशन, प्रोविडेंट फंड और बोनस न देने पर हड़ताल का आह्वान होगा.

पीड़ित पतियों के लिए काम कर रही सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और घरेलू हिंसा क़ानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इनमें संशोधन की मांग कर रही है. संस्था का दावा है कि विवाहित पुरुषों की आत्महत्याओं का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व पत्नियों का मौखिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक अत्याचार है. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रो. नागराज के एक अध्ययन में कहा गया है कि हर साल 22 से 23 हज़ार पुरुष पत्नियों के अत्याचार के कारण ख़ुदकुशी करते हैं. संस्था का दावा है कि 2005 में दायर किए गए 58,200 मुक़दमों में से 80 प्रतिशत झूठे थे. संस्था की मांग है कि क़ानून को लिंग निरपेक्ष किया जाए, क्योंकि कई मामलों में पत्नियां ही पुरुषों पर अत्याचार करती हैं. फाउंडेशन पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग कर रहा है. उसका मानना है कि भारतीय पुरुष कर से हासिल होने वाली आय का 82 प्रतिशत हिस्सा देते हैं, पर एक भी ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां वे अपनी आवाज़ उठा सकें. संगठन की वेबसाइट पर मौजूद एक लेख के मुताबिक़, सरकार महिला कल्याण के लिए हर साल 75 अरब रुपये ख़र्च करती है, इसलिए पुरुष कल्याण मंत्रालय भी बनना चाहिए, क्योंकि हर साल 56 हज़ार पुरुष वैवाहिक कारणों से आत्महत्याएं कर रहे हैं. संस्था का दावा है कि दहेज की मांग के चलते हर साल केवल 7000 महिलाओं की मौत होती है. संस्था घरेलू हिंसा क़ानून को आतंकवादी गतिविधि करार देती है.

मुंबई के चाइल्ड राइट एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र के डीजीपी एस एस विर्क से एक अनोखी गुहार की. पत्नी पीड़ित ये पति अपने बच्चों की कस्टडी चाहते थे. इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे बच्चों के अपहरण के लिए मजबूर होंगे. प्रशांत सावंत, विलास आदिक, दीपक देवरुकर और मनीष कटीरा ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर चार माह पहले ही अपना संगठन बनाया है. उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. संगठन के एक सदस्य पुरुषोत्तम महाजन पर उनकी पत्नी ने दहेज के लिए सताने का मुक़दमा दायर किया है. इसे ग़लत बताने के लिए महाजन ने एक आवाज़ रहित वीडियो यू-ट्यूब पर जारी किया है, जिसमें पत्नी उनकी पिटाई कर रही है. महाजन फ़िल्मकार सुभाष घई के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके हैं. उन्होंने यह वीडियो पुलिस को भी दिखाया, पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा. इस ग़ैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष संदीप केडिया के मुताबिक़, सारे सबूत होने के बावजूद क़ानून लागू करने वाली एजेंसियां हमेशा औरतों का पक्ष लेती हैं. संगठन के एक अन्य सदस्य के मुताबिक़, हर शनिवार वे बांद्रा कोर्ट के पास एक बैठक आयोजित करते हैं. इन्हें हर सप्ताह बच्चों की कस्टडी हासिल करने से संबंधित 50 कॉल्स आती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... चोरी की गंभीरता?! ...धीर

सबसे ख़ास बात यह कि वह पानी जो खमरिया और इसके पड़ोसी गांवों का पालन पोषण करता है, काला हो रहा है. यह पानी पीने, नहाने और सिंचाई के लायक़ बिल्कुल ही नहीं रह गया है.

केलो नदी को बचाने की ज़रूरत

कांची कोहली

खमरिया गांव भारत के बाक़ी गांवों से कम भाग्यशाली नहीं है. इसकी साफ़–सुथरी गलियां, सलीके से बनाए गए मिट्टी के घर यह बताते हैं कि दूसरे ग्रामीण इलाक़ों की समृद्धि किस तरह हो सकती है. केलो नदी इसी गांव से होकर गुज़रती है. यही नदी इन इलाक़ों की कृषि के लिए सिंचाई का साधन है. गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने का साधन भी आसान है. बिजली आदि सभी सुविधाएं होने के कारण शिक़ायत की कोई वजह नहीं हो सकती है. लेकिन, यदि कोई इस गांव के आवासीय इलाक़ों से होकर गुज़रता है तो उसके मन में इसकी ग़लत छवि क्यों उभर आती है? सबसे ख़ास बात यह कि वह पानी जो खमरिया और इसके पड़ोसी गांवों का पालन पोषण करता है, काला हो रहा है. यह पानी पीने, नहाने और सिंचाई के लायक़ बिल्कुल ही नहीं रह गया है.

खमरिया के पास केलो नदी की जलधारा कोयला खान मालिकों और मोनेट इस्पात एवं ऊर्जा लिमिटेड द्वारा नियंत्रित होती है. यदि कोई चिड़िया उड़कर आए तो कोयले की खान से खमरिया गांव की दूरी तीन किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी. जबकि घुमावदार सड़क से गांव और कोयला खान के बीच की दूरी पांच किलोमीटर पड़ती है. नदी में खदानों के पानी उत्सर्जन का स्रोत भी है. यह बात मुझे गांव के ही एक आदमी ने बताई. 5 दिसंबर 2009 को मैं वहां पहुंची. केलो नदी में कोयले के अपशिष्टों के प्रवाहित होने के किस्सों को सुनकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई. उस ग्रामीण ने बताया कि दरअसल आज आप नदी की जो गंदगी देख रही हैं, वह एक सप्ताह पहले नदी में बहाए गए खदानों के अपशिष्टों का नतीजा है. केलो नदी खमरिया और उसके आसपास के ग्रामीणों के लिए महज़ जीविका का स्रोत नहीं है, बल्कि यह पूरे रायगढ़ ज़िले को पीने का पानी मुहैया कराती है. साथ ही यह महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है. यह नदी रायगढ़ शहर के पास भी प्रदूषण का दंश झेलती है, क्योंकि वहां उद्योग काफ़ी हैं.

हम खमरिया गांव रमेश अग्रवाल और राजेश त्रिपाठी के साथ पहुंचे. ये दोनों सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता हैं. पिछले चार–पांच सालों से प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रमों के ख़िलाफ़ ये लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. पर्यावरण को बर्बाद करने वालों के ख़िलाफ़ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है. ये उस पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व क़ायम है. रायगढ़ ज़िले में उद्योगों की वजह से जिस तरह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, खमरिया गांव उसकी दूसरी कड़ी है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के मीलापुरा एवं कोंडकेल गांवों में मोनेट इस्पात को कोयला खनन के लिए साल 2000 में ही अनुमति मिल गई थी. इस कंपनी को यह अनुमति 1994 के पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के तहत मिली थी. इसके ज़रिए यह कंपनी हर साल 860.416 हेक्टेयर इलाक़े में 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष खनन कर सकती थी. पर्यावरण विभाग से जब इसे अनुमति मिली थी तो खुदाई का यह क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत था. यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था.

सभी फोटो– कांची कोहली

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जिन 17 आम और 10 ख़ास शर्तों के साथ खुदाई के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अहमियत है? यह बेहद दिलचस्प है कि इनमें से किसी भी शर्त में यह ज़िक्र नहीं किया गया कि गंदा और खदान से निकला पानी कहीं और प्रवाहित किया जाएगा. जबकि लीज पर दी गई जगहों पर ही यह सारा कुछ होना चाहिए. इसीलिए हमने अपनी यात्रा कोंडकेल से शुरू की, ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि जो गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है, वह खदानों से ही निकल रहा है, क्योंकि खमरिया ग्रामवासी इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे. हम उस जगह का पता लगाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे. इस दौरान एक अज्ञात साईकिल सवार ने रुककर हमसे बात की. हमारी मंशा जानकर उसने हमें उन जल स्रोतों के बारे में बताया, जिनकी हमें तलाश थी. ये जल स्रोत वाक़ई कोयले की खदानों से निकलने वाले काले पानी से भरे थे. हमने देखा कि कोंडकेल की खदान के बिल्कुल बगल में एक नाला बह रहा था. इस नाले के बहने की दिशा जंगलों की तरफ़ थी, जो वन विभाग के लिए अनजान नहीं है. खदान के पास एक जंग लगा पानी का पाइप था. यह सड़क से होकर जंगलों की तरफ़ जाता था. दरअसल इस पाइप को खदान से काले पानी की निकासी के लिए सड़क से लगाया गया था. जब पानी जंगलों के आसपास या अपनी दिशा बदल कर खेती योग्य भूमि की ओर रुख़ कर लेता है तो उसके असर को समझा जा सकता है. इसने हमें वहां रुकने पर विवश किया, ताकि हम उसकी फोटो ले सकें और उसकी असलियत को देख सकें.

इस पूरे क्षेत्र में जीपीएस का उपयोग किया गया था. जैसा मैंने आपको बताया, केलो नदी खमरिया से होकर गुज़रती है. और, हम 22.09,30.8 अक्षांश और 83.30,28.3 देशांतर रेखा के पास मौजूद थे. कोयले के पानी ने मोनेट के कोंडकेल संयंत्र के पास जो नाला बनाया था, वह 22.10, 32.0 अक्षांश और 83.21,30.8 देशांतर के पास स्थित था. यानी दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे. लेकिन यही पूरी हक़ीक़त नहीं थी. हमें इस बात को सुनिश्चित करना था कि क्या वाक़ई यह नाला केलो नदीं में मिलता है. हम उस नाले के प्रवाह की दिशा में चलते रहे, तो हमें पता चला कि डोमा नाला केलो नदी में खमरिया और दूसरे गांवों के पास जाकर मिलता है. यह हमारे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे भी अधिक कोयले की खदानों वाला पानी यहां 22.10, 33.5 अक्षांश और 83.31, 20.2 देशांतर के पास मिलता था.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस पानी में विषैले पदार्थों की मात्रा कितनी होगी? वहीं ध्यान रखने वाली बात है कि इसी पानी का इस्तेमाल गांव वाले अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए करते हैं. क्या वे इस बात से वाक़िफ़ हैं कि इसका इस्तेमाल उनके लिए सुरक्षित नहीं है? भला कोई इस बात का पता कैसे लगा सकता है कि उनके जंगलों के आसपास जो पानी बह रहा है, वह खदानों से निकलने वाला विषैला पानी है? रायगढ़ ज़िले के लिए इसका समाधान निकालना चुनौती भरा काम है, क्योंकि उद्योगपति धनबल और तरक़्क़ी के एजेंडों के ज़रिए विनाश का यह सारा खेल खेलते हैं. लेकिन, हमें इन तथ्यों को वैज्ञानिक तौर पर स्वीकार करने की आवश्यकता है. और, ईमानदारी से सहयोग करने की ज़रूरत है. यह सिर्फ़ खमरिया गांव की कहानी नहीं है, बल्कि दूसरे गांवों जैसे लमदरहा, गरे, कोसंपाली, कोंडकेल, कुंजेमुरा और तमंर आदि की भी यही राम कहानी है. उपर्युक्त बातें हमें जनचेतना संस्था के सदस्य डॉ. हरिहर पटेल ने बताईं. डॉ. पटेल पेशे से चिकित्सक हैं और उन्होंने इन इलाक़ों में लोगों के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट की ओर सभी का ध्यान खींचा है. इस समस्या की वजह मोनेट खदान से प्रवाहित होने वाला अपशिष्ट जल है. इन उदाहरणों से सीख लेकर और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही उन्होंने उद्योगपतियों, मसलन जिंदल समूह पर दबाव बनाने का साहस किया है. क्योंकि, इस समूह ने भी गरे गांव में खदान का काम शुरू करने का फ़ैसला लिया है. लेकिन, डॉ. पटेल इस इलाक़े के बहुत बड़े भू–भाग के मालिक हैं और कंपनी उसे ख़रीदना चाहती है. बड़े भू–भाग पर स्वामित्व के कारण ही उनमें यह इच्छाशक्ति जगी है.

इन इलाक़ों की वैज्ञानिक जांच–पड़ताल और कार्रवाई अभी बाक़ी है. ऐसे में खमरिया गांव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर भी मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि केलो नदी में और कितना प्रदूषित पानी पचाने की क्षमता है. लेकिन, पानी के बहाव का चित्र हमें झकझोरता है. यह नदी ख़ुद को स्वार्थी लोगों के चंगुल से बचाने के लिए कार्रवाई की मांग कर रही है.

(लेखिका ग़ैर सरकारी संस्था कल्पवृक्ष से जुड़ी हैं)

feedback@chauthiduniya.com

गंगा के दिन कब बहुरेंगे?

सुरेंद्र अग्निहोत्री

पिछले दिनों एक ख़बर आई कि पोलैंड के एक नवयुवक मैटीज लेसजेक टर्स्की की गंगाजल पीने से मौत हो गई. यह ख़बर निश्चित तौर पर उन लाखों–करोड़ों लोगों को आघात पहुंचाने वाली थी, जो अभी भी गंगा तेरा पानी अमृत की मान्यता के पक्षधर हैं. लेकिन सच वाकई इसके विपरीत है. कभी जीवनदायिनी रही गंगा का पानी आज इतना विषैला हो गया है कि उसे पीना तो दूर, छूना भी ख़तरे से ख़ाली नहीं है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बनारस के अस्सीघाट पर बीते दो वर्षों में प्रदूषण का पैमाना कहलाने वाले बीओडी का स्तर कभी भी तीन मिग्रा प्रति लीटर से कम नहीं रहा. बनारस हो या इलाहाबाद, बीते एक कुंभकाल यानी बारह वर्षों में पानी का स्तर साफ़ डी श्रेणी से ऊपर नहीं उठ पाया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के तहत डी श्रेणी का पानी केवल जानवरों के लिए मुफ़ीद है. गौमुख से बंगाल की खाड़ी तक इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि धन–धान्य से परिपूर्ण करने वाली गंगा का जल विषैला हो गया है. गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के तहत अब तक नौ सौ करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. अकेले इलाहाबाद के लिए 60 सौ करोड़ रुपये आवंटित हुए. ट्रीटमेंट प्लांट सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हो गए, किंतु गंगा का जलस्तर निरंतर गिरता गया. गंगा एक्शन प्लान के तहत आई करोड़ों की रक़म लूटने के लिए सरकारी–सामाजिक संगठन जुट गए. गंगा कार्य योजना माल काटो योजना के रूप में पहचानी जाने लगी. संसदीय लोक लेखा समिति भी यह गंभीर टिप्पणी करके लौटी कि कार्य योजना के बाद गंगा और प्रदूषित हुई, पानी तेजाब बन गया. नदी का फेटा सिकुड़ता गया और सफ़ेद पानी लाल होकर कालिमा की हद तक पहुंच गया. आचमन को कौन कहे, गंगाजल नहाने लायक़ भी नहीं रहा.

पूरे विश्व में गंगा एक ऐसी नदी है, जिसका स्वच्छ जल किसी भी हालत में सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है. गंगाजल पीकर जीवनयापन करने वाले को हर वे पोषक तत्व स्वत: मिल जाते थे, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी हैं. गंगा को बचाने के लिए यूं तो अनेक प्रयास हुए, पर कोई प्रयास निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सका. योग गुरु रामदेव के नेतृत्व में गंगा मुक्ति के लिए महासंग्राम छिड़ने वाला है. माला और भाला के साथ गंगा के अविरल प्रवाह और पवित्रता को बचाने हेतु संघर्ष करने के लिए इस आंदोलन के कर्ताधर्ता तैयार हैं. संयोजक के एन गोविंदाचार्य ने गंगा मुक्ति अभियान हेतु हरिद्वार में जुटे संतों से कहा कि एक ही समय में आंखों से दो लक्ष्य भेदने की नीति से हम बचें, अन्यथा अभियान अपनी विश्वसनीयता खो देगा. आंदोलनकारी मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस–वे पर रोक हेतु निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है. आर–पार की इस लड़ाई में सरकार से टकराव होना तय है. संतों द्वारा छेड़े जाने वाले इस आंदोलन के साथ खड़े होने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी तैयार दिख रहे हैं. गंगा एक्सप्रेस–वे का पहले से विरोध कर रही सपा के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है. उधर गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता जा रहा है. ग्रीन पीस फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि यही हाल रहा तो अगले 25 वर्षों में गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.

हिंदू धर्म ग्रंथ शिवपुराण के अनुसार, राजा भगीरथ ने अपने 60 हज़ार पुरखों के उद्धार हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उसे भगवान शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया था. गोमुख (उद्गम) से देवप्रयाग (अलकनंदा भागीरथी का संगम) तक इसे भागीरथी कहा जाता है. गंगा की जलधारा हिंदू धर्म में लोकपूजित है. गंगा 2540 किलोमीटर तक सफर करने के बाद

फोटो– प्रभात पाण्डेय

बंगाल की खाड़ी में गिरती है. गंगा जल प्रवाह तंत्र का क्षेत्रफल 9,57,600 वर्ग किलोमीटर है.

वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू कराया था. तबसे अब तक अरबों रुपये पानी में बहा दिए गए. पिछले अर्द्धकुंभ में संगम पर गंगा का पानी लाल हो गया तो टीकरमाफी के महंत स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी ने जनहित याचिका दाख़िल कर दी थी. न्यायालय की पहल पर नरोरा से पानी छोड़ा गया तो मेला स्नान संपन्न हो सका. कबीरमठ के महंत गुरुवचन दास ने भी जनहित याचिका दाख़िल की तो कानपुर की 36 टेनरियां बंद कर दी गईं. इलाहाबाद में भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाने लगा. फिर भी स्थिति बदतर होती चली गई. गंगा एक्शन प्लान से जुड़े वैज्ञानिक एम सी सक्सेना कहते हैं कि बुलंदशहर, कन्नौज, कानपुर, डलमऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर एवं कोलकाता आदि के गंदे नालों एवं कल–कारखानों का कचरा और गंदा पानी गंगा में छोड़ा जाना प्रदूषण का प्रमुख कारण है. गजरौला चीनी उद्योग, रायबरेली थर्मल पावर, कानपुर का चमड़ा उद्योग एवं अन्य कारखानों का प्रदूषित पानी ही गंगाजल को विषाक्त बना रहा है. गंगा सेवा आश्रम इलाहाबाद के संत अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि गंगा को समय रहते प्रदूषण मुक्त न किया गया तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ़ नहीं करेंगी.

गंगा नदी में पहले बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 62 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो 2005 में घटकर 27 मिलीग्राम प्रति लीटर रह गई. पानी में कम से कम बीओडी होना जलजीवों के लिए जीवनदायी होता है. इसीलिए नदी के पानी में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है. 1986 में यह 722 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 773 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई है. बढ़ती संवेदनहीनता के चलते गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग में भी जल संकट खड़ा हो गया है. फतेहपुर से लेकर एटा के बीच लगातार जलस्तर घट रहा है. सागर विश्वविद्यालय में मत्स्य वैज्ञानिक डॉ. आशीष पटेरिया कहते हैं कि नदियों को मैला करने वालों के प्रति कड़े क़ानून होने के बावजूद सरकार ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. 1974 में बने प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम क़ानून की धारा 41 में जल प्रदूषित करने वालों को कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक छह साल की क़ैद एवं जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन आज तक इस क़ानून के तहत किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है.

गंगा एक्सप्रेस हाइवे के नाम पर गंगा के किनारों को बेच रही उत्तर प्रदेश सरकार पर अब लगाम कसने की तैयारी की जा रही है. उत्तर प्रदेश का पर्यावरण विभाग गंगा का जीआईएस डाटा बेस तैयार करने की कवायद में लग गया है. कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक गंगाजल की गुणवत्ता और नदी को प्रदूषित करने वाले स्रोतों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विभाग ने हाई रिज़ोल्यूशन सेटेलाइट डाटा एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. इस आशय का प्रस्ताव रिमोट सेसिंग एप्लिकेशन सेंटर से तैयार कराया गया है. प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए पर्यावरण विभाग ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद प्रदेश में गंगा के नाम पर पैसों का अंबार लगने वाला है. गंगा महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम स्वरूप पाठक कहते हैं कि गंगा के किनारे बसे गांवों के लोग गंगा की रक्षा की लड़ाई में आगे आएं. कृषि भूमि बचाव मोर्चा के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार गंगा को बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं. जे पी यादव ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें पशुपालन से जुड़े लोगों को बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण से पशुओं के चरने योग्य भूमि समाप्त हो जाएगी. बिना चारे के पशुओं को ज़िंदा रखना संभव न हो पाएगा. जीपी समूह द्वारा बलिया से नोएडा तक की गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना भले ही न्यायालय की पहल के कारण गति नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन इस परियोजना के चलते आने वाले दिनों में गंगा के अस्तित्व पर गंभीर संकट हो सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

गंगा एक्शन प्लान

शहर	राज्य–शहर	अनुमानित खर्च (लाखों में)
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	3272.36
आरा	बिहार	255.20
बद्रेश्वर–चापदानी	पश्चिम बंगाल	3378.84
बैद्यबाटी	पश्चिम बंगाल	1291.11
बांसबेरिया	पश्चिम बंगाल	2680.69
बइहिया	बिहार	41.26
बाढ़	बिहार	68.69
बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	2395.18
भागलपुर	बिहार	516.77
बजबज	पश्चिम बंगाल	985.37
बक्सर	बिहारी	76.14
छपरा	बिहार	167.62
सर्कुलर–कनाल	पश्चिम बंगाल	901.82
फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	51.02
फतुहा	बिहार	66.56
गढ़मुक्तेश्वर	उत्तर प्रदेश	103.90
गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	771.78
हरिद्वार–ऋषिकेश	उत्तराखंड	648.00
कानपुर	उत्तर प्रदेश	8573.88
मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	369.60
मुगलसराय	उत्तर प्रदेश	409.02
मुंगेर	बिहार	116.38
पटना	बिहार	1163.57
रिषड़ा	पश्चिम बंगाल	1191.24
साहबगंज	झारखंड	47.50
सैदपुर	उत्तर प्रदेश	61.62
सुलतानगंज	बिहार	93.81
टाली नाला	पश्चिम बंगाल	3545.36
वाराणसी	उत्तर प्रदेश	45.05.97
सीईटीपी	कोलकाता	6500.00
अन्य		1816.00
कुल		46,116.16

उक्त अनुमान 2000 तक के हैं.

स्रोत–कैबिनेट कमेटी

मुद्दा केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही ही एक महत्वपूर्ण मसला है. मसलन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो और किस तरह उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए?

सरकार को भ्रष्टाचार के सभी रास्तों यानी मिलावट, कम नापतौल, नक़ली दवाओं सहित दूसरी चीज़ों की बिक्री पर लगाम लगाना चाहिए.

अगर पाकिस्तानी भारत की सीमा पर आ जाएं तो क्या होगा ?

एम जे अकबर

लाहौर में मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं. वह एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और इन दिनों आम लोगों के अधिकारों और पाकिस्तान के क़ानूनी ढांचे की अखंडता के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने मुझसे एक बेहद चौंकाने वाला सवाल पूछा. उस सवाल ने मुझे कुछ समय तक उलझाए रखा. ज़रा सोचिए, यदि लाखों पाकिस्तानी बाघा सीमा पर पहुंच जाएं और वे भारत में तालिबान एवं उसके वैचारिक योद्धाओं से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करने लगें तो ऐसी हालत में भारत क्या करेगा? यही मेरे पाकिस्तानी मित्र का सवाल था.

यह संभावना कल्पनाओं से परे है. ठीक उसी तरह, जैसे कोई विश्लेषक कॉलेज में कॉफ़ी पीने के दौरान कई सुझाव देता है. 1969 से लेकर दो साल बाद तक पूर्वी पाकिस्तान से आए 30 लाख शरणार्थियों ने कलकत्ता की गलियों और बीच शहर में पनाह ली. इस समस्या ने दो मुल्कों को युद्ध के लिए मजबूर किया और जिससे बांग्लादेश आज़ाद हुआ. अपने जन्म के 25 साल के भीतर ही पाकिस्तान ने अपनी आधी आबादी का विश्वास खो दिया था. उसके अगले चार दशक के भीतर जो बाक़ी आधे रह गए हैं, वे भी ख़ौफ़ के साये में जी रहे हैं. उनका यह भय किसी और से नहीं, बल्कि मौजूदा पाकिस्तान की आधी आबादी से है. 1971 की घटना को सिर्फ़ पाकिस्तान से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. चंद सेकेंड के लिए ही, पर उसका असर भारत पर भी तो पड़ा होगा. इस घटना का रिसाव पश्चिम यानी अफ़ग़ानिस्तान की ओर नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे एक बार फिर पूरब और पश्चिम का टकराव पैदा हो जाता. सीमांत पश्चिम से पूरब आने में अवरोध पैदा होता है और पूरब के लोग शरण के लिए हमेशा पूरब की ओर ही रुख़ करते हैं.

मेरे मित्र के उस सवाल पर भारत और ख़ासतौर पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित तौर पर, कई मायनों में पाकिस्तानियों के आगमन पर उसके अस्थिर नतीजों से लोगों को हैरानी, परेशानी और चिंता होगी. लेकिन कुछ मायनों में, देर-सबेर यह जनसमूह एक व्यापक भावनात्मक लगाव के तहत एक होगा. और, तब तो इसे सरकारी नीतियों के तहत लाया जा सकता है. क्या यह सहानुभूति या सनक होगी? जब बच्चे, जवान और महिलाएं भारत में हमदर्दी की तलाश करेंगे तो क्या हमारा मानव हृदय उनके दिलों को जीत पाएगा. अथवा, यह कहते हुए हम उनका उपहास करेंगे कि आपने 1947 में अपने लिए एक अलग बिछावन तैयार किया था तो अब आप उसके कांटों पर सोइए.

इस संदर्भ में पंजाब की आवाज़ निर्णायक हो सकती है. मेरा मानना है कि सभी नहीं तो अधिकांश पंजाबी अपने दिल से और शायद आंखों में आंसुओं के साथ यही कहेंगे कि उन्हें कांटों की सेज पर सोने के लिए न छोड़ा जाए. क्या यह बात भावनाओं में बहकर की जा रही है? शायद, लेकिन बग़ैर भावनाओं के ज़िंदगी बड़ी निष्ठुर हो जाएगी. 1971 में पश्चिम बंगाल में किसी ने शरणार्थियों का मजहब नहीं पूछा. उनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन यह ज़्यादा अहम बात नहीं थी. जो सबसे अहम बात थी, वह यह कि वे तीस लाख भयभीत और भूखे बंगाली लोग थे.

लेकिन उस दरम्यान वक़्त और जगह दोनों में महत्वपूर्ण अंतर था. पूर्वी पाकिस्तान से भारत को कभी भी भय का एहसास नहीं हुआ. शुरुआती वर्षों में कराची के राष्ट्रवादियों ने बंगाली मुसलमानों पर काफ़ी दबाव बनाया कि वह बांग्ला उर्दू वर्णमाला के मुताबिक़ लिखें. लेकिन लाख दबाव के बाद भी बंगाली मुसलमानों ने अपनी भाषा और लिपि को अलविदा नहीं बोला. (जैसा कि उदाहरण के तौर पर कमाल अतातुर्क ने तुर्क को अरबी लिपि में छोड़कर रोमन में शुरू कराया) इस पर लोगों की इतनी गंभीर और सख्त प्रतिक्रिया सामने आई कि इस विचार को भुला ही दिया गया. बंगाल में दंगे हुए. यह पंजाब के दंगों की तरह व्यापक नहीं तो ख़तरनाक ज़रूर थे. लेकिन संबंधों को बरकरार रखा गया. एक तरफ़ दंगा था तो दूसरी तरफ़ बंगाली हिंदुओं के प्रति भेदभाव, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं का अस्तित्व मिटा नहीं. जैसा कि पाकिस्तानी पंजाब और सिंध में हिंदुओं के साथ हुआ. बंगालियों के ख़िलाफ़ पश्चिमी पाकिस्तान का ज़ुल्म सभी हदों को पार कर गया. उनका यह ज़ुल्म भारतीय दमन के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के गुस्से से कहीं अधिक बर्बर था. और, इसे सिर्फ़ नस्लवाद के तौर पर ही परिभाषित किया जा सकता है.

वक्त अपना चक्र ख़ुद बनाता है. 1971 में भारतीय 1965 की आग में झुलस रहे थे. जंग एक त्रासदी है, लेकिन मानवीय इतिहास का यह एक अभिन्न अंग रहा है. पूरे इतिहास में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि वह कभी तनाव या जंग के साये से नहीं गुज़रा. पिछले चार दशक का सबसे कटु अनुभव आतंकवाद रहा है. आतंकवाद एक शातिर, छली और घृणित बुराई है और यह बुराई किसी मासूम और दुश्मन में भेद करना नहीं जानती है. ख़ुदा न करे, यदि बाघा के प्रवेश द्वार पर ऐसी फ़रियाद सुनाई दे तो कितने लोग उनकी आंखों में आतंकवाद के ख़ौफ़ को याद रखना चाहेंगे? जंग से निश्चित तौर पर भारत में शरणार्थियों की तादाद बढ़ेगी. यह मुमकिन है कि मानव पलायन के दु:ख में पांचवां स्तंभ ख़ुद एक छलावा साबित होगा. जब आवाम ने सीमाओं को अप्रासंगिक बना दिया है तो भला सेना, राज्य और ग़ैर राज्य, वर्दीधारी या ग़ैर वर्दीधारियों को पानी में खींची गई सीमा का सम्मान क्यों करना चाहिए? इस जंग में कौन कहां होगा? जिस तरह पाकिस्तान विचारधाराओं में बंटा है, क्या पाकिस्तानी सेना भी उसी तरह बांटी जाएगी? क्या आधे पाकिस्तानी भारतीय सेना के साथ मुक़ाबला करेंगे? अधिक सरल विचार अकल्पनीय विचारों का पीछा करते हैं.

आज़ादी के बाद नए देश में आ रहे शरणार्थियों के दु:खों को पाकिस्तान ने बाघा सीमा की अपनी ओर की दीवार पर चित्रित किया है. यह आपदा एकतरफ़ा नहीं थी. उस समय लाखों व्यथित लोग पाकिस्तान से भारत भी आए. लेकिन, भारत ने उस पल को पत्थरों पर दर्ज़ नहीं किया. यह सभी को याद दिलाना है कि वह गृहयुद्ध का क्रूर जंग क्षेत्र था. शायद लाहौरवासी, चाहे वे जहां भी हैं, बाघा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले इस छवि को मिटाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

न्यायिक जवाबदेही : न्यायधीशों की नियुक्ति और बर्ख़ास्तगी

रवि किशोर

न्यायमूर्ति दिनाकरन का मामला एक ऐसा मसला है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति दिनाकरन को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के निर्णय से हुई. जैसा कि सभी को मालूम है, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने उनकी प्रोन्नति का विरोध किया. और, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं क़ानून मंत्री तक ने आपत्ति व्यक्त की. वरिष्ठ अधिवक्तागण और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि इस मसले को लेकर मुख्य न्यायाधीश एवं क़ानून मंत्री के पास भी गए. उन्हें आपत्ति इस बात को लेकर थी कि जस्टिस दिनाकरन ने तथाकथित तौर पर काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है. और, यह खनन संबंधी मामलों को धारवाड़ सर्किट बेंच से बेंगलुरू स्थानांतरित करने के बारे में संशय को बढ़ाता है. दिनाकरन की प्रोन्नति संबंधी फाइल पुनर्विचार हेतु वापस कॉलेजियम के पास भेजने के लिए सरकार को बाध्य किया गया.

बहरहाल, अब पूरा मामला एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है और दिनाकरन को सर्वोच्च न्यायालय में प्रोन्नत करने का मामला पूरी तरह से गौण हो चुका है. कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई. राज्यसभा के 75 सांसदों, जो कि भारतीय जनता पार्टी, वामदलों, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कषगम और जनता दल युनाइटेड से ताल्लुक़ रखते हैं, ने उनके ख़िलाफ़ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया. यह प्रस्ताव कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनाकरन के ख़िलाफ़ तीन माह तक चले अभियान का नतीजा है. सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीश दिनाकरन का मनोनयन किया गया था. इस निर्णय की बड़ी तीखी आलोचना हुई थी. तथाकथित तौर पर, जस्टिस दिनाकरन पर भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे. वास्तविक मुद्दा सिर्फ़ दिनाकरन की पदोन्नति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है. उच्च न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति और न्यायिक ज़िम्मेवारी का मुद्दा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है, उसमें कई सालों से समुचित बदलाव विचाराधीन है. लेकिन विवाद उसके बाद भी है. यहां तक कि संविधान सभा में भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सदस्यों के विचार अलग-अलग थे. संविधान सभा में भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. उसमें यह भी नहीं बताया गया कि संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए किसे अधिकृत किया जाएगा. वक़ालत के पेशे में होना ही न्यायाधीश बनने की पर्याप्त योग्यता नहीं है. भारी मुवक्किलों वाला वकील होना भी इसके लिए सही मापदंड नहीं है. इसके लिए संविधान की मूल भावना को समझना ज़रूरी है. अपने न्याय, निर्णय और व्याख्यात्मक कौशल के इस्तेमाल से समाज में संविधान सम्मत बदलाव लाने की प्रतिबद्धता ज़रूरी है.

मुद्दा केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही ही एक महत्वपूर्ण मसला है. मसलन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो और किस तरह उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए? यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि इन दोनों सवालों के जवाब उच्च न्यायिक व्यवस्था के चरित्र का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. आमलोगों को अदालत के बारे में कम ही जानकारी है. मौलिक अधिकार के रूप में मताधिकार को जानने के बाद ही हम जनप्रतिनिधियों और चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में जान पाते हैं. इस पारदर्शिता ने हमारे लोकतंत्र को व्यापक बनाया है. जहां तक न्यायपालिका की बात है तो निचले स्तर से लेकर जिला न्यायाधीश के स्तर तक आम जनता न्यायाधीशों के बारे में न्यायपालिका में उनके काम से ही जान पाती है. यदि हम न्यायालयों में जज़ों की नियुक्ति की वरिष्ठता को देखें तो उनकी नियुक्ति, अधिकार और गतिविधियों को लेकर रहस्य हमेशा बना रहा है. अभी भी मुसीबत के पलों में कोई भी मसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है. चाहे मसला आंतरिक हो या बाह्य, ये ही उस पर तर्क-वितर्क करते हैं. इसके अलावा जब कार्यपालिका बुनियादी आज़ादी को ख़तरे में डालती है, तब भी मुद्दा न्यायपालिका के पास ही जाता है. ऐसी स्थितियों के दौरान हमें यह बताया गया है कि न्यायतंत्र लोकतांत्रिक शासन का सूचकांक है. यही बात हमारे संविधान में भी कही गई है.

हमें आज़ादी मिली और उस वक़्त हमें एक ऐसे प्रशासन के ज़िम्मे छोड़ दिया गया, जो औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित था. और, जो न्यायिक व्यवस्था थी, वह ख़ासतौर पर ऐसे क़ानूनों से लैस थी, जिसका मक़सद औपनिवेशिक सत्ता की रक्षा करना और उसके ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी विरोध और विद्रोह को कुचलना था. उच्च और उच्चतम न्यायालय की संरचना इस विरासत के प्रमाण हैं. 26 जनवरी 1950 को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लागू होने के बाद भी कुछ नहीं बदला. बदलाव के लिए किसी व्यवस्था को सूत्रधार नहीं बनाया गया. लेकिन, न्यायपालिका के संदर्भ में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया. हालांकि हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया. इसके पीछे मक़सद यह था कि विधायिका मनमाने ढंग से क़ानून का निर्माण न करे. सरकार के कामकाज के तरीक़े पर लगाम कसने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना ज़रूरी समझा गया. इसका स्वरूप इस तरह का रखा गया कि संविधान के अंतर्गत नागरिक अधिकारों की जो गारंटी दी गई है, उसकी रक्षा की जा सके.

सेवानिवृत्त हो रहे प्रत्येक न्यायाधीश न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं, लेकिन अपने पूरे सेवाकाल में इसके लिए वे कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि व्यवस्था को कैसे पाक-साफ़ रखा जाए, इस बारे में वे सुझाव तक नहीं देते हैं. उच्च न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए ज़रूरी बौद्धिक क्षमता और दृढ़ता कहीं दिखाई नहीं देती. बहस में यह बात कहीं भी नहीं आती है कि वकील में न्यायाधीश बनने के लिए किन गुणों और क्षमताओं का होना ज़रूरी है. न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालय के हों या सर्वोच्च न्यायालय के, निस्संदेह एक संवैधानिक नियुक्ति है. इस पद में असीम शक्ति है, जिसका इस्तेमाल होता है. उन्हें और शक्तिशाली बनाने से विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं. वर्षों तक न्यायाधीशों के कामकाज की दबे स्वरों में आलोचना के बाद नई दिल्ली में 18-19 सितंबर, 1992 को मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहले से चलन में रहे और विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्य नियम, दिशानिर्देश और सिद्धांतों को अपनाने की बात कही गई. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मूल्यों की पुनर्बहाली का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की थी. इसका मक़सद न्यायाधीशों के व्यवहार के लिए एक दिशा निर्देश जारी करना था, बात चाहे उनकी निजी अथवा कार्यालयी ज़िंदगी की हो. मसौदा तैयार होकर स्वीकृति के लिए आया और स्वीकृत भी हो गया. ये प्रावधान उच्च नैतिकता और नैतिक मानदंडों की रक्षा करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अपनाए जाने की ज़रूरत है. बहरहाल, आज तक यह नैतिक लफ्फाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और सिर्फ़ काग़ज़ों तक ही सिमटी है.

आप सुप्रीम कोर्ट को वैटिकन की तरह और मुख्य न्यायाधीश को पोप जैसा मान सकते हैं. ये वही शख़्स हैं, जो संस्था की गरिमा और स्वतंत्रता को बहाल कर सकते हैं. और, इस लिहाज से वह न्यायिक योग्यता के लिए ज़रूरी व्यक्तियों के गुण-अवगुण आदि का आकलन कर सकते हैं और अपना मंतव्य ज़ाहिर कर सकते हैं. किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार को उनकी राय पर सवाल खड़ा करने या उनकी अनुशंसाओं की सूक्ष्मता से जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसी कोई भी कोशिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दख़ल देने जैसी होगी. इस तर्क का आधार यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सारे तथ्यों से वाक़िफ़ होते हैं. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सही प्रत्याशी कौन हैं, इस बात का सही आकलन न्यायपालिका ही कर सकती है. ऐसी तमाम कोशिशों का मक़सद राजनीतिक दख़ल की संभावना को ख़त्म करना है, क्योंकि यह दख़ल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दहलीज पर ही गंदा कर देता है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

देश-समाज का हित सर्वोपरि

चौथी दुनिया अख़बार मुझे पहली बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. बहुत अच्छा लगा. इसमें प्रकाशित आलेख-विचार दीगर समाचारपत्रों से अलग हैं. देश और समाज के हितों को ध्यान में रखकर लिखे जाने वाले विचार हमेशा सराहनीय होते हैं.

गुलाब चंद्र कटारिया, *श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

बधाई

कुंभ की जानकारी बहुत अच्छी है. पहले हम यही जानते थे कि कुंभ एक मेला होता है, लेकिन सीरीज पढ़ने के बाद लगता है कि कुंभ के बारे में जितना भी जाना-समझा जाए, वह कम है. इस ज्ञानवर्द्धक सीरीज के प्रकाशन के लिए लेखक एवं अख़बार दोनों ही बधाई के पात्र हैं.

राजेश्वर सिंह, *जयपुर, राजस्थान.*

सीआईए-मोसाद की करतूत

आवरण कथा-सीआईए और मोसाद की हिंदुस्तान पर बुरी नज़र काफ़ी खोजपरक-सारगर्भित है. उक्त विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसियां हमारे देश को बर्बाद करना चाहती हैं, यह हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है. हमारे सुरक्षातंत्र और देश के जिम्मेदार लोगों को इस दिशा में प्रभावी क़दम उठाने चाहिए.

राधिका रमण, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

झारखंड का दुर्भाग्य

यह जानकर दु:ख होता है कि हर बार अख़बारों और अन्य संचार माध्यमों द्वारा सावधान किए जाने के बावजूद जनता अपराधियों को विधानसभाओं में भेज रही है. अपराधियों का कोई धर्म-ईमान नहीं होता. झारखंड का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसे सही खेवनहार नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए जनता भी किसी हद तक ज़िम्मेदार है.

संजय कुमार, *बेगूसराय, बिहार.*

वन्यजीवों की तस्करी

तस्करों के निशाने पर बेज़ुबान-रिपोर्ट यह बताती है कि व्यवस्था के नाकारापन से वन्यजीवों के अस्तित्व पर बन आई है. तस्करों के हौसले बुलंद हैं. लेकिन, शासन-प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है. अब तो ज़रूरत इस बात की है कि जनसामान्य ही कोई ठोस पहल करे, तभी हम इन बेज़ुबानों को बचा सकेंगे.

रश्मि अग्रवाल, *कीर्ति नगर, नई दिल्ली.*

सज़ा में कोताही

चौथी दुनिया के 11 जनवरी के अंक में प्रकाशित आलेख रुचिका प्रकरण: अपराधी को नाममात्र की सज़ा पढ़ा. लेखक ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बेबाकी से अपने विचार रखे हैं. वास्तव में न्याय मिलने में शिथिलता अथवा अपराध के मुक़ाबले कम सज़ा मिलना ही वह कारण है, जो न्यायिक व्यवस्था के प्रति जनसामान्य के विश्वास को कमज़ोर कर रहा है. सिर्फ़ रुचिका का ही मामला अकेला नहीं है. ऐसे कई मामले सुनने में आ चुके हैं, जिनमें फ़रियादी की पूरी उम्र गुज़र जाती है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिल पाता. कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए?

सुनीता श्रीवास्तव, *देहरादून, उत्तराखंड.*

कला बाज़ार और मुन्नी मोबाइल

11 जनवरी के अंक में साहित्य दुनिया पृष्ठ पर करोड़ों का कला बाज़ार लेख रोचक है. मुन्नी मोबाइल सीरीज़ भी अच्छी है. साहित्यिक कहानियां भी शामिल करें तो अच्छा रहेगा.

सुषमा सक्सेना, *लाइनपार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.*

मॉल संस्कृति का विस्तार

कांची कोहली का आलेख-मॉल यानी आधुनिक युग की नई इमारतें मौज़ूदा समय का आईना है. हमारी जरूरतें और उनके सापेक्ष हमारे संसाधनों का स्वरूप कितना बदलता जा रहा है, यही इस लेख का सार है. हम अपने सरलतम कल को भूलते हुए नई-नई व्यवस्थाओं में उलझते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि इन सबसे माहौल दमघोंटू होता जा रहा है. यही नहीं, हम समाज से भी लगभग कटते जा रहे हैं.

आर के रत्नाकर, *रायपुर, छत्तीसगढ़.*

सफलता की कामना

सबसे पहले अपनी धारदार पत्रकारिता के लिए साधुवाद स्वीकार करें. भविष्य में भी इस पैनेपन की आशा है. हम सब आपके साथ हैं. बस, आप संघर्ष करते रहिए. हम चौथी दुनिया की सफलता की कामना करते हैं.

अरशद जमाल, *बेलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.*

सावधानी बहुत ज़रूरी

4-10 जनवरी के अंक की संपादकीय ठोस है. राष्ट्रीय समस्याओं पर राजनीति घातक है. समस्याएं हल होने के लिए ही आती हैं. सावधानी ही समस्याओं को जन्म नहीं देती. असावधानी और लचर नीति राष्ट्रघाती है.

प्रदीप सिंह राठौर, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

सामंती संस्कृति घातक

चौथी दुनिया के 4-10 जनवरी के अंक में प्रकाशित आलेख-महिला सरपंचों पर अत्याचार अच्छा लगा. वंशवाद, परिवारवाद, छुआछूत, दहेज प्रथा, दलित उत्पीड़न एवं अंतरजातीय-अंतरधर्मीय विवाहों का विरोध सामंती संस्कृति के विभिन्न रूप हैं. इस संस्कृति के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है.

सतीश गोपाल गुरहा, *कानूनगोयान, बरेली, उत्तर प्रदेश.*

साईं की महिमा

साईं की महिमा पृष्ठ शुरू करने के लिए बधाई. पृष्ठ पर काफ़ी शिक्षाप्रद सामग्री होती है. ख़ासतौर पर साक्षात्कार नवीन और पठनीय होता है. आशा है कि अगले अंकों में भी ऐसे ही लेख और साक्षात्कार पढ़ने को मिलेंगे.

अनूप गंगवार, *कायमगंज, फर्रुख़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

ज्योति बसु का जाना

संतोष भारतीय

मुकेश के यादगार गीत *जाने कहां गए वे दिन*.......को ज़रा तोड़ दें, तो एक अहम सवाल बनता है, कहां गए वे लोग? ज्योति बसु अब हमारे बीच नहीं हैं. ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं हैं. ये सभी देश के महज़ राजनायक नहीं थे, बल्कि इस देश की जनता के महानायक रहे. आज़ाद भारत की ये हस्तियां अपने चरम पर पहुंचीं. आम आदमी की आवाज़ और उसका भरोसा बनीं. ज्योति बसु के जाने से आम आदमी की आवाज़ और भरोसे को एक गहरा आघात हुआ है. यह आघात गहरा इसलिए है कि ज्योति दा माटी के उन लालों की फ़ेहरिस्त के आख़िरी चिराग़ थे, जो आम आदमी की आवाज़ और भरोसे के महानायक थे. धीरे-धीरे इन महानायकों का साथ छूट रहा है और अब देश में राजनायकों की फ़ेहरिस्त में ऐसी हस्ती नहीं दिखती, जो आम आदमी का महानायक बनने का माद्दा रखती हो.

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति बसु का 95 साल की उम्र में निधन हो गया. पूरा देश शोकसंतप्त है. इसलिए नहीं कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री या फिर किसी राजनीतिक दल के पूर्व नेता का निधन हुआ है, बल्कि इसलिए कि उनके बीच एक ऐसी हस्ती नहीं रही, जिसने राजनीति और विचारधारा के परे जाकर देश की जनता की सेवा की है. आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया है. उनका भरोसा जीता है. वे एक ऐसी हस्ती थे, जिसके पास लोग बेहिचक जाते थे और अपनी बात रखते थे. लोग इस विश्वास के साथ वापस आते थे कि ज्योति बसु उनकी बात समझ गए हैं और उनके हितों की रक्षा की जाएगी. ज्योति दा पर ऐसा विश्वास देश की समूची जनता रखती थी. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और वी पी सिंह भी भारतीय लोकतंत्र के ऐसे महानायक रहे, जिन्होंने आम आदमी के ऐसे विश्वास को जीता था. इसी लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना भी है. अब ऐसे महानायक जनता के बीच नहीं हैं, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी के. पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी महानायकों की आख़िरी कड़ी हैं.

1914-2010

ज्योति बसु सरीखे नेता अब इस लोकतंत्र में पैदा नहीं हो रहे. हमारे इर्द-गिर्द ऐसी हस्ती नहीं बची, जिसे जनता से जुड़े होने का गौरव मिला हो. एक भी ऐसा नेता देखने को नहीं मिलता, जिसे आम आदमी की आवाज़ का रखवाला कहा जा सके. ऐसा कोई नहीं, जिस पर देश की जनता विश्वास कर सके. 8 जुलाई 1914 को पूर्वी बंगाल के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्में ज्योति बसु ने कोलकाता के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की. वकालत करने के लिए लंदन का रुख़ किया. 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ली. आज़ादी के बाद रेलवे कर्मचारियों के साथ आंदोलन में कूदे ज्योति बसु पहली बार राजनीतिक चर्चा में आए और 1957 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए. अगले बीस साल तक ज्योति बसु ने प्रदेश की राजनीति को इस क़दर प्रभावित किया कि 1977 में पहली बार वामदलों को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला और खुद उन्हें मुख्यमंत्री का पद. इस पद के मिलने के बाद ज्योति बसु बंगाल की राजनीति में ख़ुद राजनीति के पर्यायवाची बन गए. 23 साल तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर बैठकर उन्होंने भारतीय राजनीति का इतिहास लिख दिया. बतौर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का जो काम ज्योति बसु ने किया, वह देश के किसी दूसरे राज्य में सोचा भी नहीं जा सकता था. देश में लोकतंत्र की गाथा ज्योति बसु के बिना लिखी नहीं जा सकती है.

इसे लोकतंत्र की विडंबना नहीं तो और क्या कहा जा सकता है. 1996 के लोकसभा चुनाव के पहले देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ज्योति बसु देश के प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं. ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा था कि वामदल पूरे देश में लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती दावेदारी के चलते जहां राष्ट्रीय पार्टियां नकारी जा रही थीं, देश अस्थिरता के माहौल में था, ऐसे में जो नाम पूरे देश में गूंज रहा था, वह ज्योति बसु का था. यह बंगाल के इस राजनायक पर देश की जनता का विश्वास नहीं तो और क्या है कि वह समूचे देश का महानायक बना.

1996 में आम चुनाव के नतीजों के बाद वामदलों ने सत्ता में साझेदारी से मना कर दिया और सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया. इस फ़ैसले ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और ख़ुद ज्योति बसु के शब्दों में यह वामदल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई. बहरहाल, बग़ैर प्रधानमंत्री बने भी ज्योति बसु ने देश की जनता का विश्वास जीता और आख़िरी दम तक उस विश्वास को क़ायम रखा. आज उनकी कमी इस लोकतंत्र को महसूस हो रही है. हमारे मौज़ूदा राजनायक भी इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि महानायक बनने के लिए उन्हें आम आदमी की आवाज़ बनने के साथ-साथ उनके विश्वास पर भी क़ायम रहना होगा. अफ़सोस इसी बात का है कि देश की जनता ऐसे नेताओं की कमी महसूस कर रही है, जो उनके हितों की रक्षा कर सकें.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

जनता महंगाई की मार से बेहाल

डी आर आहूजा

दिल्ली में गृहणियां आसमान छूती महंगाई के बोझ तले दबती जा रही हैं. रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की बढ़ती क़ीमत ने उन्हें सबसे अधिक परेशान किया है. किराने के सामान, दाल, फल, सब्ज़ियों, पॉल्ट्री, मछलियों, दूध और दूसरे खाद्य पदार्थों की बढ़ती क़ीमतों ने उन पर सबसे अधिक असर डाला है. यहां तक कि उनका मासिक बजट भी बिगड़ गया है. इस बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें अपनी रसोई में कटौती करनी पड़ रही है. इस महंगाई से यदि कोई सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग. दरअसल बढ़ती क़ीमतों की वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएं उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस साल खाद्य पदार्थों की क़ीमत में लगभग 50 से 100 फ़ीसदी तक इज़ाफ़ा हुआ है.

इसमें कोई शक़ नहीं कि कृषि वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई है. यह कमी सूखा और ग्लोबल वार्मिंग के चलते आई है. लेकिन, क़ीमतों में मौजूदा वृद्धि के लिए थोक और ख़ुदरा विक्रेता ज़्यादा कसूरवार हैं. वे भोले-भाले उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं. फ़सलों की पैदावार करने वाले ग़रीब किसान रह जाते हैं और सारा मुनाफ़ा व्यापारियों के हिस्से में चला जाता है. यहां तक कि किसान अपना मूल ख़र्च यानी बीज, सिंचाई और रसायनों की क़ीमत तक नहीं निकाल पाते हैं. उनके हिस्से अगर कुछ आता है तो बस कठिन परिश्रम. इस वर्ष आलू की क़ीमत दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है. भिंडी और करेला 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं. फलों के दाम जैसे सेब आदि ने 80-100 रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छू लिया है. संतरा समेत खट्टे फल 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं. दाल को ग़रीबों का प्रोटीन कहा जाता है और इसका मूल्य भी पिछले साल की अपेक्षा 60 से 80 फ़ीसदी तक बढ़ा है. रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों के बढ़ती क़ीमत ने भारत के लाखों ग़रीबों की चिंता बढ़ा दी है. पॉल्ट्री, मछली और अंडे तो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गए हैं.

उन परिवारों की हालत तो और भी ख़राब हो रही है, जहां सिर्फ़ एक सदस्य कमाने वाला है और उसका वेतन भी पांच-सात हज़ार रुपये महीना है. अगर यह दो-तीन सदस्यीय परिवार किराए के घर में रहता हो तो फिर उसकी दिक्कतों का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ऐसे परिवारों के लोग किस तरह अपना जीवनयापन कर रहे हैं, इस तरफ़ सरकार का कोई ध्यान नहीं है. घर का एक बच्चा अगर स्कूल जाता है और वह भी किसी छोटी कक्षा में, तब भी उस पर पांच-सात सौ रुपये महीने का ख़र्च आ जाता है. लेकिन सरकार को फ़ुर्सत ही नहीं है कि वह ऐसे लोगों की तरफ़ एक नज़र देख भी ले.

सरकारी दुकानों, मदर डेयरी आदि जगहों पर सब्ज़ियां बड़ी कंपनियों द्वारा खोले गए रिटेल की अपेक्षा 10 फ़ीसदी सस्ती मिल रही हैं. हालांकि इन सरकारी दुकानों और बूथों पर सब्ज़ियों एवं फलों की गुणवत्ता बड़ी कंपनियों की खुदरा दुकानों की तुलना में अच्छी नहीं है.

मंत्री, सांसद, विधायक और अफसर मज़े कर रहे हैं, आम ग़रीब जनता को रोटी के लाले हैं. तुर्रा यह कि प्रजातंत्र है!

सरकारी दुकानों, मदर डेयरी आदि जगहों पर सब्ज़ियां बड़ी कंपनियों द्वारा खोले गए रिटेल की अपेक्षा 10 फ़ीसदी सस्ती मिल रही हैं. हालांकि इन सरकारी दुकानों और बूथों पर सब्ज़ियों एवं फलों की गुणवत्ता बड़ी कंपनियों की खुदरा दुकानों की तुलना में अच्छी नहीं है. मदर डेयरी की दुकानों पर आलू मिट्टी से ढका होता है. इसके अलावा दूसरे फल एवं सब्ज़ियां जो यहां मिलती हैं, वे या तो सड़ी होती हैं या उनकी गुणवत्ता इतनी घटिया होती है कि उन्हें जानवर भी नहीं खा सकते. इस बीच सरकार बढ़ती क़ीमतों को रोकने के लिए व्यापारियों के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने के बजाय न सिर्फ़ चुपचाप बैठी है, बल्कि उसने दूध, पानी और बिजली की क़ीमत भी बढ़ा दी है. अब तो मेट्रो से सफ़र करना भी महंगा हो गया है. उपभोक्ता यह गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को महंगाई रोकने के लिए कुछ कड़े क़दम उठाने चाहिए. लेकिन जब सरकार ख़ुद ज़रूरी सामानों की क़ीमत बढ़ा रही है तो वह व्यापारियों से क़ीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कैसे कह सकती है?

सरकार को भ्रष्टाचार के सभी रास्तों यानी मिलावट, कम नापतौल, नक़ली दवाओं सहित दूसरी चीज़ों की बिक्री पर लगाम लगाना चाहिए. सरकार लगातार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही है. यहां तक कि मंत्रियों, जजों, विधानसभा सदस्यों और सांसदों का वेतन भी बढ़ा है. लेकिन आम आदमी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है. ख़ासकर उस आम आदमी के बारे में, जो निजी फर्म और असंगठित क्षेत्रों में काम करता है. दवा विक्रेता अपनी मर्ज़ी से दवाइयों की क़ीमतें बढ़ा रहे हैं. यही नहीं, बाज़ार में नक़ली दवाइयां खुलेआम बेचकर मरीज़ों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. निजी अस्पतालों में इलाज़ कराना आम आदमी के बूते की बात नहीं रह गई है. सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें लगी होती हैं और मरीज़ों को बेड के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है.

कुछ साल पहले सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें उसने वस्तुओं के साथ डब्बे के वजन पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन, बिना किसी भय के इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. मिठाई की क़ीमत दोगुनी करने वाले हलवाई इसके लिए मुख्य रूप से दोषी हैं. भारतीय मिठाइयों को बनाने में खोया का इस्तेमाल ख़ास तौर पर किया जाता है, पर इसमें भी यूरिया समेत कई ज़हरीले रसायनों को मिलाया जा रहा है. यहां तक कि पेय पदार्थों में भी रसायन मिलाए जा रहे हैं. ये रसायन ज़हरीले होते हैं और इन वजहों से सैकड़ों लोगों को हर साल अपनी जान गंवानी पड़ती है. ये सभी अवैध कारोबार बिना किसी डर के खुलेआम हो रहे हैं और सरकार चुपचाप सारा तमाशा देख रही है. दरअसल आज उपभोक्ता क्रांति वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि तमाम अवैध कारोबार और मिलावट के धंधे को ख़त्म किया जा सके . उपभोक्ताओं को बढ़ती क़ीमत और अवैध व्यापार के ख़िलाफ़ एकजुट होने की ज़रूरत है. उन्हें सामाजिक तौर पर अवैध व्यापारियों, मुनाफ़ाखोरों और मिलावट करने वालों का बहिष्कार करना चाहिए.

कई साल पहले जब बढ़ती क़ीमतों की ऐसी ही स्थितियां आईं थीं तो उपभोक्ता एकजुट हुए थे. बढ़ती महंगाई का मुक़ाबला करने में महिलाएं सबसे आगे थीं. कुछ कॉलोनियों में महिलाओं ने फल एवं सब्ज़ियां थोक दरों पर बेचने के लिए स्टॉल भी लगाए थे. ग्रेटर कैलाश के एन ब्लॉक बाज़ार में महिलाओं ने ऐसा ही स्टॉल लगाया था. इन महिलाओं में बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल थीं और उन्होंने सब्ज़ी मंडी से फल एवं सब्ज़ियां ख़रीद कर लोगों को बेची थीं. आज ऐसे क़दम उठाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि उपभोक्ताओं के हित और अधिकारों की रक्षा हो सके.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

(लेखक द ट्रिब्यून के ब्यूरो प्रमुख रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

स्वीडन रहने के लिहाज़ से विश्व का सबसे महंगा शहर है. भारत साउथ एशिया में भूटान, मालदीव और श्रीलंका के बाद चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार उसने लंबी छलांग लगाई है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

केजीबी का काला सच

सोवियत संघ का ख़ुफ़िया आतंक

सोवियत पायलट ओसिपोविक, जिसने यात्री विमान को निशाना बनाया (बाएं) और अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य लॉरेंस मैक्डोनल्ड (दाएं)

दुनिया की नज़रों में भले ही वे 269 यात्री बेकसूर थे, लेकिन केजीबी ने उन्हें दुश्मन मान लिया था. कोरियाई विमान पर सीमा लांघने का आरोप लग गया और नतीजा यह हुआ कि सारे लोग काल के गाल में समा गए. यह केजीबी के काले कारतूतों की बेहद ही ख़ौफ़नाक दास्तां थी.

तारीख़ एक सितंबर 1983. इस दिन कोरियन एयरलाइंस के बोइंग 747 विमान ने न्यूयॉर्क से सियोल के लिए उड़ान भरी. इसने अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 246 यात्रियों एवं 23 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी. यात्रियों में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य लॉरेंस मैक्डोनल्ड भी थे. उड़ान भरने के कुछ समय बाद यह विमान रास्ता भटक गया. पायलट को अपनी ग़लती का अंदाज़ा हो गया था. नतीजतन उसने विमान की गति कम कर दी. यह विमान ज्यों ही तयशुदा रास्ते से थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे हवाई इलाक़े में दाख़िल हुआ, इसके क़रीब एक इंटरसेप्टर यानी हवा में ही विमान को मार गिराने वाला लड़ाकू विमान मंडराने लगा. अब दोनों विमान एक आइलैंड के ऊपर हवा से बातें कर रहे थे. लेकिन, उस आइलैंड का हवाई क्षेत्र बेहद संकरा था. इससे दोनों विमानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. एक तरह से कहा जाए तो इन दोनों के बीच शह और मात का खेल चल रहा था. बोइंग इंटरसेप्टर की पहुंच से बाहर होने ही वाला था, तभी इंटरसेप्टर को कंट्रोल रूम से एक संदेश मिला. बोइंग को नेस्तनाबूद करने का संदेश.

और, उसने ऐसा ही किया. लेकिन कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल. इंटरसेप्टर का पायलट पहले ही 243 राउंड गोलियां इस कोशिश में बर्बाद कर चुका था. पायलट के मुताबिक़, यह उसकी ज़िंदगी का बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था. कई राउंड गोलियां चलाने के बाद भी वह बोइंग का बाल बांका नहीं कर पा रहा था. फिर पायलट ने एक तरक़ीब निकाली. वह अपने इंटरसेप्टर को बोइंग के ठीक ऊपर उड़ाने लगा. इस तरह कि संकरे हवाई इलाक़े से उसे बचने का कोई मौक़ा न मिल सके. यानी बोइंग का पायलट विमान को नीचे ले जाने के लिए मजबूर हो गया. इसका सिर्फ़ एक ही अंजाम हो सकता था. उस संकरे हवाई क्षेत्र से विमान का लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर जाना. यही हुआ भी. विमान पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई. बोइंग के नीचे गिरने के बाद इंटरसेप्टर ने उस पर एक के बाद एक मिसाइलें दागना शुरू कर दिया. पायलट के मुताबिक़, उसने विमान वैध तरीक़े से मार गिराया. यानी उसने विमान के परखच्चे उड़ा दिए. विमान में सवार सभी 246 यात्री मौत की नींद सो गए. यही नहीं, 23 क्रू मेंबर्स में भी कोई नहीं बच सका. यानी विमान के साथ-साथ कुल 269 लोगों का वजूद हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया. यह पूरा हादसा बस एक ग़लती का नतीजा था. वह ग़लती थी कोरियाई विमान का रास्ता भटक जाना.

हालांकि इस विमान हादसे को लेकर कई सस्पेंस पैदा किए गए. किसी के लिए यह बात बेहद अटपटी लग सकती है कि आख़िर रास्ता भटकने की क़ीमत 269 लोगों की जान नहीं हो सकती है. वह भी तब, जबकि उस विमान में अमेरिकी कांग्रेस का प्रभावशाली सदस्य सवार हो. यदि आप ऐसा सोचते हैं कि विमान के इस तरह नेस्तनाबूद होने के पीछे इतनी छोटी वजह नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. यह कोई विमान हादसा नहीं था और न ही किसी ग़लती का नतीजा. इसकी हक़ीक़त तो कुछ और ही थी. हम आपको बताते हैं कि आख़िर उस विमान के साथ हुआ क्या था?

बात अस्सी और नब्बे के दशक की है. उन दिनों शीतयुद्ध अपने पूरे उफान पर था. दुनिया की दो बड़ी शक्तियां एक-दूसरे को पटखनी देने की हर कोशिश में लगी थीं. इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन तरीक़े को अपनाया. इसी का नतीजा था कोरियन एयरलाइंस के विमान का हवा में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना. जैसा हमने आपको बताया कि यह हादसा एक सितंबर 1983 को हुआ. शुरुआत में सोवियत संघ इस बात से मुकरता रहा कि इस विमान को उसके अंजाम तक पहुंचाने में उसका कोई हाथ है, लेकिन बाद में उसने यह बात स्वीकार कर ली कि यह उसका ही कारनामा था. केजीबी के मुताबिक़, यह यात्रियों से भरा कोई विमान नहीं, बल्कि जासूसी मिशन पर निकला अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए का विमान था. और, यह सोवियत संघ के हवाई इलाक़े में अहम जानकारियां जुटाने के मक़सद से मंडरा रहा था. सोवियत संघ के मुताबिक़, इस विमान के ज़रिए अमेरिका उसकी सैनिक ताक़तों की असलियत का अंदाज़ा लगाना चाहता था. लेकिन, इस मिशन से किसी ख़तरनाक मंसूबे की बू आ रही थी. दरअसल, शीतयुद्ध के दौर में अमेरिका ने यूरोप में सोवियत संघ को निशाना बनाकर अपनी मिसाइल तैनात की थी. यह बात सोवियत संघ को नागवार लगी. नतीजतन, उसने अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने के लिए इस मिशन को अंजाम दिया. सोवियत संघ के इस मिशन के लिए उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी ने पूरे जाल को बिछाया.

मेजर गेन्नाडी ओसिपोविक. यही नाम था उस इंटरसेप्टर सु-15 के पायलट का, जिसने बोइंग 747 को नेस्तनाबूद किया था. इस पायलट ने 1991 में यानी इस वारदात के ठीक आठ साल बाद अपने इंटरव्यू में इस मिशन की पूरी दास्तां बताई. उसने बताया कि सोवियत अधिकारियों को यह बात पूरी तरह मालूम थी कि यह कोई जासूसी विमान नहीं, बल्कि नागरिक विमान है. इसके बावजूद उन्होंने इसे ख़त्म करने का आदेश दिया. मेजर ओसिपोविक ने बताया कि इंटरसेप्टर से उस विमान को गिराने से पहले मैंने अच्छी तरह देखा कि वह एक बोइंग 747 विमान था. मुझे यह भी पता था कि यह एक नागरिक विमान है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कुछ भी लेना-देना नहीं था. उस विमान ने सोवियत हवाई इलाक़े में दाख़िल होते समय पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई थी. उसका ख़ामियाज़ा तो उसे भुगतना ही था. पायलट के मुताबिक़, मुझसे न किसी ने पूछा और न ही मैंने बताया कि यह एक नागरिक विमान है. यानी उस नागरिक विमान को जानबूझ कर मार गिराया गया.

यह सारा खेल केजीबी की रणनीतियों का नतीजा था. इस शातिर एजेंसी ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए सोवियत अधिकारियों को गुमराह किया, जिसकी क़ीमत 269 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी. यह बेहद जुदा, लेकिन बेहद ख़ौफ़नाक तरीक़ा था केजीबी का. वह भी अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने का.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

बेहतर देशों की सूची में भारत का 88वां स्थान

क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2010 के अनुसार, विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छे देशों की सूची में भारत 88वें पायदान पर है. भारत ने यह स्थान 35 पायदानों की छलांग लगाकर हासिल किया है. सर्वे के मुताबिक़, भारत ने रूस और चीन जैसे देशों को इस सूची में पछाड़ दिया है. एशिया महाद्वीप के लिए जारी सूची में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर भूटान है. यह सूची ट्रैवल मैग्जीन इंटरनेशनल लिविंग ने जारी की है. इस सूची में फ्रांस पहले पायदान पर है. ग़ौरतलब है कि फ्रांस लगातार पांच साल से पहले स्थान पर काबिज है. उसके बाद आस्ट्रेलिया, स्विट्रजरलैंड और जर्मनी का नंबर आता है. वहीं इस सूची में अमेरिका चौथा स्थान खोकर सातवें स्थान पर पहुंच गया. इंडेक्स के मुताबिक़, स्वीडन रहने के लिहाज़ से विश्व का सबसे महंगा शहर है. 2009 में जारी सूची में भारत साउथ एशिया में भूटान, मालदीव और श्रीलंका के बाद चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत ने लंबी छलांग लगाई है.

ग़ौरतलब है कि यह इंडेक्स लगातार 30वें वर्ष सफलतापूर्वक प्रकाशित किया गया है. इसमें 194 देशों को शामिल किया गया. सूची जारी करने से पहले इसे नौ वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे जीवन जीने का स्तर, संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, वातावरण, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, संरचना, सुरक्षा व जोखिम और जलवायु. भारत ने न सिर्फ़ इस सूची में अपना बेहतर सुधार किया है, बल्कि उसने कॉस्ट ऑफ लिविंग कैटेगरी में 25 प्वाइंट भी अर्जित किए हैं. गत वर्ष की तुलना में भारत ने इस बार 40 के मुक़ाबले 65 प्वाइंट हासिल किए.

आंखें बताती हैं, पुरुष क्या चाहता है

पुरुष की आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है. उसकी आंखों से मालूम पड़ जाता है कि वह दीर्घकालीन या अल्पकालीन संबंध बनाना चहता है. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का. अगर पुरुष किसी महिला से लंबे समय तक आंख मिलाता है तो वह लंबी अवधि तक साथ निभाने वाले हमसफर के बारे में सोचता है. लेकिन, जब उसकी नज़रें बराबर किसी महिला के चेहरे और शरीर को निहारती हैं तो उस वक़्त उसके दिमाग़ में कोई दूसरी बातें घूमती हैं. मतलब यह कि वह अल्प समय के लिए रिश्ता बनाना चाहता है.

यह शोध टोक्यो यूनिवर्सिटी के डॉ. टॉम क्यूरी द्वारा किया गया. शोध के दौरान उन्होंने पाया कि चेहरा शरीर से कहीं अधिक महत्व रखता है, तब जबकि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी की तलाश में रहता है. लिटिल ऑफ स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉ. एंथोनी ने कहा कि जब आप दीर्घकालीन संबंध के बारे में सोचते हैं, तब आप दोस्ताना, विनोदी, सहकारी और सुखद हमसफर के बारे में सोचते हैं. ग़ौरतलब है कि उक्त सारी जानकारियां हम चेहरे से प्राप्त करते हैं. लेकिन जब यही बातें पुरुषों और कम अवधि के रिश्ते के लिए लागू होती हैं तो पुरुषों को इस बात की तनिक चिंता नहीं रहती है कि किसी का चेहरा कितना सुंदर है. शरीर उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता है.

ग़ौरतलब है कि यह निष्कर्ष 260 लोगों पर किए गए शोध के ज़रिए सामने आया है. शोध के दौरान पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से विभाजित किया गया था.

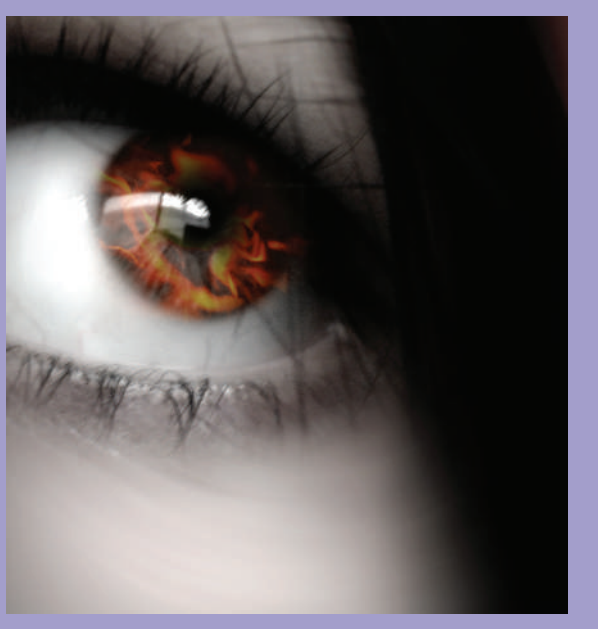

उसके बाद उनसे विपरीत सेक्स के मॉडल की फोटो देखने के लिए कहा गया, जो सिर्फ अंडर गारमेंट में थीं. उसके बाद उनसे दीर्घकालिक संबंध और मनोविनोद के बारे में पूछा गया. 20 फ़ीसदी पुरुषों ने फोटो में जिसका शरीर हष्ट-पुष्ट था, उसे प्राथमिकता दी. जबकि बाकी ने चेहरे को प्राथमिकता दी. जब उनसे अल्पकालीन संबंध के बारे में पूछा गया तो 40 फ़ीसदी ने चेहरे की अपेक्षा शरीर को तवज्जो दी.

राशिफल

25 जनवरी–31 जनवरी 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी. निजी सुख में व्यवधान आने की आशंका है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलने की संभावना है. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. व्यर्थ की समस्या से परेशान हो सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
भागदौड़ रहेगी. संबंधों में निकटता आएगी. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. यात्रा-देशाटन की स्थिति का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें. कोई ऐसी बात हो सकती है, जो आपके हित में न हो.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे. व्यक्ति विशेष का सहयोग मिलेगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. मकान, संपत्ति या गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. धन, पद और प्रतिष्ठा की आकांक्षा पूरी होगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिल सकता है. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. जारी प्रयास फलीभूत होंगे. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
लंबे समय से पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. रचनात्मक कार्य फलीभूत होंगे. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ेगी. धार्मिक प्रयास फलीभूत होंगे. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी. फिर भी अज्ञात भय रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. धन और सम्मान में वृद्धि होगी. आय-व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
स्वास्थ्य में सुधार होगा. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा. धन, सम्मान, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होगी. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. मनोरंजन के सुखद अवसर प्राप्त होंगे. संबंधों में निकटता आएगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. किसी से विवाद होने की आशंका है. वाणी में मधुरता बनाए रखें. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
संतान के व्यवहार से चिंतित रहेंगे. व्यवसायिक उलझनें रहेंगी. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. निजी संबंध मज़बूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद रहेगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अफ़ग़ानिस्तान के खोस्त इलाक़ेमें स्थित अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए के किले में और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक इलाक़े में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया.

पाकिस्तान में भ्रम की स्थिति

कराची को समझना कभी भी आसान नहीं रहा है. पिछले तीन सप्ताह के घटनाक्रमों ने इस काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है. एक शहर की विशाल हक़ीक़त के लिए हम अपने पुरोधाओं को एकजुट होते देख सकते हैं, जिन्होंने एक मुल्क की आशा और हताशा को संगठित कर दिया है. यह पाकिस्तानी विकास का पहिया है और इस मुल्क में मानव पूंजी का सबसे बहुमूल्य स्रोत है.

लेकिन यह भी स्वाभाविक है कि कराची कई मायनों में निष्क्रिय हो चुका है. जातीय मिश्रण, प्रशासनिक और सामाजिक बीमारियों के संदर्भ में अपने जन्म से ही यह पहले पायदान पर रहा है. ग्रामीण–शहरी विभाजन के कारण यह दूसरे शहरों जैसा नहीं है. उदाहरण के तौर पर लाहौर ने अपनी अंदरूनी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर किया है. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पूरे इतिहास में कराची शेष मुल्क से राजनीतिक तौर पर एक क़दम आगे ही था. एक वक़्त ऐसा भी था, जब मजहबी पार्टियां राजनीति में अपना वर्चस्व रखती थीं. अब ज़ाहिर तौर पर, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) उसी प्रकार का समूह है. एमक्यूएम अपना गठबंधन बदलने में स्थिर कारक रहा है. ख़ैर, जब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में क्या हो रहा है, तो ऐसे में यह पूरा परिदृश्य प्रासंगिक नहीं हो सकता है. पूरे मुल्क में जो विकास की लहर चल ही है, उससे ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों की तुलना में कराची में उसका असर ज़्यादा हुआ है. तो क्या इसका मतलब यह है कि कराची में जो सत्ता अस्तित्व में रहती थी, वह बदलने वाली है. एक बार फिर ताज़ा घटनाओं की, उनकी लंबी अवधि के नतीजों के संदर्भ में व्याख्या करना आसान नहीं है. जब हम इन घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारा ख़ास ध्यान अशुरा धमाके के नतीजे पर चला जाता है. ज़ाहिर तौर पर शहर के पुराने बाज़ारों को जलाने और बर्बाद करने की योजना बनाई गई थी. ऐसा किसने किया और उसका मक़सद क्या था? निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे कई तरह की बातें की जा सकती हैं. षड्यंत्रकारी सिद्धांतों के लिए उनमें हम अपने पसंद के सिद्धांत को चुनते हैं. दुर्भाग्यवश वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं को ज़्यादा समय तक लाभ पहुंचने वाला नहीं है. फिर भी यह अंदाज़ा लगाना आसान है कि प्रशासन पंगु हो गया, क्योंकि शीर्ष अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं. नतीजतन, कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है. मसलन, अशुरा बम धमाका आत्मघाती हमला था या वहां पहले से ही विस्फोटक रखे गए थे?

अशुरा बम धमाके का मकसद और उसमें निहित हमारे बाध्यकारी स्वार्थ के तात्पर्य को देखें तो लोगों की हत्या से भय का माहौल पैदा किया गया था. सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और समूहों ने आरोप लगाया कि इन धमाकों में उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया. ल्यारी में एक बड़ी घटना हुई और इसके नतीजे भयावह थे. उच्च स्तर की मीटिंग की गई और कुछ समय के लिए केंद्रीय स्तर पर संघीय आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने वहां डेरा जमाए रखा. उन्होंने करारा जवाब दिया कि इस तरह की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शायद वह यह बात भूल गए कि उन्होंने यही बातें पहले भी कही थीं. लेकिन दोषियों ने उनकी बातों को पूरी तरह नकार दिया.

आख़िर में, एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई. यह कराची की पुरानी बस्ती ल्यारी से शुरू हुआ. इन जगहों पर सिंधी और बलूचों की आबादी काफी अधिक है. यह इलाक़ा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को समर्थन देने में कट्टर माना जाता है. साथ ही ड्रग माफियाओं के गैंगवार की वजह से भी यह जाना जाता है. यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पर उत्साही और सामाजिक ताने–बाने में बेहतर ढंग से बुना हुआ माना जाता है. यह उर्दू भाषी पड़ोसी जैसे लियाक़तबाद और नज़ीमाबाद से मुक़ाबला भी करता है. उन हत्याओं के लिए चाहे जो भी तत्व ज़िम्मेदार रहे हों, ल्यारी की जनता ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का विरोध कर दिया. रविवार और सोमवार की रातों में जिस तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए, वह इन इलाक़ों की राजनीतिक जागरूकता को बताता है. सांप्रदायिक एकता यहां की सबसे उल्लेखनीय बात है. यह बेहद ही दिलचस्प है कि शेष कराची ने आगजनी और धमाकों के बाद ख़ुद को ल्यारी से अलग कर लिया है. लेकिन ल्यारी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और लगभग दस हज़ार लोगों ने प्रेस क्लब तक मार्च किया. नतीजतन शेष शहर को ध्यान देना ही था. यह उल्लेखनीय है कि ल्यारी का यह शक्ति प्रदर्शन महज़ चंद घंटे में ही तय किया गया. यह पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, हालांकि लोगों का गुस्सा उनके नारों में साफ़ झलक रहा था.

फिलहाल मैं ल्यारी की राजनीति में हुए ताज़ा घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा नहीं देने जा रहा हूं. लेकिन, ज़ाहिर तौर पर यह विरोध प्रदर्शन पीपीपी सरकार के ख़िलाफ़ भावुक अविश्वास की अभिव्यक्ति थी. स्वाभाविक तौर पर काफ़ी तेज़ प्रतिक्रिया व्यक्त की गई. एक बार फिर इस बात को लेकर दुविधा पैदा हो गई कि ऑपरेशन की अनुमति किसने दी. पीपीपी के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रिया बड़ी तेज़ी से सामने आई कि मैंने नहीं. ऑपरेशन को तत्काल बंद कर दिया गया है और ल्यारी के लोगों के ज़ख्म पर मरहम लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है.

अब ल्यारी के लोगों द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी एक ख़ास अहमियत थी. और, उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है. भीड़ देखने के लिए मेरे पास एक अवसर था. अलग–अलग समूहों में लोग मेरे ऑफिस के पास से गुज़र रहे थे और तभी मैंने कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की. मैंने जितने प्रदर्शनकारियों से बात की, मुझे लगा कि बलूचिस्तान में मुझे वे सभी बेनज़ीर के वफ़ादार लगे, लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी के बारे में कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था. इस समय मेरा सवाल यह है कि जिन नियमों पर कराची की राजनीति चलती है, क्या ल्यारी उन्हें बदल सकता है? अथवा, यदि इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या यह आंतरिक सिंध और बलूचिस्तान की राजनीति के साथ कराची के संबंधों की शुरुआत है? वह भी इस ज़ोर के साथ, जिसे ल्यारी ने इन तरीक़ों से अहम बनाया है.

सभी फोटो–*पीटीआई*

जी सलाहुद्दीन
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक पाकिस्तान से हैं)

अमेरिका, दक्षिण एशिया और मानव बम

अफ़ग़ानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना.

दक्षिण एशिया आज फिदायीन हमलों से दहल रहा है. जिहाद पर आमादा लोग इस बात से बेपरवाह हैं कि उनकी कमर पर बंधा बम उनकी धज्जियां उड़ा देगा. उन्हें मतलब सिर्फ़ अपने मक़सद से है. इस मक़सद में एक ही कहानी है, जो अलग–अलग शक्ल और शरीर में बयान की जा रही है. यह कहानी न्याय और अन्याय के तराजू पर तौली जा रही है, जहां अन्याय का शिकार एक शख्स न्याय करने पर आमादा है. इन हमलों की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बम को हमारे आपके बीच किसी एक शख्स की कमर पर बांधा जा रहा है. यह ख़तरा इसलिए बड़ा है, क्योंकि हमारे बीच ही ऐसे लोग पनप रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी और मौत के बीच की दूरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दक्षिण एशियाई समाज में पनपते इन बमों को रोका नहीं जा सकता है.

अफ़गानिस्तान के खोस्त इलाक़े में स्थित अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए के किले में और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही जम्मू–कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक इलाक़े में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया. इसी दरम्यान पाकिस्तान में फिदायीन हमला हुआ, जिसने 80 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया.

बीएसएफ द्वारा अटारी बॉर्डर पर गिरफ्तार पाकिस्तानी फिदायीन हमलावर नामून अरशद.

अफ़ग़ानिस्तान में सीआईए पर हमला

अल बलावी को अफ़ग़ानिस्तान के खोस्त शहर के नज़दीक सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) बेस में 30 दिसंबर 2009 को हुए आत्मघाती हमले का साज़िशकर्ता बताया गया. इस आत्मघाती बम हमले में सीआईए के सात अधिकारी मारे गए थे. हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगा कि इस तरह की घटना को अंजाम तक पहुंचाने का आदेश कौन देता है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान ने इस आत्मघाती हमले की ज़िम्मेदारी ली है. अफगान तालिबान ने पहले ही दावा किया था कि आत्मघाती हमलावर अफ़ग़ान सेना का एक अधिकारी था.

अमेरिकी मीडिया (द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट) ने आत्मघाती हमलावर के बारे में जो लिखा है, वह काफी चौंकाने वाला है. हमलावर डबल ख़ुफ़िया एजेंट था. उसे अफ़ग़ान में सीआईए बेस में दाखिल होने की अनुमति इस आधार पर दी गई कि वह अलकायदा के प्रमुख नेताओं के बारे में जानकारी देगा. उसने जानकारी देने का वादा भी किया था. इसी दरम्यान वह अपने मंसूबे में कामयाब हो गया. द वाशिंगटन पोस्ट ने उस आत्मघाती हमलावर का नाम हूमम खलील अबू मूलाल अल बलावी बताया है. वह जॉर्डन का रहने वाला था और जॉर्डन की ख़ुफ़िया एजेंसी ने उसकी नियुक्ति अफ़ग़ानिस्तान में की थी. इस बात की भी संभावना जताई गई है कि उसका मक़सद अलकायदा के सेकेंड–इन–कमांड आयमन अल जवाहिरी को दबोचना था. वेस्टर्न ख़ुफ़िया अधिकारियों के अनुसार, अल बलावी जॉर्डन का एक डॉक्टर था. इतना ही नहीं, वह डबल एजेंट था और आत्मघाती हमले में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रति वफादार भी. वहीं सउदी अरब के अख़बार द नेशनल के मुताबिक़, उसका जन्म कुवैत के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उसके नौ भाई–बहन थे. वह कुवैत में 1990 में हुए इराक के आक्रमण तक रहा. उसके बाद उसका परिवार कुवैत से हमेशा के लिए जॉर्डन चला गया. अल बलावी ने छह साल तक तुर्की के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की और 2002 में स्नातक की उपाधि ली. उसने मेडिकल का प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन हॉस्पिटल से लिया. उसके बाद उसने डैफिनाह बैरेक से शादी की, जो तुर्की की पत्रकार एवं अनुवादक थी. हालांकि इस्लामिक वेबसाइट ने उसे ट्रिपल एजेंट बताया है.

भारत–पाक सीमा पर फिदायीन गिरफ़्तार

आतंकवादियों की एक ख़तरनाक साज़िश का उस समय पर्दाफाश हुआ, जब भारत–पाक सीमा पर पंद्रह साल के नामून अरशद को भारतीय सेना ने गिरफ़्तार किया. बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स ने उसे उस वक़्त गिरफ्तार किया, जब वह बॉर्डर फेंस के बिल्कुल क़रीब था. पूछताछ के दौरान अरशद ने जो सनसनीख़ेज खुलासा किया, उससे भारतीय प्रशासन की आंखें खुली की खुली रह गईं. उसने बताया कि उसे पेशावर में फिदायीन का प्रशिक्षण दिया गया था और वह सात सदस्यीय आतंकी ग्रुप का सदस्य है, जो भारतीय सीमा को लांघने की फिराक में था. उसने यह भी बताया कि मुंबई हमलों में गिरफ़्तार आतंकी अजमल कसाब ने भी उसी जगह से प्रशिक्षण लिया है, जहां उसे और उसके छह अन्य साथियों को प्रशिक्षण दिया गया.

पंद्रह वर्षीय नामून अरशद लाहौर के गुजरापुरा का रहने वाला है. अरशद धर्म शिक्षा के लिए पेशावर जाना चाहता था, लेकिन उसके कुछ साथियों ने उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे आतंकी शिविर तक पहुंचा दिया, जहां उसे प्रशिक्षण देने के बाद भारत में फिदायीन हमले का आदेश देकर भारत–पाकिस्तान सीमा को पार करने का हुक्म दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान उसे उसका यह मक़सद समझाया गया कि उसे भारत में तबाही का ऐसा मंजर फैलाना है, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जाए.

दक्षिण एशिया के सुदूर इलाक़ों में घटी इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखने पर किसी को भी हैरानी होगी. इन्हें एक साथ देखने के पीछे तर्क यह है कि किस हालात में दो शख्स एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, जहां वे अपनी जान देकर अपने साथ कई और लोगों की ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हो गए. फिदायीन हमला दुनिया के लिए नया नहीं है. इस तरह के हमलों की शुरुआत ईरान में उस वक्त हुई, जब अमेरिकी दखलंदाजी के बाद सात वर्षों तक चले ईरान–इराक युद्ध को रोका गया. उसके बाद फिदायीन हमलों को मध्य एशिया की राजनीति में संस्थागत रूप में जोड़ने का काम इज़रायल–फिलीस्तीन विवाद में किया गया. दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जहां फिलीस्तीन एक ऐसा मसला बना, जिसे हम सभ्यताओं के टकराव की स्थिति की संज्ञा दे सकते हैं.

राहुल मिश्र/ बिमलेश झा
feedback@chauthiduniya.com

विधवा स्त्री को साईं पर विश्वास था. उसने बेटे के शव की अंत्येष्टि नहीं करने दी और साईं बाबा की मूर्ति के सामने अपने बेटे का शव रखकर बैठ गई.

साईं मेरे मसीहा हैं : गूफी पेंटल

विकास कपूर

दूरदर्शन के धारावाहिक महाभारत में शकुनी का पात्र निभाने वाले गूफी पेंटल अपनी अभिनय क्षमता से हज़ारों–लाखों लोगों की प्रशंसा के पात्र बने. उन्होंने धारावाहिक महाभारत में केवल शकुनी का क़िरदार ही नहीं निभाया, बल्कि उस भव्य और सफल धारावाहिक की कास्टिंग भी की. मामाश्री के नाम से प्रसिद्ध गूफी पेंटल ने पिछले दिनों रामायण चित्रा की फ़िल्म *श्री चैतन्य महाप्रभु* का सफल निर्देशन भी किया. बहुआयामी प्रतिभा के धनी गूफी के भीतर सद्गुरु साईं समर्थ की सच्ची भक्ति कूट–कूटकर भरी है. बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि अभिनेता, कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर गूफी जी एक अच्छे कवि एवं गीतकार भी हैं. ऐसा नहीं है कि फ़िल्मों में वह काम नहीं कर रहे हैं.

इस समय उनकी कई फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं, जिनमें हिंदी में *लॉटरी* एवं तूफ़ान, भोजपुरी में *जब प्यार हो गइल* और पंजाबी में *मिनी पंजाब* प्रमुख हैं. इसके अलावा एक और फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, जिससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं. इसका नाम है *पानी कम चाय*. यह एक कॉमेडी फ़िल्म है. गूफी जी एक ओर जहां बड़े पर्दे पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीवी और स्टेज पर भी बराबर नज़र आ रहे हैं. उन्होंने इससे पहले भी कई नाटकों में अपनी कला की छटा बिखेरी है. उनके द्वारा अभिनीत नाटक *गधे घोड़े, कान्हा ओ कान्हा, साईं बाबा और हानूस* काफ़ी चर्चित रहे हैं. वह फ्रांस के कांस फेस्टीवल में शिरकत कर चुके हैं, जहां उन्हें शकुनी के किरदार के लिए सम्मानित किया जा चुका है. इस समय गूफी भीष्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस की आगामी फ़िल्म में व्यस्त हैं. साईं बाबा की भक्ति के अनेक गीत लिख चुके गूफी पेंटल ने पिछले दिनों शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के निर्माणाधीन एलबम के लिए कुछ गाने लिखे. प्रस्तुत हैं उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश:

ॐ साईं राम...

जय जय श्री सद्गुरु साईं राम...

आप अपने जीवन में साईं बाबा की कृपा को किस प्रकार देखते हैं?

सच कहूं तो जबसे मुझे साईं का साथ मिला है, तब से जीवन को सही और सच्ची दिशा मिली है. साईं बाबा केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सद्गुरू और मेरे भगवान ही नहीं, सच्चे दोस्त भी हैं. मैं जीवन के हर पल में अपने साईं के साथ रहने का अनुभव करता हूं. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि साईं का वरदहस्त मेरे सिर पर रहता है.

प्रसिद्ध सूफ़ी गायक हमसर ने पिछले दिनों आपका लिखा एक गीत रिकॉर्ड किया. उस गीत के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?

(गीत के बोल गुनगुनाते हुए) *मेरा साईं मेरा मसीहा है. वह सुख देकर दुःख हर लेता है. एक बार जिसे लौ लग जाए, वह साईं दीवाना होता है.* इस गीत के बोल ही मेरी साईं भक्ति का परिचय देते हैं. मेरी रग–रग में मेरे साईं बसे हैं. मैं साईं बाबा के श्रीचरणों में लौ लगाकर हर पल उनका दीवाना बना रहना चाहता हूं. समाज से भी यही कहना चाहता हूं कि एक बार साईं से लौ लगाकर तो देखो, फिर तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा साईं कृपा से इस प्रकार बदलेगी कि दुःख की काली छाया का कहीं नामोनिशान भी नहीं बचेगा. केवल सुख ही सुख होगा.

चौथी दुनिया के माध्यम से आप साईं भक्तों को कोई संदेश देना चाहते हैं?

मैं इतना कहना चाहता हूं कि साईं बाबा केवल बुत (मूर्ति) और चित्र नहीं हैं, वे ज़िंदा ख़ुदा हैं. तुमने उनकी मूर्ति में प्राण–प्रतिष्ठा की हो अथवा न की हो, साईं उसमें विराजमान हैं और हर पल तुम्हारी हर गतिविधि का मूल्यांकन कर रहे हैं. इसलिए अपने जीवन में एक सच्चे साईं भक्त का आचरण करो. ॐ साईं राम.

भक्ति की शक्ति

विभिन्न अख़बारों में पत्रकार और सह–संपादक के रूप में कार्य करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए थे. बचपन से ही मुझे किसी भी दैवीय शक्ति अथवा भगवान नाम की किसी भी सत्ता पर विश्वास नहीं था. मैं कर्म को मानने वाला व्यक्ति था. मेरी मां मुझे प्रायः नास्तिक कहा करती थीं, हालांकि मेरी मां, पत्नी और परिवार के अन्य सभी सदस्य भगवान पर काफ़ी विश्वास करते थे और नियमित पूजा–पाठ भी किया करते थे.

एक दिन जब मैं एक अख़बार के कार्यालय में बैठा था, तभी साईं बाबा के कुछ भक्त आ गए. वे बाबा के किसी चमत्कार का बढ़–चढ़कर बखान कर रहे थे. उनके अनुसार एक विधवा स्त्री के इकलौते बेटे की सांप के काट लेने से मृत्यु हो गई थी. विधवा स्त्री को साईं पर विश्वास था. उसने बेटे के शव की अंत्येष्टि नहीं करने दी और साईं बाबा की मूर्ति के सामने अपने बेटे का शव रखकर बैठ गई. लगभग चौदह घंटे बाद मृत युवा लड़के ने साईं कृपा से आंख खोल दी. अब वह युवा बिल्कुल स्वस्थ है. मेरे पास आए साईं भक्त इसी चमत्कार को अख़बार में छपवाना चाहते थे.

उनकी सारी बात बेमन से सुनने के बाद और नास्तिक होने के कारण मैंने उन्हें काफ़ी अनाप–शनाप कहा और पूछा कि इन चमत्कारों के बारे में बताकर आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? क्या सारी दुनिया कामकाज बंद करके हरि नाम का जाप करने लगे? वे सब शांति से मुझे सुनते रहे, फिर अपने काग़ज़ उठाकर बोले कि महाशय आप क्रोध न करें, शिरडी साईं बाबा तो सभी पर कृपा करते हैं. अगर कभी आप भी किसी परेशानी में घिर जाएं तो सच्चे मन से बाबा को पुकारें, बाबा आप पर रहम ज़रूर करेंगे. उनकी इस बात पर भी मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें कार्यालय से बाहर फेंकवा देने की धमकी देते हुए निराश लौट जाने पर विवश कर दिया.

इस घटना एक राजनीतिक लेख ने मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान ला दिया. मुझे नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया. कई प्रकाशकों के पास मेरा पैसा बाक़ी था, वे भी देने में आनाकानी करने लगे. एक–दो मामले कोर्ट में पहुंच गए. घर की माली हालत बिगड़ती जा रही थी. इस बीच गांव से मेरी मां भी आ गईं. उनकी तबियत ठीक नहीं रहती थी. उनकी दवा पर भी कुछ पैसा ख़र्च हो जाया करता था. एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, मां की दवाई भी नहीं ला पाया था. मां की हालत बिगड़ने लगी और लगभग सवा ग्यारह बजे उनकी मृत्यु हो गई. मैं काफ़ी परेशान था. घर में पैसे नहीं थे. मुझे लगा कि मां की अर्थी तो नहीं उठ पाएगी, अलबत्ता मेरी इज़्ज़त की अर्थी कल सुबह ज़रूर उठेगी. मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए.

मैंने अपने आपको भीतर के कमरे में बंद कर लिया था. मैं फूट–फूटकर रो रहा था. अपने लिखे तमाम लेख फाड़–फाड़कर हवा में उछाल रहा था. तभी इन लेखों के बीच मुझे साईं बाबा का एक चित्र दिखाई दिया. मैं नहीं जानता कि वह चित्र कब और कैसे मेरे लेखों के बीच आ गया. अभी मैं उस चित्र को देख ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में उन्हीं साईं भक्तों के स्वर गूंजने लगे, उनके शब्दों से मुझे शिरडी साईं बाबा की याद आई और मैंने साईं बाबा से प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़ दिए. मैंने बाबा से कहा, मुझे मां के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए सिर्फ़ चौबीस घंटों की मोहलत दे दें, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा. अभी मेरी प्रार्थना पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मुझे मां की पुकार सुनाई दी. वह मुझे ही पुकार रही थीं. मन ही मन बाबा को प्रणाम कर मैं मां के पास पहुंचा. मां अब बिल्कुल स्वस्थ थीं और इतनी देर रात घर में इतने सारे लोगों को आया देख आश्चर्य कर रही थीं.

सुबह उठा तो पोस्टमैन पौने आठ हज़ार रुपये का मनीआर्डर लेकर आया. लखनऊ के एक प्रकाशक ने बाक़ी रूपये भिजवाए थे. सारा घर ख़ुशियों में डूब गया. मां भी काफ़ी प्रसन्न थीं. पर रात होते ही मां की तबियत फिर बिगड़ने लगी. ठीक सवा ग्यारह बजे एक बार फिर मां के प्राण निकल गए. मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ करने को कहा तो मैंने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, मां साईं बाबा के पास चली गई. बाबा से मांगी मियाद पूरी हो गई. मां का क्रियाकर्म करके हम शिरडी जाएंगे. सच कहूं तो पिछली रात मां की मृत्यु पर मैं फूट–फूटकर रोया था, पर आज मेरा मन बिल्कुल शांत था. मुझे मां की मृत्यु पर आत्मिक संतोष था कि वह अब इस आगमन के चक्कर से मुक्त होकर साईं के परमधाम पहुंच गई है. उस दिन के बाद से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी साईं बाबा की सेवा और भक्ति में लगा दी.

(प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार स्व. रामकुमार भ्रमर ने श्री शिरडी साईं बाबा से संबंधित अपना एक अनुभव साईं बाबा और मैं नामक पुस्तक में लिखा था. प्रस्तुत लेख उसी पुस्तक से साभार प्रकाशित किया जा रहा है)

साईं चित्र प्रतियोगिता

प्रिय बच्चों, आज से हम तुम्हारे लिए साईं चित्र प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं. यदि तुम्हारी आयु 14 वर्ष तक है तो अपनी फोटो और आयु प्रमाणपत्र के साथ साईं बाबा का रंगीन चित्र स्वयं बनाकर हमें *शिरडी साईंबाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 17517, मोतीलाल नगर नंबर-1 गोरेगांव (वेस्ट) मुंबई-58* पर भेजो अथवा sai4world@rediffmail.com पर ई-मेल करो.

सभी साईं भक्तों को सूचित किया जाता है कि वे अपने साईं अनुभवों एवं साईं उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@rediffmail.com पर मेल द्वारा भेज सकते हैं.

असीम खेत्रपाल

गुरु ही सफलता का द्वार

भारतीय और विशेष रूप से हिंदू धर्म गुरु की सत्ता को सर्वोच्च मानता है. गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पायं. वास्तव में गुरु प्राचीन संस्कृत का शब्द है, जो गु और रु दो शब्दों से मिलकर बना है. इन दोनों ही शब्दों का व्यापक अर्थ है. प्राचीन संस्कृत में गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला यानी अंधकार का नाश करने वाला.

गुरु के चरणों में सच्चा समर्पण ही व्यक्ति को मोक्ष एवं सफलता के साथ सच्चिदानंद में एकाकार हो जाने की प्रेरणा देता है. शिरडी के साईं समर्थ सच्चे सद्गुरु हैं, जिनके श्रीचरणों में सच्ची श्रद्धा भक्त को सच्चिदानंद में एकाकार हो जाने की प्रेरणा देती है. 15 अक्टूबर 1918 को अपनी महासमाधि से पहले ही साईं बाबा ने भक्तों को वचन दिया था कि उनकी समाधि भक्तों की मनोभिलाषा पूर्ण करेगी और आज भी अनेक भक्त हैं, जो सच्ची श्रद्धा से साईं बाबा को याद कर उनकी कृपा पाते हैं.

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन का साईं भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साईं की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साईं चरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साईं भक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साईं भक्ति को और अधिक दृढ़ करने एवं सद्गुरु साईं समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साईं भक्त..... और फोन नंबर..... कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें.

ज्ञानोदय

प्रेम में स्मृति का ही सुख है. एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है. **-बाबू जयशंकर प्रसाद**

प्रेम एक बीज है, जो एक बार जमकर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है. **-प्रेमचंद**

प्रेम से भरा हृदय अपने प्रेम पात्र की भूल पर दया करता है और ख़ुद घायल हो जाने पर भी उससे प्यार करता है. **-महात्मा गांधी**

प्रेम कभी स्वयं को नहीं पहचानता, दूसरों के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है. स्वार्थपरता और प्रेम घोर विरोधी हैं. जहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम पनप ही नहीं सकता. **-अश्विनी कुमार दत्त**

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!
Giriraj Sai Hills

Giriraj Sai Hills offers an innovative selection of Fully Furnished and Spacious Studio, One Bedroom, Two bedroom Apartments & Fully Furnished Villa
Starting From Rs. 9.65 lakhs*
AUM
Aum Infrastructure & Developers
Delhi Office : 156, Sant Nagar, Ground Floor, East of Kailash, New Delhi-110065
Phone No: +91 11 46594226 / 46594227

जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में गंगा की धारा के बीच खड़ा श्री गंगा मंदिर तो आज भी असज्जित है बाक़ी हरकी पौड़ी दर्ज़नों खोखा मंदिरों, बेतरतीब-असुंदर तख्तों और जगह-जगह रखी गंगासभा की दान वसूली मेज-कुर्सियों का समुच्चय बनकर रह गई है.

इलियट के राज

अनंत विजय

अस्सी के दशक की एक फ़िल्म में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अंग्रेजी कविता को नई दिशा देने वाले कवि टी एस इलियट के पारिवारिक जीवन के कई अनछुए पहलुओं को दर्शाया गया था, जिसे लेकर अच्छा-ख़ासा विवाद खड़ा हो गया था. इलियट पर आरोप लगता रहा है कि वह एक क्रूर पति थे और अपनी पहली पत्नी विवियन पर तमाम ज़ुल्म किया करते थे. इसे लेकर इंग्लैंड और अमेरिका में अच्छा- ख़ासा विवाद भी रहा है. इलियट के जीवनकाल में उन पर जमकर हमले भी हुए और उन्हें तमाम आलोचनाएं झेलनी पड़ीं.

दरअसल अगर हम इलियट के जीवन के पन्नों को थोड़ा पलटें तो बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है. यह 1915 के वसंत की बात है, जब हॉवर्ड में डॉयल के संपादक सियोफील्ड थायर ने अपनी बहन की दोस्त एवं डांसर विवियन वुड से इलियट को मिलवाया. वसंत का मौसम था, पहचान को प्यार में बदलते देर नहीं लगी और इलियट ने परिवार की मर्जी के ख़िलाफ़ विवियन से शादी रचा ली. लेकिन इसके बाद के संघर्ष ने दोनों के रिश्तों के बीच खटास पैदा कर दी. एक वजह विवियन की बर्टेंड रसेल से नज़दीकी भी रही. संघर्ष के दिनों में इलियट अपनी पत्नी के साथ रसेल के घर रह रहे थे, उस दौरान कुछ समय के लिए बर्टेंड रसेल और विवियन एक-दूसरे के बेहद क़रीब आ गए थे. इस क़रीबी ने पति-पत्नी के रिश्ते में दरार डाल दी. संबंध बनते-बिगड़ते रहे, लेकिन दस साल के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे और अपने धार्मिक विश्वास के चलते तलाक नहीं ली. पति से अलग रहने एवं साथ होने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने से विवियन को जो मानसिक तनाव और अवसाद हुआ, उसने उसे अंदर से तोड़ दिया. हालात इतने बिगड़े कि उसे लंदन के एक मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करवाना पड़ा. तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती चली गई और 1937 में गुमनामी में विवियन की मौत हो गई. यह वह वक़्त था, जब इलियट को अंग्रेजी कविता की दुनिया में प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा दोनों हासिल हो रही थी. आलोचकों का आरोप है कि अपने करियर के चक्कर में इलियट ने पत्नी पर समुचित ध्यान नहीं दिया और उसे उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया. कालांतर में इलियट ने दूसरी शादी भी रचाई.

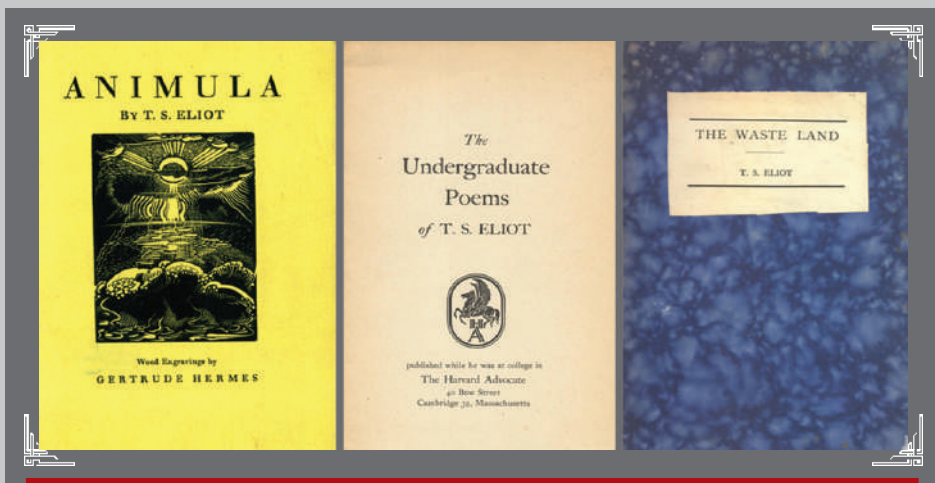

इलियट की कृतियां

लेकिन, इलियट की मौत के चालीस साल बाद ये तमाम आरोप ख़ारिज़ होते नज़र आ रहे हैं. इलियट की दूसरी पत्नी केवैलेरी ने इलियट के कुछ पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया है, जो बीस से तीस के दशक में इलियट ने अपने भाई एवं साहित्यिक मित्रों को लिखे थे. इन पत्रों से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि इलियट अपनी पहली पत्नी की बीमारी को लेकर बेहद दु:खी रहा करते थे. विवियन की देखभाल करने वाले डॉक्टरों को कोसते हुए इलियट उन्हें जर्मन ब्रूट और अपनी हुनर का दंभ भरने वाला करार दे रहे थे. उन्होंने एक पत्र में लिखा कि वह अपनी पत्नी की बीमारी से इतना तंग आ चुके हैं कि वह आत्महत्या करना चाहते हैं.

अप्रैल, 1944 में इलियट ने अपने भाई को लिखा, विवियन की पिछली बीमारी और उसकी वजह से जो कष्ट झेल रही है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता. मैं उसे तीन महीने के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकता. जब 1927 में इलियट ने अमेरिका की नागरिकता छोड़ कर ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार की तो उन्होंने उपन्यासकार जॉन मिडिल्टन मरे को एक पत्र लिखा, मेरी पत्नी की तबीयत बेहद ख़राब है और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पिछले तीन दिनों से वह यह सोच रही है कि उसके शरीर और दिमाग़ का साथ छूट चुका है. अपने दु:ख और संत्रास का वर्णन करते हुए इलियट ने यहां तक लिख दिया कि मैंने जानबूझ कर अपनी भावनाओं का क़त्ल कर दिया है, अपने आपको मार दिया है, ताकि मैं विवियन को यह अहसास दिला सकूं कि कोई उसका ध्यान रखने वाला है. मरे को ही एक दूसरे खत में इलियट ने यह लिखा, विवियन की तबीयत बहुत ख़राब है और कई बार तो यह लगता है कि वह मौत के बिल्कुल पास खड़ी है. ये उसके जीवन के सबसे ख़राब पल हैं और वह क़िस्मत के सहारे ही जीवित है.

इलियट के इस पत्र को उनकी दूसरी पत्नी के सक्रिय सहयोग से प्रकाशित किया गया है. इन पत्रों से इलियट के क्रूर पति और एंटी सीमेटिक होने की जो छवि थी, वह ध्वस्त होती लग रही है. लेकिन, पत्रों के इस संग्रह के प्रकाशन के पहले ही पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर अच्छी-ख़ासी साहित्यिक बहस शुरू हो गई है और इलियट के समर्थकों ने आरोप लगाने वाले आलोचकों पर हल्ला बोल दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस किस दिशा में मुड़ती है और अंग्रेजी के महानतम कवियों में से एक इलियट को लेकर अंग्रेजी आलोचकों का क्या रुख़ होता है.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

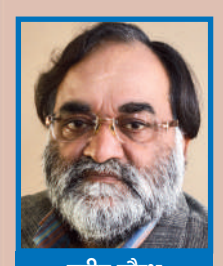

प्रदीप सौरभ

अहमदाबाद में पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने वाला जुहापुरा इलाक़ा था. उस इलाक़े में रहने वाले बिल्डर और पोलिटीशियन सगीर अहमद से लतीफ ने प्रोटेक्शन मनी की मांग की. भाजपा से विद्रोह कर जोड़तोड़ द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री बने शंकर सिंह वाघेला से सगीर के अच्छे रिश्ते थे. सगीर ने लतीफ की अनसुनी कर दी. लतीफ ने जेल के अंदर रहते अपने गुर्गों से सगीर की हत्या करवा दी. वाघेला इस बात से बहुत आहत हुए. इसी के बाद लतीफ के एनकाउंटर की तैयारियां शुरू हो गईं. सगीर की हत्या के एक सप्ताह के अंदर लतीफ की मौत का इंतज़ाम कर दिया गया. अंततः लतीफ मारा गया और उसके आतंक का ख़ात्मा हो गया.

1997 में उसकी मौत के बाद शराब के धंधे में एक प्रकार का वैक्यूम आ गया. हालांकि लतीफ के छुटभैयों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं संभला. बाद में लतीफ के धंधे को हिंदू व्यापारियों ने संभाल लिया. हिंदू ब्रिगेड का इन व्यापारियों को समर्थन मिलने लगा. दंगों में लतीफ की जो भूमिका होती थी, उसकी भरपाई करने वाला मुसलमानों के बीच अब कोई नहीं था.

मोदी सरकार ने दंगों की स्क्रिप्ट लिख ली थी. पुलिस द्वारा दंगाइयों को खुली छूट देना तय हो चुका था. ख़ून का बदला ख़ून. दंगाई मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के नेतृत्व में पहुंचने लगे. हमले पर हमले. लाशें ज़मीन पर बिछने लगीं. गुजरात की फिजा में लाशों की दुर्गंध तैरने लगी. अहमदाबाद में ऊंची दीवारों से घिरी गुलबर्ग सोसायटी आग के हवाले कर दी गई. दंगाइयों ने लोगों को तलवारों से काटा. पैंतालिस लोग मारे गए. नरोडा-पाटिया में दंगाइयों ने बस्ती को दोनों ओर से घेर कर आग लगा दी. आग में झुलसते लोगों को भागने भी नहीं दिया गया. क़रीब सौ लोगों का वहीं क़ब्रिस्तान बन गया.

आग फैलती गई. बड़ोदरा में बेस्ट बेकरी की भट्टी में बेकरी के मालिक के पूरे परिवार को झोंक दिया गया. लूनावाड़ा में दंगाइयों से जान बचाकर भाग रहे ट्रक में सवार 67 लोगों को ज़िंदा जला दिया. सांबरकांठा के विसनगरम में दर्ज़नों को मौत के घाट सुलाया गया. पंचमहल ज़िले में पांडरवाडा में बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. सरदारपुरा की कहानी में भी तीस लोग ज़िंदा दफ़न कर दिए गए. चुन-चुनकर लोगों को मारा.

दंगाइयों की रणनीति से लग रहा था कि गोधरा

अग्निकांड न भी होता, तो भी गुजरात में दंगों की भूमिका तैयार थी. दंगाई वोटरलिस्ट लेकर मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे थे. दिल्ली दरवाज़ा के बाहर बनी दुकानों का वाक्या है. दंगाइयों ने दुकानों में आग लगा दी. इस बीच पता चला कि इन दुकानों में एक हिंदू की दुकान है, तो वे उसे बुझाने में जुट गए. दुकान में लगे फोन से दुकानदार को आग लगने की सूचना भी दी. बताया कि आकर आग बुझा लो. मुसलमानों की आर्थिक तरक़्क़ी भी दंगाइयों की आंख में खटक रही थी. चेलिया समुदाय के लोगों के होटलों को खोज-खोजकर आग के हवाले कर दिया. ये चेलिया वे लोग हैं, जिन्होंने गुजरात में पंजाबी और उत्तर भारतीय भोजन को सस्ते में परोस कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

गुजरात में मुसलमान होना गाली बन गया था. मुसलमान पाकिस्तानी हो गए थे और हिंदू राजा हिंदुस्तानी. एक देश में दो देश. ख़ास तरह की दाढ़ी और टोपी किसी की भी मौत का सबब बन सकती थी. आनंद भारती भी दाढ़ी रखते थे. उनके शुभचिंतक उन्हें फोन कर दाढ़ी कटाने की सलाह दे रहे थे. दाढ़ी कटवाना विकल्प नहीं था. गुजराती अख़बारों को छोड़ कर राष्ट्रीय अख़बार मोदी के कारनामों का खुलासा कर रहे थे. इसीलिए वे हिंदू ब्रिगेड के निशाने पर थे. उन्हें धमकी भरी गुमनाम चिट्ठियां भेजी जा रही थीं. गुजरात से भागने की सलाह दी जा रही थी. पत्रकारों पर हमले किए जा रहे थे. टीवी पत्रकारों की ओबी वैंस को भी कई बार निशाना बनाया गया. आनंद भारती की कार पर भी हमला हुआ. एक बार उन्हें दंगाइयों ने पकड़ कर कहा, बोलो, भारत माता की जय. वंदेमातरम.

(अगले अंक में जारी)

feedback@chauthiduniya.com

कामकाज से शासन संतुष्ट, लेकिन आम लोग नहीं

डॉ.कमलकांत बुधकर

उत्तराखंड के तीर्थनगर हरिद्वार में कहने को महाकुंभ शुरू हो चुका है और सरकारी घोषणाओं में इस महापर्व की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. घोषणाओं से ऐसा लगता है कि मेज़बान जाजम बिछाकर, थाली परोस कर और हाथ में पंखा लिए बस दरवाज़े पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब मेहमान आएं और कब उनकी ख़ातिरदारी शुरू हो. लेकिन, मेहमानों के आने में अभी देर है और परिस्थितियां भी कुछ अलग हैं. घर का मुखिया भले ही हर बार और हर तरह से घोषणा करे कि हम करोड़ों लोगों के स्वागत के लिए तैयार हैं, पर बाक़ी घर वाले इसके लिए पूरी तरह अब भी तैयार नहीं हैं.

यह पंक्तियां मकर संक्रांति स्नान के पहले दिन लिखी जा रही हैं. गत 12 जनवरी को ही मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने देश-विदेशों के लिए बनाए गए प्रेस-मीडिया केंद्र का उद्घाटन किया. इन दिनों मुख्यमंत्री जब भी हरिद्वार आते हैं, उनकी ज़ुबान पर तुलनात्मक आंकड़े ही रहते हैं. वह यह बताते नहीं अघाते कि पिछले अर्द्धकुंभों और कुंभों की तुलना में इस बार उनकी सरकार ने सर्वाधिक पैसा ख़र्च करके सर्वाधिक स्थायी कार्य कराए हैं. उनका दावा है कि 2004 तक के इन महामेलों में 75 प्रतिशत अस्थायी और पच्चीस प्रतिशत स्थायी कार्य हुए. जबकि इस बार उनके अनुसार, स्थिति उलट है. पच्चीस प्रतिशत अस्थायी कार्यों के मुक़ाबले 75 प्रतिशत कार्य स्थायी हो रहे हैं, वह भी समय सीमा में. लेकिन, आंकड़ों की यह बयानबाज़ी कितनी खोखली है, यह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बख़ूबी मालूम है. मज़े की बात यह है कि मुख्यमंत्री जब 1998 के कुंभकार्यों की आलोचना करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि तब भी उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपाई सरकार थी और वह स्वयं उस सरकार में मंत्री थे. ख़ैर..!

अब दिल्ली से हरिद्वार आने वाले मुख्य राजमार्ग की बात करें. मुज़फ़्फ़रनगर बाईपास से आगे रुड़की और रुड़की से हरिद्वार तक, सहारनपुर से वाया रुड़की हरिद्वार, नजीबाबाद-बिजनौर से हरिद्वार और ऋषिकेश-देहरादून से हरिद्वार आदि मार्ग वैसे ही हैं, जैसे 1998 के महाकुंभ एवं 2004 के अर्द्धकुंभ के दौरान थे. हरिद्वार में प्रवेश कराने वाले किसी भी मार्ग को आवश्यकता और वादों के बावजूद फोरलेन का नहीं बनाया जा सका है. हरिद्वार के दोनों ओर देहरादून और दिल्ली मार्गों को थोड़ी दूर तक दो-दो ढाई-ढाई फुट चौड़ा करने की कवायद अलबत्ता दिसंबर-जनवरी में हुई है, पर उसके चलते सड़कों की मरम्मत तक आधी-अधूरी है. सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं है, यह अधिकारी स्वयं मानते हैं और इसके लिए अब ठंडे मौसम को दोष देते हैं. पर सच्चाई यह है कि कुंभ प्रशासन द्वारा किए जा रहे सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में परस्पर विभागीय सामंजस्य का घोर अभाव देखा गया. हरिद्वार की शायद ही कोई सड़क ऐसी हो, जिसे बार-बार न तोड़ा गया हो. कभी गंगा प्रदूषण वालों ने सड़क तोड़ी तो कभी बीएसएनएल वालों ने! कभी जल निगम वाले तोड़ गए तो कभी बिजली वाले खोद गए. सड़क निर्माण का सबसे भद्दा उदाहरण ख़ास हरकी पौड़ी तक पहुंचाने वाली अपर रोड है, जिसे विभाग ने स्थानीय नागरिकों की परेशानी समझे बग़ैर इतना ऊंचा बनाने की कोशिश की कि उनकी दुकानें नीचे गड्ढे में पहुंच गईं. नाराज़ नागरिकों ने बनी-बनाई सड़क तोड़ दी. अब कहा जा रहा है कि वह कुंभ के बाद ही बन पाएगी. सड़क पर थीगले ज़रूर लगा दिए गए हैं. रोड़ी मैदान में सर्विस लेन के नाम पर एक सड़क बनाई जा रही है. यह सड़क कुंभ के बाद की बारिश झेल ले तो बड़ी बात होगी.

जहां तक सफाई का प्रश्न है तो सड़क निर्माण के बाद कुंभ कार्यों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. लोक निर्माण विभाग के बाद सर्वाधिक व्यय कराने वाला विभाग स्वास्थ्य है. इस विभाग द्वारा स्थायी से ज़्यादा अस्थायी मदों में ख़र्च किया जाता है और उसी में अधिकारियों के लिए भारी गुंजाइश निकलती है. इतिहास

चर्चा कुंभनगर की

में अनेक कुंभ स्वच्छता के अभाव में प्लेग और हैज़े जैसी महामारियों की भेंट चढ़ चुके हैं. 1891 के महाकुंभ को तो हैज़े के प्रकोप के चलते एकबारगी निरस्त करने तक का मन अधिकारियों ने बना लिया था. मेले में स्वच्छता बहुत मायने रखती है. लेखक को ऐसे भी कुंभ याद हैं, जिनमें हरिद्वार शहर, यहां के घाट, गलियां, बाज़ार और सड़कें सब चमचमाया करते थे. हरिद्वार शहर की स्वच्छता की सूचक यहां की प्रसिद्ध शिवमूर्ति है, जो रेलवे स्टेशन के निकट वाले चौराहे पर आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है. लेकिन अब तो समय बदल गया है. जनजागृति ने अधिकार तो दे दिए, पर कर्तव्य से दूर कर दिया. सफाईकर्मी बढ़ाए गए, उनका दैनिक वेतन 180 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया और यह छूट भी उन्हें दी गई कि उनका भुगतान बैंक में खाता खोले बग़ैर नक़द ही होगा. इन सारी सुविधाओं के बावजूद सरकारी कुंभकाल शुरू होने के बाद भी जगह-जगह गंदगी के ढेर हैं. सड़कों का कूड़ा नालियों में ठूंस दिया जाता है. कई-कई दिनों तक कूड़ा उठता नहीं है. सभी शहरों का यही हाल है. पंचपुरी के हरिद्वार मायापुर इलाक़े में तो फिर भी सफाईकर्मी नज़र आ जाते हैं, पर ज्वालापुर की हालत तो बदतर है.

बिजली-पानी के मामले में भी करोड़ों रुपये ख़र्च होने के बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं. सघन बस्ती ज्वालापुर में जनवरी के दूसरे सप्ताह में यह हाल है कि बिजली एक घंटे के लिए जाकर फिर आधा घंटा आती है और फिर एक घंटे के लिए गुल हो जाती है. कुंभ का केंद्र हरकी पौड़ी तो सायंकालीन आरती के बाद प्राय: अंधेरे में होता है. नाईघाट सहित हरकी पौड़ी पर लगाए गए चार हाईमास्क जलते तो हैं, पर उनकी रोशनी अपर्याप्त रहती है. हरकी पौड़ी के घाट अंधेरे में ही रहते हैं. अधिकारियों का कहना है कि हमने वहां तक बिजली पहुंचा दी है. अब आगे का काम हरकी पौड़ी की व्यवस्थापिका श्री गंगासभा या नगर पालिका परिषद करे. पंडों की संस्था श्री गंगासभा में जूतों में दाल बंट रही है. उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि हरकी पौड़ी पर गंदगी है या इलाक़ा अंधेरे में डूबा है. वे आपस में लड़ने-भिड़ने में ही मशगूल हैं. यही वजह है कि कुंभ प्रशासन ने भी मुख्य स्नान स्थल हरकी पौड़ी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है. बारह बरस से अपने जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में गंगा की धारा के बीच खड़ा श्री गंगा मंदिर तो आज भी असज्जित है, बाक़ी हरकी पौड़ी भी दर्ज़नों खोखा मंदिरों, बेतरतीब-असुंदर तख्तों और जगह-जगह रखी गंगासभा की दान वसूली मेज-कुर्सियों का समुच्चय बनकर रह गई है. श्री गंगा मंदिर कुंभस्थली का हृदय केंद्र है, पर न शासन का ध्यान उसकी ओर है और न कुंभ प्रशासन का. प्रशासन चाहे तो मंदिर के व्यवस्थापकों को अस्थायी सज्जा का निर्देश देकर हरकी पौड़ी की सुंदरता तो लौटा सकता है, पर कोई कुछ क्यों करे? हरिद्वार एवं हरकी पौड़ी पर दिल्ली-देहरादून से माननीय लोग आते हैं और गंगाजली प्रसाद से आवभगत पाकर सब कुछ अच्छा है के फतवे जारी करके लौट जाते हैं.

लोगों का कहना है कि प्रशासन का सारा ध्यान साधु-संतों और उनके अखाड़ों की ओर ही है. रहना भी चाहिए, क्योंकि साधु-संतों के अखाड़े अगर अपनी अखाड़ेबाजी पर उतर आए तो प्रशासन की नींद हराम करने में उन्हें देर नहीं लगेगी. यही वजह है कि आज वे प्रशासन से वह सब कुछ करा लेना चाहते हैं, जिसे कराने में फिर बारह बरस की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. अखाड़ों ने अपने-अपने परिसरों में कुंभ प्रशासन के ख़र्चे पर लाखों-करोड़ों रुपये के कार्य करा लिए हैं और ऐसे निर्माणों की अनुमतियां आनन-फानन ने ली हैं, जो सामान्यतया मिलना मुश्किल होतीं. बहरहाल साधु-संतों का कुंभ तो 14 अप्रैल के बाद शेष हो जाएगा. बाक़ी रहेगी जनता और शासन-प्रशासन, जो बाद तक या कहिए कि अगले चुनावों तक हिसाब मांगते-देते रहेंगे!

kk@budhkar.in

स्वाति मोदो के रिसायकल्ड सीडब्ल्यूजी कलेक्शन हेम्प और जूट से बने हैं. स्वाति के ये डिजायनर जूते न सिर्फ़ शुभ हैं, बल्कि स्टाइलिश और आरामदायक भी हैं.

स्वाति के जोडिएक जूते

आपने राशि चक्रों पर आधारित ब्रेसलेट और अंगूठियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसे जूतों के बारे में नहीं सुना होगा, जो आपकी गृह दशाओं पर आधारित हैं. अमेरिकी कंपनी ट्रस्टी एलायंस ने स्वाति मोदो ने साथ मिलकर जोडिएक पर आधारित जूते लांच किए हैं. इनकी ख़ासियत है कि ये पूरी तरह ज्योतिष गणना पर आधारित हैं. जन्म विवरण ज्योतिष को लग्न कुंडली से षोदस वर्ग सितारे निकालने में मदद करता है. चंद्रमा की स्थिति जातक को दूसरे ग्रह दशा के साथ जन्मदशा भी प्रदान करती है. वर्तमान दशा पांच वर्गों में होती है, जिससे जातक को सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं. उक्त पांच दशाएं हैं- महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा और सूक्ष्मदशा. सभी महादशाओं के अपने ग्रह होते हैं, जो उन्हें नियंत्रित करते हैं. जन्म कुंडली से शुभ अंक, शुभ रंग और हमेशा साथ रखने वाली शुभ लकड़ी का पता चलता है. स्वाती मोदो के जोडिएक जूते इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इनमें राशि के हिसाब से ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके इन्हें शुभ बनाया जाता है, जिससे पहनने वाले के क़दम सिर्फ़ संकेतों पर उठें. यह जूते शुभ मुहूर्त निकाल कर कुशल ज्योतिषों के निरीक्षण में बनाए जाते हैं. इन्हें बनाने के लिए राशि के अनुसार शुभ माने गए फैब्रिक का रंग, धागा, लकड़ी, धातु, पत्थर, नगीने, नॉन लेदर गुडस आदि का इस्तेमाल होता है. स्वाति मोदो के रिसायकल्ड सीडब्ल्यूजी कलेक्शन हेम्प और जूट से बने हैं. स्वाति के ये डिजायनर जूते न सिर्फ शुभ हैं, बल्कि स्टाइलिश और आरामदायक भी हैं. स्वाति हमेशा डिज़ायनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी. अपनी लालसा को बेहद क्रिएटिव तरीक़े से इस्तेमाल करते हुए उसने जोडिएक जूतों के रूप में एक नायाब तोहफ़ा दुनिया के सामने पेश किया है.

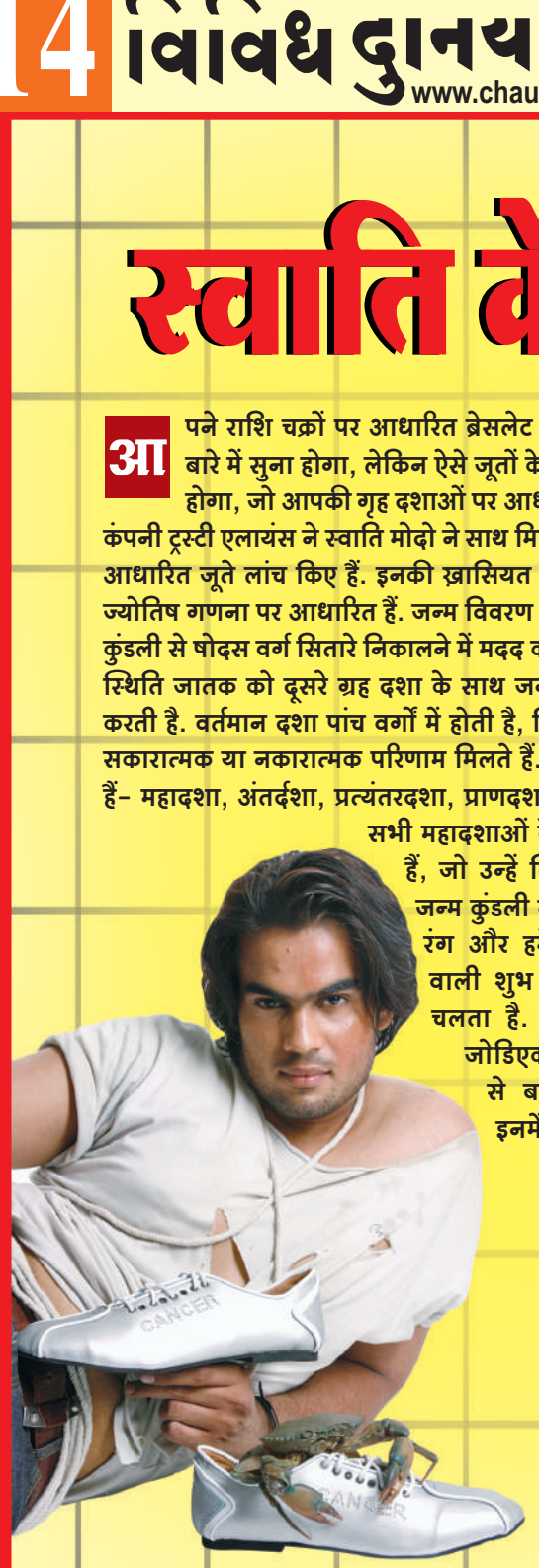

वी सीरीज़ ग्लोबल न्यू एज मोबाइल

वीडियोकॉन ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में अपना क़दम बढ़ाते हुए आधुनिक फीचर्स से लैस ग्लोबल मोबाइल फोन लांच किया है. भारतीय युवाओं की पसंद, मोबाइल फोन के प्रति उनके नज़रिए और ज़रूरतों का अध्ययन करके कंपनी ने स्टाइलिश वी सीरीज़ मोबाइल हैंडसेट रेंज बाज़ार में उतारी है. वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वी एन धूत ने इस अवसर पर कहा कि मोबाइल फोन सेवा के क्षेत्र में कंपनी क्वालिटी, रेंज, तकनीक और वैल्यू किसी में कोई समझौता नहीं करेगी, जिससे वह भारतीय उपभोक्ताओं के दिल पर राज कर सके. इस मोबाइल फोन में कई आधुनिक फीचर्स हैं, जिनमें बेसिक कलर मोड्यूल्स, फोन विद एफ एम रेडियो, सिंगल-डबल सिम की सुविधा, एमपी-3 म्यूजिक, कैमरा, मल्टीमीडिया, आधुनिकतम टच फोन एवं टच विंडो फोन आदि शामिल हैं. इसके अलावा इस फोन का आकर्षक लुक लोगों को लुभाने के लिए काफ़ी है.

वीडियोकॉन मोबाइल फोन डिवीजन के सीईओ अनिल खेरा ने कहा कि कंपनी की विश्वसनीयता जनता के बीच बनी रहे, इसके लिए सेवा एवं प्रोडक्ट की क्वालिटी पर हमारा पूरा ध्यान है. इसी बात का ख्याल यूनिक फीचर्स वाले इस मोबाइल फोन में भी रखा गया है. सीईओ राहुल गोयल ने कहा कि भारतीय बाज़ार की पहुंच अब विश्व स्तर तक हो गई है. कंपनी ने फोन लांच करते हुए उपभोक्ताओं के रिस्पांस का पूरा ध्यान रखा है. वीडियोकॉन के नए लोगो वी और मोबाइल फोन का ब्रांड प्रचार संदेश वी इज द न्यू मी को भी काफ़ी पसंद किया जाएगा. मोबाइल फोन की क़ीमत उनके मॉडल्स एवं फीचर्स के अनुसार 1650 रुपये से लेकर 18,500 रुपये तक रखी गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लेनोवो का नया थिंक पैड टी-510

लेनोवो ने थिंक पैड लैपटॉप की सीरीज़ में नया थिंक पैड टी-510 लांच किया है. इसे ख़ासतौर से बिजनेस यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह इंडस्ट्रियल डिजायन में बना है और देखने में स्लीक है. इसमें सिमेट्रीकल डिस्प्ले, क्लीन लाइंस और मज़बूत एवं चौड़े कब्जे हैं. इस लैपटॉप को कंफर्टेबल के साथ-साथ स्टाइलिश बनाता है इसका नेक्स्ट जेनेरेशन की-बोर्ड. इसके सॉफ्ट की बटन प्रयोग में बहुत ही आसान हैं. इसके अलावा मॉडर्न लुक के लिहाज़ से कंपनी ने इसमें टचपैड डाला है, जिसे इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है. 15 इंच स्क्रीन साइज के थिंक पैड टी-510 में इंटेल कोर आई-5 और आई-7 भी हैं. इसके अलावा इस ख़ास लैप्पी में ऑप्शनल एनविडिया डेडीकेटेड ग्राफिक्स की भी सुविधा है. आप कई तरह के डिजाइन प्रोजेक्ट पर इस फीचर का बख़ूबी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें सिर्फ़ फीचर्स और स्टाइलिश लुक ही नहीं है बल्कि यूजर्स की आंखों का भी ध्यान रखा गया है. आंखों को साइड इफेक्ट से बचाने के लिए कंपनी ने इसके स्क्रीन पर लेड बैकलाइट और एंटी-ग्लेयर कोटिंग की है. इस लैपटॉप में मल्टी टच ट्रैक पैड के साथ 2- एमपी वेब कैमरा, चार यूएसबी पोर्ट जिनमें एक यूएसबी कोम्बो पोर्ट एवं ईसाटा पोर्ट हैं, एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट, डिस्प्ले पोर्ट एवं वीजीए आउटपुट, फायर वायर पोर्ट, 5 इन 1 मीडिया कार्ड रीडर, फिंगर प्रिंट रीडर और एक ऑप्शनल स्मार्ट कार्ड रीडर है. कंपनी के अनुसार, थिंक पैड टी-510 18 घंटे का रन टाइम देता है और एक्सट्रा इस्तेमाल के लिए कंपनी की तरफ़ से इसके साथ 9 सेल स्लाइस बैट्री दी गई है. लेनोवो के ऑनलाइन स्टोर से थिंक पैड टी-510 को 999 डॉलर में ख़रीदा जा सकता है.

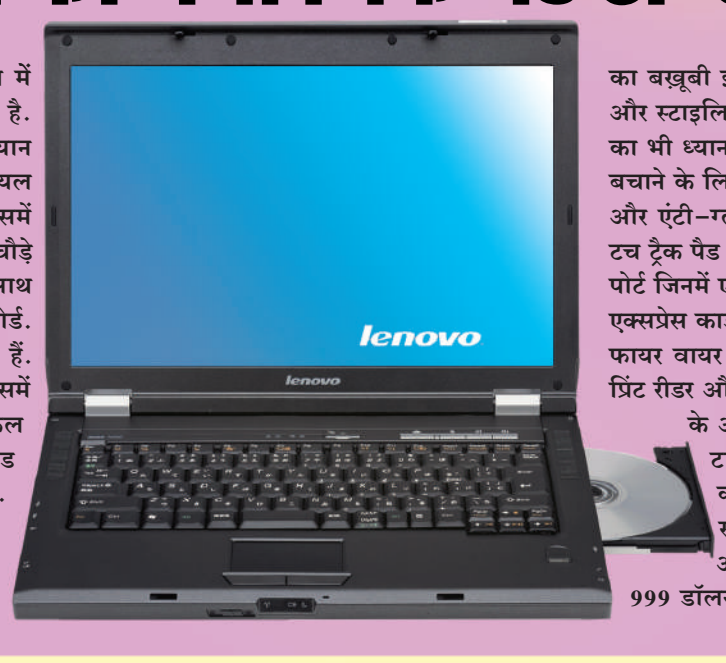

सितारों के हाथ बच्चों के साथ

बचपन की पढ़ाई में किसी स्पोर्ट्सपर्सन और एक्ट्रेस का कितना मन लगता होगा, यह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन अपनी स्टेशनरी से क्रिकेटर और एक्ट्रेस का जुड़ाव देखकर बच्चों को कितनी ख़ुशी होगी, यह कहना कठिन नहीं है. यही वजह है कि आईटीसी एजूकेशन व स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कंपनी क्लासमेट ने स्टाइलिश क्रिकेटर युवराज सिंह एवं चर्चित अदाकारा सोहा अली खान को बतौर ब्रांड एंबेसडर साइन किया है. पिछले दिनों क्लासमेट ने स्टेशनरी की नई रेंज, जिसमें पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और नोटबुक्स आदि शामिल हैं, लांच की है. इन सभी पर सोहा अली खान एवं युवराज की फोटो देखकर बच्चों को अच्छा लगेगा. साथ ही उन जैसा बनने की प्रेरणा भी मिलेगी. इस अवसर पर आईटीसी एजूकेशन व स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस चीफ एक्जीक्यूटिव चांद दास ने कहा कि सभी बच्चों में कोई न कोई ख़ास तरह का गुण ज़रूर होता है, जिसे उभार कर सामने लाने की ज़रूरत होती है. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेरणा और प्रोत्साहन की होती है. ब्रांड के साथ जुड़े दोनों ही लोग अपने-अपने क्षेत्रों में कामयाब हस्तियां हैं. ब्रांड के साथ जुड़ने के मौक़े पर स्टार क्रिकेटर युवराज ने कहा कि खेल और शिक्षा दो अलग-अलग चीजें न होकर एक साथ मिलकर किसी भी बच्चे का जीवन संवारने का काम करते हैं. आगे चलकर यह बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह खेलकूद में आगे बढ़ना चाहता है या एजूकेशन सेक्टर में. अभिनेत्री सोहा ने कहा कि वह क्लासमेट ब्रांड की तरह ही डिफरेंट आइडियाज में विश्वास करती हैं और अपने जीवन में आइडिया पर ख़ास जोर देती हैं, बात चाहे फ़िल्में साइन करने की हो या दूसरे फ़ैसलों की. क्लासमेट बच्चों के लिए नए आइडियाज को सपोर्ट करती है.

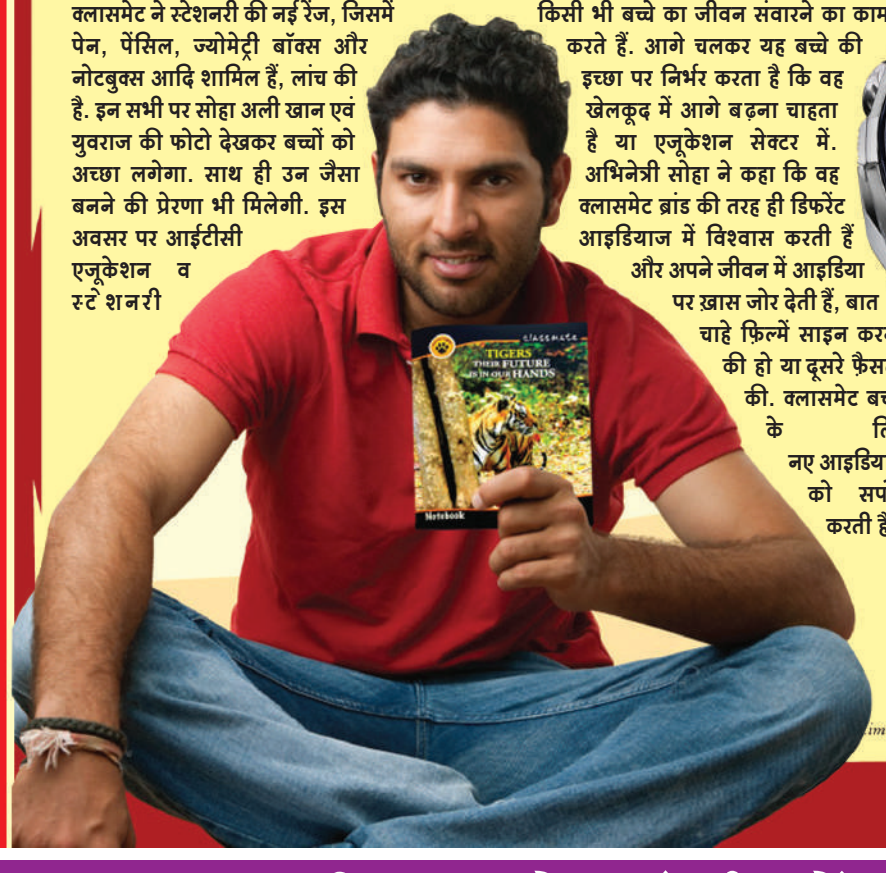

टैग हॉयर की नई रेंज

आधुनिक ड्रेसिंग सेंस में घड़ियों की अपनी ख़ास जगह है. ये अब केवल वक़्त जानने का ज़रिया नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गई हैं. इस स्टाइलिश ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए घड़ियों की कंपनी टैग हॉयर ने महिलाओं और पुरुषों के लिए स्टाइलिश कलेक्शन की नई रेंज लांच की है. महिलाओं के लिए मिंक लिंक रीवर ऑफ डायमंड्स मॉडल और पुरुषों के लिए लियोनार्डो डि कैपरियो एक्कारेस 500 एम कैलरबर 5 मॉडल का लिमिटेड एडिशन लांच किया गया है. मिंक लिंक रीवर ऑफ डायमंड्स में 2.186 कैरेट के 5 सफायर और 241 हीरे लगे हैं. इसके 24-एमएम ब्लू-ब्लैक डायल में 11 चमकदार हीरे जड़े हैं. डायल के साथ लगी स्टेनलेस स्टील पट्टी में बनी पॉलिश्ड तिरछी फलिका इसकी ख़ूबसूरती में चार चांद लगाती है. इसमें लगे 48 डायमंड और सभी कोनों पर लगे चार सफायर इस घड़ी को और भी शालीन बनाते हैं. 8,04,000 रुपये की क़ीमत वाली इस घड़ी में टॉप वेसेलटॉन वीवीएस हीरे लगे हैं, जो 100 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट हैं और सफायर क्रिस्टल स्क्रैच रेसिस्टेंट हैं. क़ीमती पत्थरों से जड़ी इस घड़ी को पहन कर किसी भी आम लड़की को राजकुमारियों सा अहसास होगा. टैग हॉयर की तरफ से पुरुषों के लिए लांच की गई इलेक्ट्रिक ब्लू रंग के डायल वाली लियोनार्डो डि कैपरियो एक्कारेस 500 एम कैलीबर 5 मॉडल हाईटेक और हाई परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स घड़ी है. मेरीडियन लाइन एफेक्ट के साथ पॉलिश्ड सुइयों के छोर पर लगे चमकीले मार्कर और संख्या 9 के पास तारीख़ दिखाती हुई मैग्नीफाइंग ग्लास चढ़ी डेट विंडो है.

इसके 43 एमएम केस पर चमचमाता ब्लू इपोक्सी है. स्टेनलेस स्टील अंकों वाले डायल के साथ रबर की ब्लू स्टैप या थ्री रो वाली स्टील ब्रेसलेट है, जिसमें डाइव एक्सटेंशन और सेफ्टी पुश बटन लगे हैं. डायल पर कंपनी के लोगो के साथ 1,28,000 रुपये में आने वाली यह स्टैंडर्ड घड़ी स्कैच रेसिस्टेंट और 500 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

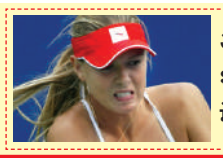

ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम मुक़ाबला है . शीर्ष के सभी खिलाड़ी एक बेहतर आग़ाज़ के इरादे से मुक़ाबले में उतरेंगे, लेकिन चुनौतियां उनके सामने आसान नहीं होंगीं.

टीम इंडिया क्यों हारती है?

फोटो– प्रभात पाण्डेय

मशहूर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इयान चैपल ने हाल ही में भारतीय टीम पर एक टिप्पणी की. चैपल की यह आलोचना भारतीय गेंदबाज़ों को लेकर थी. उनका मानना है कि भारतीय टीम में एक भी बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ नहीं हैं. और, इसका ख़ामियाज़ा टीम को चुकाना पड़ सकता है. चैपल का सीधा निशाना भारतीय टीम थी, जो आजकल टेस्ट में पहले पायदान पर है. मुमकिन है, टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के वर्चस्व को तोड़ने की वजह से चैपल टीम इंडिया को निशाना बना रहे हैं. उन्हें यह हजम न हो रहा हो कि आख़िर बल्लेबाज़ी के बूते कोई टीम कैसे पहले पायदान पर क़ाबिज़ हो सकती है. आज भारतीय टीम सफलता की बुलंदियों पर है. टेस्ट में नंबर एक और एकदिवसीय में दूसरे नंबर पर है. इससे हमें टीम इंडिया की ख़ामी नज़र न आती हो. हम भले ही चैपल की बातों को अपनी कमज़ोरी के तौर पर न देखें, लेकिन उनकी बातों में कहीं न कहीं कड़वी सच्चाई की झलक नज़र आती है.

पिछले दिनों बांग्लादेश के साथ त्रिकोणीय शृंखला इसकी बेहतरीन मिसाल है. फ़ाइनल में हम उस श्रीलंकाई टीम से हार गए, जिसे कुछ दिन पहले ही अपनी ज़मीन पर धूल चटाई थी. इसमें सबसे बड़ा योगदान गेंदबाज़ों का ही था. घरेलू मैदानों पर अव्वल प्रदर्शन करने वाले सभी गेंदबाज़ों ने हमें निराश ही नहीं किया, बल्कि टीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया. चाहे वह ज़हीर ख़ान हों या कानपुर टेस्ट में श्रीलंका के ख़िलाफ़ उम्दा प्रदर्शन करने वाले श्रीसंथ. लगभग हर मैच में सभी ने दिल खोलकर रन लुटाए. फिरकी गेंदबाज़ हरभजन भी कहां पीछे थे. लगता है, वह भी इरफ़ान पठान की राह पर चल पड़े हैं. गेंदबाज़ी के बजाय बल्लेबाज़ी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं. यदि ऐसा रहा तो कहीं उन्हें भी पठान की तरह टीम से बाहर न बैठना पड़ जाए.

फोटो– पीटीआई

यह महज़ चंद मैचों की ही बात नहीं है. हां, यह ज़रूर है कि भारतीय गेंदबाज़ चंद मैचों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसी बूते कई मैच खेल जाते हैं. अपने करियर के आग़ाज़ में तेज़ गेंदबाज़ चमत्कारी प्रदर्शन करते हैं. लेकिन जैसे-जैसे गेंदबाज़ी में उनका अनुभव बढ़ता जाता है, उनके प्रदर्शन में गिरावट आने लगती है. कुछ इस तरह की, मानो वे राष्ट्रीय के टीम नहीं, बल्कि क्लब स्तर के गेंदबाज़ हों. अभी हाल में जितने भी गेंदबाज़ों ने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई, सभी का कमोबेश यही हाल रहा. अजीत आगरकर, मुनाफ़ पटेल, आर पी सिंह, ईशांत शर्मा एवं इरफ़ान पठान आदि कभी भारतीय टीम की धुरी हुआ करते थे. आज टीम में इनकी जगह भी नहीं है.

पिछले दिनों बांग्लादेश के साथ त्रिकोणीय शृंखला के फ़ाइनल में हम उस श्रीलंकाई टीम से हार गए, जिसे कुछ दिन पहले ही अपनी ज़मीन पर धूल चटाई थी. पहले टेस्ट के दौरान बांग्लादेश के साथ बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन भी काफ़ी कुछ कह जाता है.

अभी हमारी टीम टेस्ट मैचों में फिसड्डी बांग्लादेश से मुक़ाबला कर रही है. बांग्लादेश के सामने पहले टेस्ट में हमारे बल्लेबाज़ों ने किस तरह का प्रदर्शन किया और आगे उनका यह प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह हम सभी जानते हैं. ज़्यादा मैच हमने उसके ख़िलाफ़ नहीं खेले हैं, फिर भी उसकी वजह से हमें 2007 के विश्वकप में पहले दौर से ही बाहर होना पड़ा था. एकदिवसीय शृंखला के दौरान बांग्लादेशी टीम भले ही हार गई, लेकिन उसके बल्लेबाज़ों ने भी भारतीय गेंदबाज़ों की ख़ूब धुनाई की और श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों ने क्या हाल किया, वह भी हमारे सामने है. जब हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चैपल के बयान का करारा जवाब देते हैं तो हमें सुकून मिलता है. लेकिन एक पल ठहर कर हमें यह सोचना चाहिए कि यदि कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो उसकी वाजिब वजह क्या है? चैपल के बयानों को ग़लत ठहराने के बजाय टीम इंडिया यदि क्षेत्ररक्षण और गेंदबाज़ी पर ध्यान दे तो वाक़ई हम न टेस्ट और न ही एकदिवसीय, बल्कि क्रिकेट के हर स्वरूप में सिरमौर बने रहेंगे.

ऑस्ट्रेलियन ओपन का जादू

ऑस्ट्रेलियन ओपन की जंग शुरू हो चुकी है. साल 2010 का यह पहला ग्रैंड स्लैम मुक़ाबला है. रोज़र फेडरर से लेकर सेरेना विलियम्स तक सभी शीर्ष खिलाड़ियों की नज़र ख़िताब पर है. लेकिन ख़िताब उसके ही हाथ लगेगा, जो सबसे बेहतर होगा. यदि कोई बड़ा उलटफेर न हुआ तो पिछली बार के चैंपियन रफेल नडाल को फेडरर से कड़ी चुनौती मिलने वाली है. यानी इस बार नडाल को ख़िताब अपने नाम करने के लिए काफ़ी मेहनत-मशक्कत करनी पड़ जाएगी. वहीं महिलाओं के वर्ग में पिछली बार एकल ख़िताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स के सामने भी चुनौतियां आसान नहीं हैं. टेनिस कोर्ट में पूर्व चैंपियन जस्टिन हेना हार्डिन एवं किम क्लाइसटर्स की वापसी से सेरेना के रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं. साथ में मारिया शारापोवा, दिनारा साफ़िन एवं एना इवानोविक भी सेरेना और ख़िताब के बीच में किसी दीवार से कम नहीं हैं. रोजर फेडरर पिछली बार नडाल के हाथों हार का बदला लेने के लिए तैयार हैं तो चोट से उबरने के बाद रूसी बाला मारिया शारापोवा भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. 18 जनवरी से शुरू हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह मुक़ाबला 31 जनवरी तक चलने वाला है. इस दरम्यान कई उलटफेर भी हुए. कई बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त खानी पड़ी. लेकिन अभी भी सबकी नज़रें उस खिलाड़ी पर टिकी हैं, जो पुरुष, महिला, युगल और मिश्रित युगल मुक़ाबले में ख़िताब अपने नाम करेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 25 जनवरी–31 जनवरी 2010

ऐश्वर्या ने निर्देशक रामगोपाल वर्मा के साथ *सरकार राज* में काम किया था और नीतू उनके साथ फ़िल्म *रण* में नज़र आएंगी. इसलिए वह ख़ुद को ऐश्वर्या समझ बैठी हैं.

कामयाबी की राह

हर अभिनेत्री चाहती है कि उसका क़द दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहे. क़द बढ़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगी. हम बात कर रहे हैं मिनिषा लांबा की. मिनिषा को अभी तक बॉलीवुड में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिसे देखकर दर्शक कहें कि वेल डन मिनिषा. लेकिन, यह चमत्कार जल्द होने वाला है. उन्हें श्याम बेनेगल निर्देशित फ़िल्म *वेल डन अब्बा* से बहुत आशाएं हैं. कुछ दिनों पहले दुबई फ़िल्म फेस्टिवल में *वेल डन अब्बा* की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. वहां लोगों ने मिनिषा के अभिनय की तारीफ़ में जमकर कसीदे पढ़े. मिनिषा को यह बहुत अच्छा लगा. मिनिषा कहती हैं कि यह अवसर उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव था. श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मेरा सपना पूरा हो गया. मिनिषा को उम्मीद है कि इस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद उन्हें बॉलीवुड और बाहर वाले कहेंगे कि वेल डन मिनिषा. देखते हैं, क्या वाकई उनकी यह फ़िल्म वेल डन साबित होगी.

ऑफर का इंतज़ार

ही रोइनों के आने-जाने का तो पता ही नहीं चल पाता. अब आप कोएना को ही देख लीजिए. वह कब आईं और चली गईं, पता ही नहीं चला. कुछ समय पहले तक बॉलीवुड की मशहूर आइटम नंबर रह चुकीं कोएना आजकल इंडस्ट्री से ग़ायब हैं. पहले तो कोएना ने अपने लटके-झटकों से इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब उनका नाम सुनने में ही नहीं आता. पहले उन्हें काम से फ़ुर्सत नहीं मिलती थी. कुछ साल पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि कोयना आइटम डांस पर ध्यान न देकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं करना चाहती हैं जिनसे लोग उन्हें अच्छा डांसर मानने के साथ-साथ एक अच्छी अदाकारा भी मानें. इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी. प्रीतिश नंदी कम्यूनिकेशन की फ़िल्म *एक खिलाड़ी एक हसीना* में उनके साइकोपैथ डॉक्टर के किरदार और *अपना सपना मनी मनी* में रितेश के साथ उनकी कॉमेडी को ख़ूब सराहा गया था. इतना ही नहीं, उनके एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में भी काम करने की चर्चा ज़ोरों पर थी, जिसमें वह सुपरवूमैन के किरदार में थीं, लेकिन फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई है. अब फ़िलहाल उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है. वैसे वह फ़िल्मों में काम करें या न करें, लेकिन साल के अंत में न्यू इयर पर डांस करने के ऑफर तो मिल ही जाते थे. लेकिन इस साल तो ऐसे ऑफर भी नहीं मिले. बावजूद इसके कोयना को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल निश्चित ही उन्हें अच्छे ऑफर्स ज़रूर मिलेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ़िल्म प्रीव्यू

स्ट्राइकर

फ़िल्म *रंग दे बसंती* से चर्चा में आए अभिनेता सिद्धार्थ की काफ़ी दिनों बाद फ़िल्म स्ट्राइकर से बॉलीवुड में वापसी हो रही है. वह साउथ में बराबर सक्रिय रहे, लेकिन हिंदी फ़िल्मों के मामले में थोड़ा चूजी हो गए. स्ट्राइकर एक सच्ची घटना पर आधारित है. 80 के दशक में मुंबई में किस तरह अपराध अपने पांव पसार रहा था, यही इस फ़िल्म में दिखाया गया है. सिद्धार्थ सूर्या के किरदार में हैं, जो कैरम के खेल में उस्ताद है. मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कैरम के ज़रिए वह स्कूल लेवल पर चैंपियन बन जाता है, लेकिन एक दिन काम की तलाश में वह दुबई चला जाता है. काम तो उसे वहां मिल जाता है, पर एक कंपनी के हाथों ठगकर वह अपनी सारी कमाई गंवा देता है. निराश सूर्या की मुलाक़ात जलील से होती है, जो अपराध जगत का बादशाह है.

मजबूरी के चलते वह जलील के साथ काम करने लगता है. कैरम का स्ट्राइकर अपराध जगत में स्ट्राइकर की भूमिका में आ जाता है. किस तरह वह अपराध के दलदल से बाहर निकलता है, यही फ़िल्म का क्लाइमेक्स है. सिद्धार्थ के अलावा आदित्य पंचोली, पदमाप्रिया, सीमा विश्वास और अनुपम भी इसमें नज़र आएंगे. निर्देशक और निर्माता हैं चंदन अरोड़ा. यह 5 फरवरी को प्रदर्शित होगी.

ऐश्वर्या की बराबरी

नीतू चंद्रा इन दिनों शायद ख़ुद को ऐश्वर्या राय समझने लगी हैं. कहां इंडस्ट्री में कल की आईं देशी बोल्ड बाला नीतू और कहां ख़ूबसूरती की मिसाल ऐश्वर्या राय! लेकिन नीतू ख़ुद को ऐश्वर्या समझने की भूल कर बैठी हैं. इस बात की वजह यह है कि ऐश्वर्या राय ने इंडस्ट्री के जिन नामी-गिरामी निर्देशकों के साथ काम किया है, उन्हीं के साथ नीतू भी काम कर रही हैं. हालांकि यह एक संयोग की बात है पर नीतू को कुछ और लग रहा है. दरअसल ऐश्वर्या ने निर्देशक रामगोपाल वर्मा के साथ फ़िल्म *सरकार राज* में काम किया था और नीतू उनके साथ फ़िल्म *रण* में नज़र आ रही हैं. इसेके अलावा ऐश ने जग मूंदड़ा के साथ प्रोवोक्ड में काम किया और नीतू उनकी फ़िल्म *द अपार्टमेंट* में आ रही हैं. नीतू ख़ुद को ऐश्वर्या राय के बराबर इसलिए भी बताने लगी हैं, क्योंकि अब वह मुंबई के लोखंडवाला में उसी घर में रहने के लिए चली गई हैं, जहां ऐश ने शुरुआती दिनों में अपना डेरा जमाया था. लेकिन नीतू जी समान निर्देशकों के साथ काम करना ही काफ़ी नहीं है. भूमिकाएं भी ऐश की तरह चुनौतीपूर्ण मिलें तब जाकर बात बनेगी. *रण* फ़िल्म के साइड रोल से कुछ भी नहीं होगा. यूं तो इंडस्ट्री में हर हीरोइन ऐश जैसी बुलंदी और क़िस्मत पाने की ख्वाहिश पाल सकती है, लेकिन सच तो यह है कि सबको सब कुछ नहीं मिल पाता. यह क़ुदरत का नियम है.

राइट और रांग

मुक्ता आर्ट्स इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फ़िल्म काफ़ी वक़्त से ख़ुद के रिलीज़ होने की राह देख रही थी. अब इसे 5 फरवरी को रिलीज किया जाएगा. फ़िल्म सुभाष घई के प्रोडक्शन में बन रही है, लेकिन उनका मार्क इस फ़िल्म में नहीं है. फ़िल्म में सनी देओल, इरफान ख़ान, ईशा कोप्पिकर और कोंकणा सेन नज़र आएंगे. इस मर्डर मिस्ट्री में विनय और अजय पुलिस ऑफीसर हैं और दोस्त भी. कहानी में मोड़ तब आता है, जब अजय की पत्नी का क़त्ल हो जाता है और इल्ज़ाम अजय पर आ जाता है. इस केस में विनय के अलावा अजय की दोस्त कोंकणा भी काम कर रही है. असली ख़ूनी कौन है? इसी तहक़ीक़ात पर फ़िल्म आगे बढ़ती है. अजय और विनय का किरदार सनी और इरफान ने निभाया है. निर्देशक नीरज पाठक हैं. संगीत सांवरिया फेम मोंटी शर्मा ने दिया है, जबकि गीतों को कलमबद्ध किया है समीर ने.

मूसा

पिछले सप्ताह लगातार चार फ़िल्में रिलीज होने के कारण इस सप्ताह बड़े बैनर की कोई भी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है. इस दौरान कम बजट और बी-सी ग्रेड की फ़िल्मों को रिलीज होने का मौक़ा मिल जाता है. ऐसी ही फिल्मों में *मिशन 11 जुलाई* और *मूसा* का नाम लिया जा सकता है, दोनो ही फ़िल्में 5 फरवरी को प्रदर्शित हो रही है. मूसा एक एक्शन थ्रिलर है. फ़िल्म में जैकी श्राफ, समीर आफताब, यशपाल शर्मा, मोनिका और सुशांत सिंह हैं. अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के इर्द-गिर्द घूमती इस फ़िल्म की कहानी मोस्ट वांटेड आतंकवादी मूसा की है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है. फ़िल्म बताती है कि आतंकवादियों और अपराधियों का कोई धर्म-ईमान नहीं होता. वे सिर्फ़ पैसे के लिए जीते और मरते हैं. कटारिया फ़िल्म्स के बैनर तले बनी *मूसा* के निर्माता महेंद्र भाई कटारिया हैं. निर्देशन हिमांशु भट्ट ने किया है. कहानी और पटकथा भी हिमांशु ने लिखी है. संतोष शर्मा, इलियास और जगदीप ने संगीत तैयार किया है. फ़िल्म छोटे शहरों के दर्शकों और सिंगल स्क्रीन्स में ज़्यादा पसंद की जाएगी.